तृतीय माला, खण्ड १९—अंक ९

शुक्रवार, २३ अगस्त, १९६३
१ भाद्र, १८८५ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(पांचवां सत्र)

3rd Lok Sabha

(खण्ड १९ में अंक १ से अंक १० तक है)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में)

चार शिलिंग (विदेश में)

विषय सूची

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित *प्रश्न संख्या २४० से २४३ और २४५ से २५२ ११११–३७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २४४ और २५३ से २६९ ११३७–४७

अतारांकित प्रश्न संख्या ७४३ से ८०० और ८०२ से ८२२ ११४७–८३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . ११८३–८५

उत्तर प्रदेश गुजरात और अन्य राज्यों को ढलवें लोहे का अपर्याप्त संभरण

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ११८५–८६

विधेयक पर राय ११८६

सभा का कार्य ११८६–८७

व्यक्तिगत चोट (प्रतिकर बीमा) विधेयक—पुरस्थापित . ११८७–८८

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), १९६३–६४ . . ११८८–९८

श्री शाहनवाज खां ११८८–८९

श्री नम्बियार ११८९

श्री यशपाल सिंह ११८९–९१

श्री पें० वेंकटासुब्बया ११९१

श्री मुथिया ११९१

श्री ओंकार लाल बेरवा ११९१–९२

डा० गायतोंडे ११९२

श्री शिवमूर्ति स्वामी ११९२–९४

श्री जो० ना० हजारिका ११९४

श्रीमती शशांक मंजरी ११९४–९५

श्री सोनावने ११९५

श्री प्रिय गुप्त ११९५–९६

श्री पाराशर ११९६

श्री भू० ना० मंडल ११९६

श्री कृ० ल० मोरे ११९६

श्री कछवाय ११९६–९८

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

[शेष मुख पृष्ट तीन पर देखिये

लोक-सभा

शुक्रवार, २३ अगस्त, १९६३
१ भाद्र, १८८५ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

केले

†*२४०. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री यशपाल सिंह :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री इम्बीचिबावा :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री रामचन्द्र मलिक :

क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केलों के निर्यात के लिए नई मंडियों की खोज करने के लिए कोई समिति नियुक्त की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी सिफारिशें क्या हैं और रूस को बहुत बड़ी मात्रा में केलों का निर्यात करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ; और

(ग) देश में केलों की पैदावार बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

†मूल अंग्रेजी में

1005 (Ai) LS—1.

†**अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) केलों के निर्यात बढ़ाने के कार्य की देखभाल करने के लिये, श्री वी० शंकर, सचिव, खाद्य विभाग, खाद्य तथा कृषि मंत्रालय, की अध्यक्षता में केलों के निर्यातकों, उत्पादकों आदि की एक 'केला विकास समिति' स्थापित की गई है ।

(ख) बाहरी देशों को केले के निर्यात को बढ़ाने के लिये अनेक कदम उठाये जा रहे हैं। निर्यात के लिये केलों की उपलब्धि का सवर्क्षण कर लिया गया है । केलों के विपणन की सम्भावनाओं की खोज करने के लिये केलों के निर्यातकों व उत्पादकों और सम्बन्धित अधिकारियों का एक प्रतिनिधि मंडल अभी पश्चिम एशियाई तथा यूरोपियन देशों को गया है । इस वर्ष केले के रूस को भेजे जाने की सम्भावना है ।

(ग) देश के केलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् योजनायें चला रही है ।

†**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : इस बात को बिचारते हुए कि इस देश में बहुत सी किस्मोंके केले उगाये जाते हैं, क्या जान सकता हूं कि रूसी रोम किस विशेष किस्म अथवा प्रकार के केले में रुचि रखते हैं और क्या रूसी मांग को पूरा करने के लिये उस किस्म का पर्याप्त उत्पादन है ।

†**श्री मनुभाई शाह** : जी, हां । जिन किस्मों में वे रुचि रखते हैं उन में से मुख्य किस्में वे हैं जो महाराष्ट्र राज्य के जलगांव से आती हैं; केरल तथा मैसूर से आने वाली दो अन्य किस्में भी ऐसी हैं। यह हमारे पास बहुत हैं, और वर्तमान विक्रय से हम उन से बहुत सारा धन प्राप्त कर सकते हैं ।

†**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या मैं यह समझ लूं कि केलों के निर्यात में मुख्य कठिनाई उचित शीत भाण्डागार सुविधाओं वाले जहाजों का उपलब्ध न हो पाना है और यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूं कि इस कठिनाई को दूर करने के लिये क्या पग उठाये जा रहे हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : हम रूस के लिये केला स्टीमरों को भाड़े पर ले रहे हैं और हमने एक भाड़ पर ले भी लिया है ; गत छः महीनों में केलों का निर्यात लगभग दुगना हो गया है ; पहले छः महीनों में हमने २५ लाख रुपये के मूल्य के केले निर्यात किये हैं जब कि गत पूरे वर्ष में कुल २० लाख रुपये के केले निर्यात किये गये थे ।

श्री यशपाल सिंह : क्या ज्यादातर केला रास्ते में इसलिए ख़राब हो जाता है कि हमारे शिप्स में उनको सुरक्षित रखने का कोई इंतजाम नहीं है और बंदरगाहों पर भी इसके लिए कोई इंतजाम नहीं है ताकि उन को ठीक रखा जा सके ?

श्री मनुभाई शाह : माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं और यही कारण है कि इस के लिए नये क़िस्म के शिप्स चार्टर किये गये हैं । इस के अलावा बंदरगाहों पर भी हम इस के लिए मिकनिकल इलक्टर्स फ़िट करवा रहे हैं । अभी तक इस की व्यवस्था नहीं है लेकिन अब हम इंतज़ाम कर रहे हैं ।

†**श्री अ० क० गोपालन** : सोवियत संघ को किस किस्म के तथा कितने मूल्य के केले निर्यात किये जाने हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : लगभग १७ लाख रुपये के मूल्य के ४ हजार टन केले ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री वारियर** : उत्पादकों को कुछ प्रोत्साहन देने के लिये और यह देखने के लिये कि इन निर्यातों के लिये निर्धारित किये गये मूल्य स्वयं उत्पादकों के ही हाथों में ही जायें क्या कोई योजना बनाई गई है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : व्यवस्था इस प्रकार है । पहली बात यह है कि हमारे पास उत्पादकों की सहकारी समितियां हैं, उन्हें यह कार्य सौंप दिया जायेगा जिससे कि बिचौलिया नहीं रहेगा । दूसरे, हम दक्षिण भारत केला विकास निगम के नाम से एक समवाय बना रहे हैं जिससे कि मैसूर, मद्रास, आंध्र प्रदेश और केरल राज्य भाग लेंगे, यह सरकारी क्षेत्र का एक निगम है और दूसरी कम्पनी पूर्वी भारत केला विकास निगम अथवा पूर्वी भारत बामान निगम के नाम से है जिस में उड़ीसा राज्य अधिकांश शेयरस खरीद रहा है ।

†**श्री वासुदेवन् नायर** : इस समय हम किन किन देशों को केलों का निर्यात कर रहे हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : पूरे पश्चिम एशिया, बहरीन,कुवेत, ओमान, पश्चिम पाकिस्तान, कीनिया तथा सऊदी अरब और पश्चिम यूरोप के देशों को ।

†**श्री मोहन स्वरूप** : वे देश कौन कौन से हैं जो कि यहां से केलों का आयात करने का इरादा कर रहे हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : विशेष रूप से सभी पश्चिम यूरोपीय देश और पूर्वी यूरोपियन देश और कीनिया के अतिरिक्त जो कि केलों का उत्पादन कर रहा है कुछ अफ्रीकी देश ।

श्री ओंकार लाल बेरवा : मैं जानना चाहता हूं कि जो केला रूस भेजा जाता है उसके बदले में बिदेशी मुद्रा आती है या सामान आता है ?

श्री मनुभाई शाह : विदेशी मुद्रा आती है ।

श्री रघुनाथ सिंह : सबसे ज्यादा केला इस वक्त कहां इम्पोर्ट होता है और क्या हिन्दुस्तानी शिपिंग कम्पनियों से इस बारे में कोई बात हुई है कि शिप्स में कोल्ड स्टोरेज का इंतज़ाम होना चाहिए ।

श्री मनुभाई शाह : अभी तक तो पोज़ीशन यह है कि हम मामूली शिप्स भी बनाने में मुश्किल अनुभव कर रहे हैं लेकिन अगर १२-१५ इस तरह के शिप्स की ज़रूरत पड़ जाये तो हम उस की कोशिश करेंगे । फिलहाल हम उनको चार्टर ही कर रहे हैं लेकिन बाद में उनको परचेज़ करेंगे जिससे कि हम फ्रेट बचा सकें ।

श्री त्यागी : रूस को जो केला भेजा जा रहा है वह केला कौन सी किस्म का है? रूस वालों को चुनिया केला ज्यादा पसन्द है, लाल छाल का पसन्द है या हरी छाल का केला ज्यादा पसन्द है ?

श्री मनुभाई शाह : रूस वालों को हरी छाल का चितरी वाला केला पसन्द है । लाल छाल का भी आगे चल कर पसन्द कर लेंगे ।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया** : क्या इस देश के केला उत्पादकों को ऋण, वैज्ञानिक सुविधायें तथा अन्य प्रकार की वित्तीय सहायता देने के हेतु एक योजना तैयार करने के लिये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को आदेश दिये गये हैं ।

---

†मूल अंग्रजी में

†**श्री मनुभाई शाह** : इन सभी बातों पर बिचार किया जायेगा, और इसी कारण केन्द्रीय समिति गठित की गई है तथा दो निगम स्थापित किये जा रहे हैं ।

†**श्री म० ला० द्विवेदी** : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार केले के पाउडर को एक्सपोर्ट करने के लिए जलगांव में एक प्लांट बनाने जा रही है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जी हां, इसके लिये दो प्लांट्स बन रहे हैं ।

भारत–फ्रांस व्यापार

†*२४१. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही के महीनों में भारत फ्रांस व्यापार को बढ़ाने की संभावनाओं की खोज-बीन की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

†**अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां ।

(ख) अप्रैल, १९६३ में व्यापार स्थिति का पुनर्विलोकन किया गया था जब कि भारत फ्रांस व्यापार करार के नवीनकरण के लिये बातचीत की जा रही थी जिस का परिणाम यह निकला कि पत्री वर्ष १९६३ के लिये कुछ समिति मदों के लिये अधिक उदार अभ्यंश प्राप्त कर लिये गये थे । फ्रांस सरकार के एक उच्च शक्ति प्राप्त व्यापार प्रतिनिधि मंडल के भी निकट भविष्य में भारत का दौरा करने की आशा है और प्रारम्भिक तैयारियां काफ़ी हो चुकी हैं ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : फ्रांस के साथ व्यापार की वर्तमान स्थिति क्या हैं और उसमें किस प्रकार से सुधार हुआ है ।

†**श्री मनुभाई शाह** : स्थिति में इस प्रकार सुधार हुआ है : गतवर्ष जो हमारा प्रतिकूल सन्तुलन था, अर्थात ८ करोड़ रुपये का, वह इस वर्ष तक होकर ४ करोड़ रुपये का रह गया है । नवीन परिणामों से कदाचित हम इसका सन्तुलन कर सकेंगे ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या कुछ व्यापार प्रतिनिधि मंडल अथवा कुछ व्यक्ति भारत आये थे और यदि हां, तो उन्होंने भारत सरकार के साथ किस प्रकार की चर्चा की थी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : वे अभी तक तो नहीं आये हैं । परन्तु लगभग दो महीने पूर्व जबकि मैं पेरिस में था उस समय की फ्रांस सरकार के साथ हुई हमारी चर्चाओं के परिणाम स्वरूप, हम सरकारी प्रतिनिधि मण्डल के अतिरिक्त अन्य चार अथवा पांच उच्च शक्ति-प्राप्त व्यापार प्रतिनिधि मण्डलों को आमन्त्रित कर रहे हैं । और उसी प्रकार, उन कुछ चुनी हुई वस्तुओं के सम्बन्ध में जिनमें कि फ्रांस की रुचि है हमारे देश से भी कुछ प्रतिनिधि मण्डल फ्रांस जायेंगे ।

डा० गोविन्द दास : जहां तक यहां से फ्रांस को निर्यात होने वाली चीजों का सम्बन्ध है, अभी तक वहां पर कौन सी चीजें निर्यात होती हैं और उन चीजों की वृद्धि के अतिरिक्त क्या इस बात का भी प्रयत्न किया जा रहा है कि वहां पर अन्य और चीजें भी निर्यात की जा सकें ?

श्री मनुभाई शाह : हमारा वहां तम्बाकू जाता है, तेल जाता है, वेजीटेबुल आयल्स जाते हैं, कुछ टक्सटाइल्स और गारमेंट्स जाते हैं और हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह जाते हैं, मशरूम्स ज्यादातर जाते

†मूल अंग्रेजी में

हैं। उनसे हम मशीनरीज और फर्टीलाइजर्स ले रहे हैं। स्पशल स्टील ले रह हैं और जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी उनसे हम चीजें लेंगे ।

इसको ब्रौडबेस करके डाइवरसीफाई करने की कोशिश की जायगी।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या फ्रांस को निर्यात किये जाते वाले जूट की वस्तुओं के अभ्यंश को बढ़ाने के लिये फ्रांस सरकार को सहमत कर सकने में माननीय सदस्य का दौरा सफल रहा था ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह एक नाजुक ऐसा मद है कि जिसमें कि फ्रांस न्यूनाधिक आत्मनिर्भर है और नये प्लास्टिक थैलों और पैकिंग सामग्री के कारण अब उस देश को अपनी जूट वस्तुओं की आवश्यकताओं को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है । परन्तु हमें यह आशा है कि हम सुधार कर पायेंगे; मैं इस अवसर पर फ्रांस जूट उद्योग तथा फ्रांस सरकार से यह अपील करता हूं कि क्योंकि भारत प्रारम्भ से ही जूट वस्तुओं का निर्माणकर्ता रहा है, यदि वे जूट की बनी कुछ वस्तुओं को और अधिक मात्रा में भारत से फ्रांस भेजे जाने की अनुमति दें तो इससे दोनों देशों का ही हित होगा ।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ** : क्या निर्यात के लिये वस्तुओं की सूची बनाते समय, परम्परागत वस्तुओं के अतिरिक्त गैर-परम्परा गत वस्तुयें भी उसमें सम्मिलित की जायेंगी और दूसरे, जहां तक आयातों का सम्बन्ध है, तो यंत्रों के अतिरिक्त, उसमें अन्य कौन कौन सी वस्तुएं होंगी जिनमें कि हमारी रुचि होगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जैसा कि सदन को ज्ञात है, इन औद्योगिकृत देशों से हम मुख्यतथा औद्योगिक मशीनें, मूल कच्ची सामग्री अर्थात् अणु शक्ति स्टशनों के कुछ भाग, डीजल इंजन, हैवीकैमीकल्स, प्रैट्रो-कैमिकल्स तथा कुछ अन्य कपड़ा उद्योग की मशीनों का आयात कर रहे हैं । निर्यात की दिशा में, केवल फ्रांस के ही नहीं अपितु अन्य देशों के सम्बन्ध में भी, क्योंकि भारत का भविष्य अधिक निर्यात पर ही निर्भर करता है--हमारा वर्तमान निर्यात परम्परागत वस्तुओं पर आधारित है--अतः हम यह देखने का प्रयत्न करते हैं कि उसका विस्तार हो ; और क्योंकि भारत का औद्योगीकरण हो रहा है अतः गैर-परम्परागत निर्मित वस्तुओं पर भी भारत का भविष्य निर्भर करता है ; उनको निर्यात करने का भी हम निरन्तर प्रयत्न कर रहे हैं ।

प्रोत्साहन बोनस योजना

†*२४२. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इलेक्ट्रिकल्स परियोजना, भोपाल में एक प्रोत्साहन बोनस योजना आरम्भ की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या फैक्टरी के मान्यताप्राप्त कार्मिक संघ की शुभकामनायें इस योजना के साथ हैं ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) और (ख). श्रीमन्, अभी तक नहीं । समझौते की कार्यवाही चल रही है और इस विषय पर संघ के साथ अभी तक बात चीत हो रही है ।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि इन्सेंटिव बोनस स्कीम से कितना प्राडक्शन हैवी इलक्ट्रिकल्ज में बढ़ा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री प्र० चं० सेठी : जैसा कि मैंने अभी उत्तर में बताया है, उस स्कीम को अभी लागू नहीं किया गया है । मामला अभी कान्सिलियेशन के अधीन है और रकगनाइज्ड यूनियन से अभी बातचीत चल रही है ।

श्री यशपाल सिंह : क्या सरकार पब्लिक सैक्टर के दूसरे कारखानों में भी इस स्कीम को लागू करने पर विचार कर रही है ?

श्री प्र० चं० सेठी : यह सवाल भोपाल के मुताल्लिक है ।

श्री कछवाय : क्या यह सही है कि भोपाल के हैवी इलक्ट्रिकल्ज में कुछ बरसों से चोरियां होनी प्रारम्भ हो गई हैं ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न से उसका क्या ताल्लुक है ?

श्री प्रिय गुप्त : मैं यह जानना चाहता हूं कि इन्सेन्टिव बोनस स्कीम को लागू करते वक्त क्या मिनिस्ट्री ने यह मद्दे-नजर रखा है कि प्राडक्शन के नार्म्ज को सही ढंग से यूनिफार्म रखने के लिए आर्टिसन स्टाफ को इंस्ट्रुमेंट्स और औजार सही ढंग से दिय जायेंगे । इस के अलावा जो इन्सेंटिव बोनस दिया जाता है, वह किस प्रकार कैल्कुलेट किया जाता है और क्या इन्सेंटिव बोनस स्कीम लागू होने से रैशनलाइजशन या मजदूरों में कुछ कमी होगी ?

श्री प्र० चं० सेठी : जी नहीं, इन्सेन्टिव बोनस स्कीम लागू होने से कोई रैशनलाइजेशन या मजदूरों में कमी नहीं होगी । जहां तक बनान के सम्बन्ध में दिये जाने वाले औजारों या सामान का सवाल है, वह उन को मुहैय्या किया जाता है । इन्सेन्टिव बोनस लागू होने से मजदूरों को आर्थिक लाभ होगा ।

श्री प्रिय गुप्त : रेट्स का कैल्कुलेशन कैसे किया जाता है ?

श्री प्र० चं० सेठी : इस में दो प्रकार का लाभ मजदूरों को होगा । यदि वे पचास फीसदी एफिशेन्सी तक पहुंच जाये, तो उन को क्राफ्ट बोनस मिलेगा । फर्ज कीजिये कि एक मजदूर की दूसरे साल में जो तनख्वाह मिल रही है, उसमें और छठे साल की तन्ख्वाह में जो फर्क है, उस फर्क के अनुसार उन को फायदा हो जायगा । दूसरे, यदि वे पचास फीसदी के ऊपर एफिशियेंसी दिखायेंगे, तो क्रमशः पांच फीसदी के हिसाब से उन को फायदा होता जायगा ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या इस विशेष प्रोत्साहन बोनस योजना के लागू किये जाने के पश्चात उत्पादन में वद्धि हो गई है और क्या यह सम्बन्धित संघ से परामर्श लेकर लागू की गई है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** वह अभी तक लागू नहीं की गई है ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या इस योजना के लागू किये जान से पूर्व इस संयंत्र में कोई कार्य अध्ययन अथवा समय और गति अध्ययन किसी वैज्ञानिक ढंग से किया गया है और यदि हां, तो क्या इस कार्य के लियेज्ञ कोई विशेषज्ञ अथवा परामर्श दाता लगाय गये हैं ? मैं यह जानन चाहूंगा कि यह किस प्रकार किया जा रहा है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) :** जी हां । विशषज्ञों से परामर्श लिया गया है और उसी आधार पर योजना तैयार की गई है । अब इस सम्बन्ध में प्रतिनिध संघ के साथ समझौता बार्ता चल रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नरम लकड़ी

+

†*२४ श्री वारियर :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री बासुदेवन नायर :
श्री म० ना० स्वामी :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दियासलाई के निर्माण के लिये अपेक्षित नरम लकड़ी की कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कमी को पूरा करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

†उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख). विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) दियासलाई उद्योग के लिये अपेक्षित लकड़ी को मिलाकर सभी प्रकार की औद्योगिक लकड़ी की आम कमी है ।

(ख) इस कमी को दूर करने के लिये सरकार ने जो कदम उठाये हैं वह निम्नलिखित हैं :—

(१) दियासलाई के निर्माण के लिये उपयुक्त मुख्य स्वदेशी लकड़ी से मूल[1] दियासलाई उद्योग के लिये रक्षित कर ली गई है ।

(२) द्वितीय योजना के एक अंश के रूप में दियासलाई की लकड़ी के बागानों को बढ़ाने का एक विशष कार्यक्रम राज्य सरकारों द्वारा नियमित आधार पर चलाया गया था । दियासलाई की लकड़ी वाले बागानों को प्रोत्साहन देने के लिये भारत सरकार ने ५० % तक अर्थ सहायता दी थी । प्रथम और द्वितीय योजना काल के दौरान लगभग ८ हजार एकड़ क्षेत्र में नये बागान लगाये गये थे ।

(३) तृतीय योजना काल के दौरान ५०,००० एकड़ क्षेत्र में दियासलाई की लकड़ी के बागानों को लगाने का विचार है । केन्द्रीय सरकार व्यय का आधा भाग राज्य सरकारों को देती रहेगी ।

(४) वन अनुसंधान संस्था, देहरादून में किए गये अनुसन्धान के आधार पर अन्य कई प्रकार की लकड़ी को दियासलाई के निर्माण के लिये उपयुक्त पाया गया है । इन किस्मों को मंजूर कर लिया गया है तथा इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसीफिकेशन्स में सम्मिलित कर लिया गया है ।

(५) अभी तक के अछूते दुर्गम क्षेत्रों को खोज निकालने की सम्भावनाओं की छानबीन की जा रही है ।

†श्री वारियर : प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना कालों के दौरान हमारे द्वारा किये गये व्यय से क्या वास्तव में नरम लकड़ी के सम्भरण में वास्तविक वृद्धि हुई थी ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[1]Salmalia Malabar'ca.

†**श्री कानूनगो** : यह बताना अभी सम्भव नहीं होगा क्योंकि इस विशेष प्रकार के वृक्षों के परिपक्व होने में कम से कम ३५ वर्ष का समय लगता है।

†**श्री वारियर** : विवरण में यह संकेत किया गया है कि प्रथम तथा द्वितीय योजना कालों में नरम लकड़ी के उत्पादन में वद्धि के लिये हमने कुछ धन व्यय किया था। क्या उस व्यय के परिणामों का कोई मूल्यांकन कर लिया गया ?

†**श्री कानूनगो** : मैंने विवरण में उल्लेख किया है कि कुछ एकड़ क्षेत्र में बागान लगाये गये हैं। परन्तु उन बागानों के परिपक्व होने में कम से कम ३५ वर्ष लगेंगे।

†**श्री वारियर** : भारत के सभी दियासलाई कारखानों को चलाने के लिये कुल कितनी मात्रा में नरम लकड़ी की आवश्यकता है ? क्या उसका सम्भरण कम है ?

†**श्री कानूनगो** : मैं कुल मात्रा इस समय नहीं बता सकता, परन्तु इसका सम्भरण बहुत कम है और सम्भरण स्थिति और भी खराब होने जा रही है।

†**श्री वासुदेवन् नायर** : विवरण में यह बताया गया है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में दियासलाई की लकड़ी के जंगलों को ५०,००० एकड़ क्षेत्र में करने का विचार है। क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों में बागान लगाने का कार्य भारत में किसी भी स्थान पर किया गया है ?

†**श्री कानूनगो** : जी, हां। सभी राज्यों में।

†**श्री वासुदेवन नायर** : कितने एकड़ क्षेत्र में बागान लगा दिये गये हैं ?

†**श्री कानूनगो** : मैं प्रत्येक राज्य का एकड़ क्षेड़ नहीं बता सकता, किन्तु द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कुल ८०,००० एकड़ क्षेड़ में यह बागान लगे हुए थे।

†**श्री जसवंत मेहता** : द्वितीय योजना में इस कार्यक्रम के लिये कितनी अर्थसहायता दी गई थी और तृतीय योजना के प्रथम वर्ष में क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**श्री कानूनगो** : बागानों की लागत केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा ५० : ५० के अनुपात में वहन की जा रही है।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : विवरण के भाग (३) में यह बताया गया है कि तृतीय योजना काल में ५०,००० एकड़ क्षेत्र में बागान लगाये जाने हैं। अभी तक कितने क्षेत्र में बागान लगा दिये गये हैं ? फिर, विवरण के भाग (५) में यह बताया गया है कि अभी तक अछूते दुर्गम क्षेत्रों को खोज निकालने की सम्भावनाओं की छानबीन की जा रही है। वे किन किन राज्यों में हैं ?

†**श्री कानूनगो** : प्रश्न के प्रथम भाग के सम्बन्ध में, जैसा कि मैंने कहा है, योजना के प्रथम दो वर्षों के दौरान बागानों की प्रगति के आंकड़े मेरे पास नहीं हैं।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : यह जानकारी सभा-पटल पर रख दी जाये।

†**श्री कानूनगो** : जी हां, यदि एक प्रश्न पूछा जायेगा तो। प्रश्न के द्वितीय भाग के सम्बन्ध में, जिन नई किस्मों की प्रयोगशालाओं में जांच की गई है उनकी अभी तक कारखाने के स्तर पर जांच की जानी है तथा उसका आर्थिक रूप में लाभ निकाला जाना है।

मूल अंग्रेजी में

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : मेरा प्रश्न इससे भिन्न था। मैं अभी तक अछूते दुर्गम क्षेत्रों की खोज और छानबीन के तथा जिन राज्यों में यह की जायेगी उनके सम्बन्ध में पूछ रहा था।

†**श्री कानूनगो** : तृतीय योजना में प्रस्तावित लकड़ी के एकड़ क्षेत्र में वृद्धि करने की योजना में सभी राज्य सम्मिलित हैं। कदाचित्, यह कुछ राज्यों में थोड़ा अधिक होगा अथवा थोड़ा कम। मेरे पास आंकड़े नहीं हैं।

†**श्री हेडा** : लकड़ी की आम कमी को दृष्टिगत रखते हुए, क्या सरकार नरम गत्ते जैसी वैकल्पिक वस्तुओं को प्रोत्साहन देगी ?

†**श्री कानूनगो**: जैसा कि विवरण के भाग (४) में कहा गया है, वन अनुसन्धान संस्था में कुछ किस्मों के प्रयोगशाला स्तर पर परीक्षण किये गये थे। वाणिज्यिक स्तर में उनकी सम्भावनाओं तथा आर्थिक रूप में उपादेयिता का पता लगाया जाना है।

†**श्री क० ना० तिवारी** : क्या गवर्नमेंट को मालूम है कि नार्थ बिहार में साफ्ट टिम्बर बहुत ज्यादा तादाद में होता है और क्या वहां के जंगलों में इस को लगाने के लिए गवर्नमेंट के फ़ारेस्ट डिपाटमेंट की तरफ से कोई कोशिश की गई है ?

†**श्री कानूनगो**: यह तो कहीं भी काफी तादाद में नहीं है। इसका सम्बन्ध केवल एक ही किस्म की नरम लकड़ी सेमूल से है। उत्तर बिहार में वह अधिक मात्रा में नहीं होती। वास्तव में, किसी समय यह बहुत होती थी।

†**श्री जोकीम आल्वा** : क्या वाणिज्य मन्त्री इस बात से अवगत हैं कि मेरा निर्वाचन क्षेत्र, उत्तर कनारा, नरम लकड़ी के सबसे बड़े सम्भरणकर्ताओं में से एक है और एक विदेशी कम्पनी, वैस्ट इण्डिया मैच कम्पनी, सारी लकड़ी को सस्ते मूल्य पर खरीद रही है यद्यपि उस क्षेत्र के निधन ग्रामीण लोग उसके लिये अधिक अच्छा मूल्य मांग रहे हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति। एक प्रश्न पूछने के स्थान पर वह अपने निर्वाचन क्षेत्र के सम्बन्ध में जानकारी दे रहे हैं।

†**श्री जोकीम आल्वा** : क्योंकि उस क्षेत्र में बहुत सी नरम लकड़ी होती है अतः वहां एक दियासलाई का कारखाना प्रारम्भ करने के हेतु ग्रामीण लोगों की सहायता करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

†**श्री कानूनगो** : समाज कल्याण बोर्ड ने लगभग छः छोटे छोटे दियासलाई के कारखाने परीक्षण के तौर पर लगाये हैं। वे दक्षिण भारत के शिवकाशी क्षेत्र में बहुत भली भांति चल रहे हैं।

†**डा० गायतोंडे** : क्या यह सच है कि नागरवेली में बहुत बड़ी मात्रा में नरम लकड़ी उपलब्ध है ? यदि हां, तो उसका उपयोग करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**श्री कानूनगो** : मेरे विचार में यह सम्भव नहीं है। क्योंकि नरम लकड़ी की प्रत्येक किस्म की भारी कमी है इसलिये यदि इस प्रकार कोई बागान होते तो अवश्य ही वह खोज निकाले गये होते। फिर भी, मैं उस क्षेत्र के सम्बन्ध में पूछताछ करूंगा।

†**डा० सरोजिनी महिषी** : जहां तक दियासलाइयों के निर्माण का सम्बन्ध है हम किस सीमा तक नरम लकड़ी के स्थान पर अन्य पदार्थों को उसमें लगा सकते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कानूनगो :** जैसा कि मैंने विवरण के भाग (४) में बताया है, कुछ किस्मों के सम्बन्ध में प्रयोगशाला परीक्षण किये गये हैं। वाणिज्यिक स्तर पर उनके परीक्षण अभी किये जाने हैं।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया :** किस समय तक सरकार नरम लकड़ी की कमी को दूर कर सकेगी?

†**श्री कानूनगो :** ३५ वर्षों तक नहीं।

श्री तुलसीदास जाधव : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस देश में साफ्ट वुड की कितनी गर्ज (डिमांड) है और हम इस गर्ज को कितना पूरा कर सकते हैं।

†**श्री कानूनगो :** उस विशेष प्रकार की लकड़ी का सम्भरण बहुत कम है। इस प्रकार, इसकी सम्भरण स्थिति बहुत खराब होने जा रही है।

डा० गोविन्द दास : क्या इस बात की भी सम्भावना है कि जब यह लकड़ी काफी कम हो गई है, तो निकट भविष्य में हमको माचिस मिले ही नहीं? ऐसी हालत में क्या गवर्नमेंट प्राचीन पद्धतियों, चकमक पत्थर और दूसरी चीजों, को अपनाने के बारे में सोच रही है?

श्री कानूनगो : ऐसी सम्भावना तो नहीं है कि इतना अभाव हो जाएगा। और चकमक पत्थर की जगह तो लाइटर्ज का इस्तेमाल हो रहा है।

श्रीमती शशांक मंजरी : क्या सरकार ने लकड़ी की कमी को पूरा करने के लिए माचिस के दाम बढ़ाये हैं?

श्री कानूनगो : जी नहीं।

श्री कछवाय : मध्य प्रदेश के ग्रामोद्योगों के अन्तर्गत छोटे छोटे उद्योग चालू हैं और इनमें बांस की लकड़ी काम में लाई जाती है। क्या सरकार ने उस लकड़ी को काम में लाने को प्रोत्साहन देने का विचार किया है?

श्री कानूनगो : बांस की लकड़ी भी होती है लेकिन सिमूल की लकड़ी से अधिक सहूलियत होती है।

विद्युत् उपकरण संयंत्र

+

†*२४५. श्री भक्त दर्शन :
श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री वारियर :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री वासुदेवन् नायर :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री बालकृष्ण वासनिक :

†मूल अंग्रेजी में

श्री भागवत झा आजाद :
श्री मुरारका :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
डा० महादेव प्रसाद :

क्या इस्पात और भारी उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरिद्वार के पास रूस की सहायता से बनने वाले विद्युत् उपकरण सन्यन्त्र का परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उस पर विचार कर चुकी है ; और

(ग) क्या निर्णय किया गया है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)**: (क) से (ग). हरिद्वार के पास रूस की सहायता से बनने वाले विद्युत् उपकरण सन्यन्त्र का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन मैसर्स प्रोम्भाश एक्सपोर्ट, मास्को से प्राप्त हो गया है और रूसी विशेषज्ञों के सहयोग में हैवी इलैक्ट्रीकल्स (इंडिया) लिमिटेड के प्रविधिक विशेषज्ञ उसकी जांच कर रहे हैं।

श्री भक्त दर्शन : मैं जानना चाहता हूं कि इस प्रोजैक्ट रिपोर्ट को स्वीकार करने में अब कितना समय लगेगा और साथ ही प्रोजैक्ट रिपोर्ट के सिवाय और इस प्लांट को तैयार करने के लिये क्या क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : मुझे आशा है कि परियोजना प्रतिवेदन की जांच पड़ताल को लगभग सितम्बर के तीसरे सप्ताह तक अन्तिम रूप दे दिया जायेगा।

†**श्री रंगा** : मैंने आपसे पहले भी एक बार प्रार्थना की थी कि आप हमारी ओर से माननीय मन्त्रियों से थोड़ा जोर से बोलने की प्रार्थना करें। जो कुछ वे कहते हैं उसे हम समझ नहीं पाते।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं माननीय मन्त्रियों से कुछ अधिक जोर से तथा स्पष्ट रूप से बोलने के लिये कहूंगा।

श्री भक्त दर्शन : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के दूसरे खण्ड का उत्तर नहीं दिया गया है। मैं ने यह जानना चाहा था कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अतिरिक्त और किस किस तरह से इस प्लांट को जल्दी से जल्दी लगाने की तैयारियां की जा रही हैं और कब तक वह प्लांट लग जाने की आशा की जाती है ?

श्री प्र० चं० सेठी : प्रोजैक्ट रिपोर्ट के अतिरिक्त जहां तक प्लांट को लगाने की बात है, जमीन प्राप्त कर ली गई है, उसको बराबर वहां किया गया है, वहां एक टैक्नीकल स्कूल शुरू कर दिया गया है, बिजली और पानी की व्यवस्था उसके अन्दर की जा रही है, मकानों की तामीर का काम शुरू हो गया है, इत्यादि।

श्री भक्त दर्शन : देर से देर कब तक जैसी कि तैयारियां इस वक्त की जा रही हैं, यह प्लांट अपना काम शुरू कर देगा ?

†**श्री प्र० चं० सेठी** : आशा है कि १९६६–६७ में यह उत्पादन प्रारम्भ कर देगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** इस संयंत्र का अनुमानित उत्पादन कितना होगा, वहां किन-किन वस्तुओं का उत्पादन किया जायेगा और संयंत्र के पूरा होने के पश्चात् देश में उस वस्तु की आवश्यकता को हम कहां तक पूरा कर सकेंगे ?

†**श्री प्र० चं० सेठी :** इस संयंत्र में जल-विद्युत जनित्रों, टर्बोजनित्रों, भावी ए० सी० तथा डी० सी० मशीनों, मध्य आकार की ए० सी० तथा डी० सी० मशीनों, प्रारम्भ करने वाले, नियंत्रण करने वाले तथा पूरा करने वाले उपकरणों, जल-विद्युत तथा वाष्प टरबाइनों और उक्तलिखित के लिये अतिरिक्त पुर्जों का उत्पादन किये जाने की संभावना है । इस संयंत्र का अनुमानित उत्पादन ४० करोड़ रुपये के मूल्य का होगा ।

अध्यक्ष महोदय : सरदार अमर सिंह सहगल :

†**श्री अ० सिं० सहगल :** मेरा प्रश्न इसमें आ गया है ।

श्री यशपाल सिंह : क्या यह सही है कि हैवी इलैक्ट्रिकल्स के लिये हम लोगों से दो साल पहले जमीनें ले ली गई थीं और वे जमीनें दो साल से बेकार पड़ी हैं और एक कील भी उनमें नहीं लगाया जा सका है । हम लोग घर से बेघर किये गये हैं और बीस लाख की एग्रीकल्चरल प्राडक्शन में कमी हो चुकी है, क्या यह भी सही है ?

श्री प्र० चं० सेठी : जमीन बराबर करने के बाद उस जमीन पर तामीर का काम शुरू है । पहले जमीन को लेबल करने का काम शुरू किया गया था और बाकी तामीर का काम अब प्रारम्भ हो गया है ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** तृतीय पंचवर्षीय योजना की विद्युत् योजनाओं के सम्बन्ध में इन मशीनों की हमारी आवश्यकताओं को इस नये कारखाने में इन जनित्रों तथा टरबाइनों के उत्पादन द्वारा किस सीमा तक पूरा किये जाने की आशा है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम् :** मेरा विचार है कि माननीय सदस्य को यह ज्ञात है कि हमारे तीन उत्पादन केन्द्र होंगे—एक भोपाल में, दूसरा रामचन्द्रपुरम में और तीसरा हरद्वार में, हरद्वार का केन्द्र सब से बड़ा होगा । वर्तमान गणनाओं के अनुसार इन तीनों परियोजनाओं में पूरा उत्पादन प्रारम्भ होने पर भी कुछ कमी रह जायेगी । इस कमी को पूरा करने के लिये जो कदम उठाये जाने हैं हम उनकी जांच कर रहे हैं ।

†**श्री वारियर :** क्या परियोजना प्रतिवेदन में नक्शे और अन्य बात भी दी गई हैं ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** उन्होंने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन दिया है जिसमें नकशे, रूपांकन तथा अन्य बात सम्मिलित हैं ।

श्री ओंकारलाल बेरवा : हरिद्वार हमारा एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है और वहां पर एक नास्तिक देश, रूस के द्वारा प्लांट लगाया जा रहा है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या उस देश के द्वारा कोई शर्त तो नहीं रखी गई है कि तीर्थ स्थान भी वह हड़प कर जाये ?

श्री प्र० चं० सेठी : जी नहीं, यह स्थान तो तीर्थ स्थान से दूर है । तीर्थ स्थान तो गंगा के किनारे है ।

श्री ओंकारलाल बेरवा : रुपया लगाने में क्या उसने कोई शर्त इसके बारे में लगाई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री प्र० चं० सेठी : ऐसी कोई शर्त उनकी तरफ से नहीं लगाई गई है कि तीर्थ स्थान खत्म हो जाएगा, प्राजेक्ट रिपोर्ट बनने के बाद ।

†**श्री प्रिय गुप्त :** माननीय मंत्री ने कृपा करके उन वस्तुओं की सूची बता दी है जिनका कि कर्मशाला में उत्पादन किया जाना है । क्या मैं जान सकता हूं कि यांत्रिक ढलाई तथा खोल चढ़ाना और अन्य कार्य, यानी कि जो इसका यांत्रिक पहलू है, भी वहां पर किये जायेंगे अथवा ऐसा है कि कार्य का केवल विद्युत् सम्बन्धी भाग ही वहां पर किया जायेगा ?

†**श्री प्र० चं० सेठी :** एक ढलाई का कारखाना भी इसके साथ संलग्न है ।

अखबारी कागज का कारखाना

*२४६. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **उद्योग** मंत्री १५ मार्च, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७७९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में अखबारी कागज का कारखाना स्थापित करने के बारे में क्या निश्चय किया गया है ; और

(ख) उसे शीघ्र स्थापित करने के उद्देश्य से क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख). फर्म ने एक पुनरीक्षित प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिसमें कागज तथा अखबारी कागज का कारखाना लगाने का विचार व्यक्त किया गया है । इस कारखाने की क्षमता १०० टन प्रति दिन कागज तथा १०० टन प्रति दिन अखबारी कागज बनाने की होगी, जिसकी जांच की जा रही है ।

श्री भक्त दर्शन : जिस तरह का जवाब आज माननीय मंत्री जी ने दिया है, ठीक उसी तरह का जवाब आज से चार महीने पहले भी उन्होंने दिया था .....

अध्यक्ष महोदय : सवाल भी इसी किस्म का होगा उस वक्त भी ।

श्री भक्त दर्शन : जी नहीं .....

†**श्री म० ला० द्विवेदी :** जो प्रगति हुई है उसे वे जानना चाहते हैं ।

श्री भक्त दर्शन : उस समय माननीय मंत्री जी ने कहा था कि जो पार्टी इसको लगाने जा रही है, उन्होंने एक संशोधित परियोजना दी है और उस पर हम विचार कर रहे हैं । आज भी उन्होंने इस बात को दोहराया है । अतः मैं जानना चाहता हूं कि इस पर विचार कब तक चलता रहेगा और कब तक अन्तिम निर्णय लिया जायेगा ?

श्री कानूनगो : जो पुराना जवाब दिया, उसमें इस किस्म का प्रस्ताव उस वक्त नहीं था और न ही यह हमारे सामने था । अब प्रस्ताव आया है और इसमें एडवांटेज है कि सौ परसेंट बगास से कागज बनाया जाएगा । इससे सहूलियत होगी । इस प्रस्ताव की अच्छी तरह से जांच की जानी है ।

श्री भक्त दर्शन : चूंकि इस प्रश्न पर पिछले तीन चार वर्ष से विचार किया जा रहा है, इसलिये क्या हम आशा कर सकते हैं कि इसके बारे में जल्दी से जल्दी निर्णय किया जाएगा और इसको जल्दी से जल्दी स्थापित किया जाएगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री कानूनगो : स्थापित करने की तो कोशिश की जा रही है लेकिन यह जो देर हुई है उसमें हमको एक फायदा हुआ है। अब तक सौ परसेंट बगास से न्यूजप्रिंट बनाने का तरीका हमें मालूम नहीं था। अब यह प्रस्ताव है कि सौ परसेंट बगास में किया जाए और इसमें इम्पोर्टिड लांग फाइबर की जरूरत न होगी।

श्री शिव नारायण : जो प्रस्ताव आया है, इसको पूर्ण रूप से कब तक कार्यान्वित करने का सरकार विचार कर रही है ?

श्री कानूनगो : चन्द महीनों में ।

श्री विभूति मिश्र : उत्तर प्रदेश में भी शूगर फैक्ट्रीज हैं, जहां बगास होता है और बिहार में भी शूगर फैक्ट्रीज हैं, जहां बगास होता है। क्या सरकार के दिमाग में उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी कारखाने लगाने की बात है ?

श्री कानूनगो : एक तो लगे, तब दूसरे के बारे में देखा जाएगा।

†**श्री मानसिंह पू० पटेल :** क्या नेपा मिल्स की क्षमता बढ़ाई जा रही है ?

†**श्री कानूनगो :** नेपा मिल्स का प्रसार किया जा रहा है।

श्री म० ला० द्विवेदी : बगास के सौ परसेंट प्रयोग के लिए कौन लोग विचार कर रहे हैं ? जो विचार कर रहे हैं वे वैज्ञानिक अपने देश के हैं या विदेशी भी उसमें सहायता कर रहा है ?

श्री कानूनगो : विदेशी प्रासेस है, हम उसकी जांच कर रहे हैं कि वह प्रासेस हमारे यहां कामयाब होगा कि नहीं ।

श्री बालकृष्ण सिंह : क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अखबारी कागज की कमी के कारण कुछ मध्यम श्रेणी के अखबारों को अपने सर्कुलेशन में कमी करनी पड़ रही है ?

श्री कानूनगो : हां, चूंकि अखबारी कागज की बहुत कमी है इसलिये उसकी राशनिंग की जाती है ।

†**श्री शशि रंजन :** अखबारी कागज की कमी का पिछले कई वर्षों से अनुभव किया जा रहा है और कमी का प्रभाव प्रति वर्ष अधिकाधिक ही अनुभव किया जा रहा है । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार एसा कोई आश्वासन दे सकती है कि किस समय तक यह कमी दूर हो जायेगी ?

†**श्री कानूनगो :** मैं बस यही आश्वासन दे सकता हूं कि नेपा मिल्स का प्रसार किया जा रहा है।

†**श्री शशि रंजन :** क्या इस कठिनाई को दूर करने के लिये और कोई विशेष लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

†**श्री कानूनगो :** मांग बढ़ रही है और अखबारी कागज का उत्पादन करने की हमारी क्षमता पर्याप्त नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न काल में कोई भी आश्वासन नहीं मांगा जा सकता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री तुलसी दास जाधव : चूंकि महाराष्ट्र में बहुत से शुगर के कारखाने हैं और वहां वगास होती है इसलिये, मैं जानना चाहता हूं क्या वहां पर कोई न्यूजप्रिंट का कारखाना खोलने का विचार हैं ?

श्री कानूनगो : मैं ने अभी पहले के एक प्रश्न के उत्तर में कहा है कि पहले एक तो चालू हो तब दूसरे के बारे में सोचा जायेगा ।

डा० गोबिन्द दास : अभी मंत्री जी ने कहा है कि जहां तक नेपा कारखाने का सम्बन्ध है उसको बढ़ाने का विचार किया जा रहा है । क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि यह बात बहुत दिनों से विचाराधीन है ? क्या मैं जान सकता हूं कि यह कितना बढ़ाया जायेगा और कब तक बढ़ाया जायेगा ?

श्री कानूनगो : डबलिंग करने का विचार है ?

डा० गोबिन्द दास : कब तक ?

श्री कानूनगो : तीन चार साल में ।

†**अध्यक्ष महोदय :** शांति, शांति, । जब तक मैं किसी सदस्य को न पुकारूं उसे अपना प्रश्न पूछना प्रारम्भ नहीं करना चाहिये ।

†**श्री कृ० चं० पन्त :** क्या वगास का परीक्षण कर लिया गया है और अन्य देशों में सफलता पूर्वक उसका उपयोग किया जा रहा है अथवा हम ही पहली बार उसका उपयोग कर रहे हैं ?

†**श्री कानूनगो :** दक्षिणी अमरीका में कहीं उसका परिक्षण किया गया है ।

†**श्री वारियर :** क्या हमारी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं ने इसके लिये किसी प्रकार की प्रक्रिया अथवा अन्य किसी कच्चे माल का विकास किया है और प्रयोगशाला में अखबारी कागज के इस उत्पादन को सफलतापूर्वक पूरा किया है और क्या सरकार ने इसे देखा है ?

†**श्री कानूनगो :** वे कड़ी लकड़ी पर परीक्षण कर रहे हैं ?

†**श्री कछवाय :** मैं यह जानना चाहता हूं कि यह कारखाना कितनी लागत से लगेगा और उस से हमको कितने मुनाफे की आशा है ?

श्री कानूनगो : अभी इसका हिसाब नहीं लगाया गया है ।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ :** क्या इस विषय पर विशेषज्ञों की सलाह लेने के पश्चात् विचार कर के सरकार की यह राय हुई है कि केवल वगास ही ऐसी वस्तु अथवा कच्चा माल है जिस से कि अखबारी कागज बनाया जा सकता है, और अन्य जो जानकारी सरकार को मिली है क्या उन्हें यूंही छोड़ दिया जायेगा ?

†**श्री कानूनगो :** जरूरी नहीं है । यह एक प्रक्रिया है । अन्य प्रक्रियायें भी हैं, उदाहरणार्थ वे प्रस्ताव जो कि जम्मू तथा काश्मीर राज्य से आये हैं जहां कि वह चीड़ और देवदार से उत्पादन करना चाहते हैं । उसकी भी जांच की जा रही है ।

†**श्री बालगोबिन्द वर्मा :** अखबारी कागज के उत्पादन के मामले में किस प्रकार किस समय तक भारत आत्म निर्भर हो जायेगा ?

---

†मूल अंग्रजी में,

†**श्री कानूनगो** : मैं इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकता।

†**श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या मध्य प्रदेश अथवा अन्य किसी राज्य द्वारा छोटे पैमाने के उद्योगों में भी अखबारी कागज का उत्पादन प्रारम्भ करने के प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को भेजे गये हैं ?

†**श्री कानूनगो** : छोटे पैमाने के उद्योगों में यह नहीं किया जा सकता ।

भारतीय विदेश व्यापार संस्था

+

†*२४७. **श्री प्र० चं० बरुआ** :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री यशपाल सिंह :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री मुरारका :

क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विस्तृत बाजार सर्वेक्षण करने, वाणिज्यिक प्रचार करने और विशेषज्ञ अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए एक भारतीय विदेश व्यापार संस्था स्थापित की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्य कौन हैं और इसका प्रबन्ध करने वाले शासी निकाय में कौन कौन व्यक्ति हैं ;

(ग) चुने गये व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने के लिए क्या प्रबन्ध किया गया है ; और

(घ) क्या इस कार्य के लिये विदेशों से विशेषज्ञों की सेवायें प्राप्त की जायेंगी ?

†**अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां, । संस्था के विधान तथा प्रोग्राम की एक प्रति पटल पर रखी जाती है। **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० १५२६ / ६३]**

(ख) २००० रु० वार्षिक या २०,००० रु० एक दम देने वाला कोई भी व्यक्ति, समवाय या संगठन और संस्था इस संस्था की सदस्य बन सकती है। कार्यकारिणी समिति में सभापति महानिदेशक, केन्द्रीय सरकार के पांच अन्य मनोनीत व्यक्ति और सदस्यों के चुने हुए नौ व्यक्ति होंगे ।

(ग) प्रशिक्षण के मूल तथा पुनरध्यन पाठ्यक्रमों के लिये संस्था उस समय व्यवस्था करेंगे जब कि वह सक्रिय रूप से कार्य करना आरम्भ कर दे ।

(घ) दोनों भारतीय तथा विदेशी विशेषज्ञ संस्था की सेवा में रहेंगे ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या संस्था स्वायत्तशासी निकाय होगा या इससे सरकार स्वयं चलायगी और संस्था की स्थापना के लिए उसका आवर्तक तथा अनावर्तक व्यय कितना होगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : स्वायतशासी संस्था होगी और वित्तीय व्यवस्था आंशिक रूप शुल्क और अंशदानों से होगी और सीधी सरकारी अनुदानों से होगी ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : यह संस्था कौन कौन पुनरध्ययन पाठ्यक्रम आरम्भ करेगी और क्या उस में कोई विदेशी विशेषज्ञ होंगे या पढ़ाये जाने वाले विषयों का प्रशिक्षण लेने के लिए हमारे प्रशिक्षार्थियों को निदेश भेजा जायेगा ?

---

†मूल अंग्रजी में

†**श्री मनुभाई शाह** : संस्था के चार मुख्य खण्ड होंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या यह प्रकाशित सहित्य में है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जी हां, यह प्रकाशित साहित्य में है । यह साहित्य पूर्ण है ।

†**श्री श्री शिव नारायण** : क्या इस में कोई सरकारी मनोनीत व्यक्ति है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : आर्थिक-कार्य विभाग के सचिव इसके सभापति हैं। एक सदस्य मेरे मंत्रालय के हैं, एक योजना आयोग के हैं और प्रोफेसर हैं ।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि इस में हमारी इंडियन पार्लियामेंट का भी कोई रिप्रेजेन्टेटिव होगा ?

श्री मनुभाई शाह : यह टेकनिकल और एक्स्पर्ट लोगों का काम है । इस लिये इस में ज्यादातर एडमिनिस्ट्रटर्स होंगे चलाने के लिय इस को ।

अध्यक्ष महोदय : आइन्दा के लिये आप खुद सोच लीजिये ।

†**श्री म० ला० द्विवेदी** : जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया, साधारण सदस्य २ हजार रु० दे कर और विशेष सदस्य २० हजार रुपया दे कर ही हो सकता है ।, क्या मैं जान सकता हूं कि यदि कोई आदमी वैज्ञानिक है या टेकनिकल बातों को जानता है वह बगैर रुपय दिये हुए सदस्य नहीं हो सकता ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो आप बहस कर रहे हैं , आप सवाल पूछिये ।

श्री मा० ला० द्विवेदी : जब सरकार रुपया खर्च कर रही है तो क्या इस में विशेषक्ष नहीं रक्खे जा सकते ?

श्री मनुभाई शाह : यह तो ट्रेनिंग का सवाल है, इस में कोई हिस्सा बटने का सवाल नहीं है । यह तो जो एक्स्पर्ट लोग हैं, जो एक्स्पोर्ट और मार्केट रिसर्च का फायदा उठा सकते हैं, जो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में हिस्सा ले सकें, उन्हें स्पेशलिस्ट्स बनाने के लिये और अलग अलग जो चीजें हैं उन में रिचसर्च करने के लिये इन्स्टिट्यूशन है ।

†**श्री श्रीनारारण दास** : इस संस्था में किन देशों के विशेषज्ञ होंगे ?

†**श्री मनुभाई शाह** : कुछ अमरीका से आ सकते हैं और कुछ जापान से और कुछ दो विशेषज्ञ रूस के होंगे ?

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : सरकार इस संस्था के आरम्भ में कितना अनुदान देगी ? सरकार को किन आयुक्त विदेशी एजेंसियों से वित्तीय सहायता मिलने की आशा है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : अभी तो हमने संस्था के वार्षिक व्यय के लिए ४,७५ लाख रु० दिये हैं। संभव है कि संयुक्त राष्ट्र भी विशेष निधि अनुदान दे और इसी प्रकार टी० सी० एस० व फांर्ड प्रतिष्ठान भी अनुदान दें। संभव है कि कुछ धन योरोप के एक पूर्वीय देश से भी प्राप्त हो ।

†मूल अंग्रेजी में

†डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या बाजार अनुसन्धान तथा प्रदेश सर्वेक्षण और पण्य वस्तु सर्वेक्षण का प्रोग्राम इस संस्था ने सरकार के परामर्श से बना लिया है और क्या कोई विदेशी सहयोग प्राप्त हो गया है या प्राप्त करने का विचार है?

†श्री मनुभाई शाह : यह अभी आरम्भ हुआ है । वास्तव में, यह केवल एक पखवाड़ा पहिले ही आरम्भ हुआ था । परन्तु उस से भी पहिले, हमने बाजार-अनुसन्धान, और पण्य वस्तु सर्वेक्षण और प्रदेश सर्वेक्षण का प्रोग्राम बना लिया है और हम सहयोग भी कर रहे हैं। लन्दन प्रैस एक्सचेंजों के साथ करार होने वाला है । यह संगठन संसार में बाजार अनुसन्धान का सब से बड़ा संगठन है। संसार में अन्य संगठनों से भी वार्ता की जा रही है । वास्तव में, जिन दिनों मैं मास्को में था, हमने रूस में विदेश व्यापार अकादमी तथा केन्द्रीय बाजार अनुसन्धान संस्था से बात की थी। हम इन से भी सहयोग करेंगे ।

†श्री[redacted]शिव मूर्ति स्वामी : क्या सभी व्यापारियों के लिए या केवल इस संस्था के सदस्यों के लिये अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सम्बन्ध में निर्यात या आयात के लाइसेन्स प्राप्त का कोई प्रोग्राम है ?

†श्री मनुभाई शाह : यह प्रश्न इस मुख्य प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता ।

†श्री श्याम लाल सर्राफ : माननीय मंत्री के दिये गये उत्तर से विदित होता है कि यह संस्था दो काम करेगी ; एक शिक्षा सम्बन्धी होगा और दूसरा देश के बाहर सर्वेक्षण करना होगा । इन दोनों का आपस में कैसे ताल मेल हो सकता है ? क्या यह अन्त में प्रशिक्षण संस्था बन जायेगी या अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से सम्बद्ध सर्वेक्षण तथा अन्य पहलुओं को अपने हाथ में ले लेगी ?

†श्री मनुभाई शाह : जैसा कि आपने पहिले निदेश दिया था, मैंने इसकी व्याख्या नहीं की थी । पुस्तिका में सब दिया है ।

†अध्यक्ष महोदय : यदि यह उसमें दिया है तो इसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है ।

†श्री मनुभाई शाह : पुस्तिका में सब बातें दी हैं। मेरे माननीय सदस्य इसे पढ़ सकते हैं और फिर अपना प्रश्न पूछें।

†श्री जोकीम आल्वा : छोटे पैमाने के उद्योग और हस्तकला हमारे विदेशी व्यापार के अंग हैं परन्तु मैं देखता हूं कि इसमें उनका उल्लेख नहीं है और ये छोटे छोटे दल २००० रु० वार्षिक या २०,००० रु० एक साथ नहीं दे सकते। इनके लिये कोई स्थान क्यों नहीं रखा गया है ?

†श्री मनुभाई शाह : विशेषज्ञों के स्तर पर प्रतिनिधान सरकार द्वारा मनोनीत करने से होगा। यह बात नहीं है कि इसके लिए वे स्वयं चुने। जहां तक हस्तकला-सर्वेक्षण और बाजार अनुसन्धान की बात है, इस संस्था के ये कुछ मुख्य काम हैं। अतः जो लोग हस्तकला की वस्तुओं तथा अन्य वस्तुयें निर्यात करना चाहते हैं उन्हें सभी लाभ प्राप्त होंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दूसरा राज्य व्यापार निगम

+

†२४८. **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री घुलेश्वर मीना :
श्री राम चन्द्र उलाका :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :

क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री १३ अप्रैल, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ८४० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूसरे राज्य व्यापार निगम की रूपरेखा को इस बीच अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) इस निगम की मदद से कितनी धातु तथा खनिज का विदेशों को निर्यात तथा वहां से आयात किया जायेगा ?

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां । नये निगम का नाम मिनरल्स एण्ड मेटल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लि० होगा। आशा है कि यह १ अक्तूबर, १९६३ से काम करने लगेगा ।

(ख) यह निगम लौंह खनिज, मैंगनीज़ खनिज तथा अन्य खनिजों के निर्यात के अतिरिक्त समय-समय पर सरकार द्वारा निश्चित की गई अलौह तथा अन्य धातुओं का आयात भी किया करेगा । वर्तमान अनुमान यह है कि केवल लौह खनिज के निर्यात का लक्ष्य १९७०–७१ तक लगभग २०० लाख टन तक पहुंच जायेगा ।

श्री म० ला० द्विवेदी : अभी तक आयरन ओर के एक्सपोर्ट का काम स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन करता था । क्या कारण है कि इसकी एक अलग ब्रांच न खोल कर एक अलग कारपोरेशन बनाया जा रहा है ?

श्री मनुभाई शाह : इस वर्ष इस का काम बहुत बढ़ गया है । बहुत ज्यादा कमोडिटीज का काम स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन को हैंडिल करना पड़ रहा है । दुनिया में जब इस का काम बढ़ता है तो उसके लिए स्पेशल एजेंसीज़ नामजद कर दी जाती हैं । लेकिन केवल मिनरल ओर का डेढ़ सौ करोड़ का एक्सपोर्ट का और सौ करोड़ का इम्पोर्ट का प्रोग्राम है । इतने काम को स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन हैंडिल नहीं कर सकेगा । इसलिये दूसरे कारपोरेशन की जरूरत हुई ।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि यह कारपोरेशन मंत्रालय के अधीन होगा या इसका कोई सम्बन्ध मौजूदा स्टेट ट्रडिंग कारपोरेशन से होगा, और यदि होगा तो दोनों में समन्वय कैसे होगा ।

श्री मनुभाई शाह : आज भी कितने ही कारपोरेशन गवर्नमेंट आफ इंडिया के चल रहे हैं । इसमें तो आसान है । इसके तो हमने कांस्टीट्यूशन में ही एक इंटर कारपोरेशन बोर्ड की व्यवस्था रखी है । और कोआरडिनेशन का काम तो मिनिस्ट्री करती ही है ।

†**डा० गायतोंडे** : क्या यह निगम भी गोआ से लोह-अयस्क का निर्यात करेगा ?

---

†मूल अंग्रजी में

†**श्री मनुभाई शाह :** हां, । हमने छः सप्ताह पहिले गोआ में एक कार्यालय खोला है और अयस्क का निर्यात के लिये इसने गोआ में सभी खान मालिकों से बात की है ।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन से मंत्री जी कितना रुपया जूट खरीदने के लिए लगाना चाहते हैं क्योंकि जूट की हालत बहुत खराब है ।

श्री मनुभाई शाह : आज तक तो कारपोरेशन इस काम को कर ही रहा है और मैं माननीय सदस्य जी को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि अगले वर्ष के सीजन में और भी इस काम में तरक्की की जाएगी ।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया** : क्या मंत्रालय का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है कि जहां तक लौह-अयस्क के निर्यात का सम्बन्ध है, कुछ क्षेत्रों को सर्वथा छोड़ दिया गया है और जनता में बड़ी हलचल है कि निगम ने उन लोगों के साथ ठेका करने का कोई प्रयत्न नहीं किया है ?

श्री मनुभाई शाह : आन्ध्र प्रदेश की तनिक भी उपेक्षा नहीं की गई है । मैं सभा को बता दूं कि हमारे पास इतना अयस्क है कि हम पहिले उसे निकालना चाहते हैं जो सर्वाधिक लाभदायका है । हर जगह जाने थोड़ा खोदने और ऐसा अयस्क एकत्रित करने से जो मितव्ययी हो या अन्यथा कोई लाभ नहीं है । हमें इस मामले को दीर्घकालीन दृष्टि से देखना चाहिये ।

†**श्री वारियर :** मोनोज़ाइट और इल्मेनाइट को भी इस निगम के क्षेत्र में सम्मिलित करने के लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** हां । माननीय सदस्य को पूर्णतया विदित है कि हम इस बारे में भरसक प्रयत्न कर रहे हैं । परन्तु इस के बारे में एक प्रोद्योगिकीय अड़चन आ गई है जहां अन्य स्थानापन्न पदार्थ मिल रहे हैं : अतः कठिनाई है ।

†**श्री मलाइछामी :** उत्पादकों को अपने लौह-अयस्क का उचित मूल्य मिले, इसके लिए निगम ने क्या कार्यवाही की है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह काफी उचित बात है । आजकल हम जो मूल्य दे रहे हैं, वह संसार में सर्वाधिक है ।

श्री क० ना० तिवारी : जूट के लिये यह कारपोरेशन कितना रुपया देगा । कितना जूट खरीदेगा । और जो बिहार का जूट है उस के लिये इस साल कितने का बजट बनाया गया है ?

श्री मनुभाई शाह : इस में तो यह सवाल नहीं आता । इसके लिये अलग सवाल दें ।

†**डा० सरोजिनी महिषी :** इस बात का ध्यान रख कर कि संभव है कि देश का लौह-अयस्क का निर्यात बढ़ जाये, कारबार और मरमागाव की लदान क्षमता में कितनी वृद्धि होगी ?

†**श्री मनुभाई शाह :** इन सब बन्दरगाहों की जांच हो रही है । वास्तव में मैं बहुत शीघ्र एक या दो महीने में, लौह अस्यक के लिये खानों से परिवहन तथा बन्दरगाह सुविधाओं के विकास की एक वृहत् योजना सभा के समक्ष रखना चाहता हूं । ताकि अगले पांच, सात वर्षों में हम २००–२५० टन प्रति वर्ष निर्यात कर सकें ।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया :** मेरे प्रश्न को गलत समझा गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : जब मैं उन्हें दूसरा मौका दूंगा तो वह ठीक समझ लिया जायेगा।

†श्री दासप्पा : विभिन्न क्षेत्रों में अयस्क की उपलब्धता के बारे में अतिविरोध वक्तव्य क्यों होते हैं, जैसे, मैसूर में ३०० से ७१०० टन अयस्क उपलब्ध है ? उपलब्ध अस्यक की निश्चित मात्रा जानने के लिये क्या कार्यवाही की गई है।

†श्री मनुभाई शाह : हम इस मास को सर्वाधिक महत्व दे रहे हैं, विशेषकर उन क्षेत्रों के बारे में जिसका उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है। हाल में जर्मनी और इटली का एक विशेषज्ञ दल आया था और वे केन्द्रीय खान और ईंधन मंत्रालय और मैसूर सरकार से सम्बद्ध रहे। दुर्भाग्य की बात है कि उनका निर्णय कुछ भिन्न था। परन्तु मैं उन्हें आश्वासन दे सकता हूं कि दोनों मंत्रालय इस पर कार्य कर रहे हैं और संभावनाओं का पता लगा रहे हैं।

†श्री पें० वेंकटा सुब्बया: स्वीकृत क्षेत्र में भी जहां से राज्य व्यापार निगम लोह-अयस्क लेता रहा है, विद्यमान करार रोक दिया गया है ? ऐसा करने के क्या कारण हैं ?

†श्री मनुभाई शाह : वह किसी बात का उल्लेख नहीं कर रहे हैं। आन्ध्र के सम्बन्ध में मैं बता चुका हूं कि हम लोह-अयस्क खरीद रहे हैं वहां एक सहकारी समिति असफल हो गई है, जिसे हमने समय दिया था और वह ६०,००० रु० का सब से छोटा ठेका था। यदि बड़े क्षेत्र और बड़ी मात्रा में हैं जो हम से छूट गई हैं, तो वह हमें बता सकते हैं और हम उनकी जांच करेंगे।

मोटर साइकिलों का निर्माण

\+

*२४६. श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री स० मो० बनर्जी :
डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री द्वारका दास मंत्री :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री शिवमूर्ति स्वामी :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्कूटरों, मोटर साइकिलों तथा आटोसाइकिलों के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) उनका संभरण मांग से कितना कम है तथा मांग कब तक पूरी हो जाने की आशा है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इनकी कीमतें अधिक होने के क्या कारण हैं ; और

(घ) इन्हें कम मूल्य पर उपलब्ध करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख). तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक मोटर साइकिलों, स्कूटरों तथा आटोसाइकिलों इत्यादि के उत्पादन का लक्ष्य ६०,००० (संख्या) प्रतिवर्ष का है। यह क्षमता आठ फर्मों को दिए गए लाइसेंसों से पूर्णतया पूरी हो जाती है। पांच फर्में उत्पादन कर रही हैं। १९६२ और १९६३ (जनवरी से जून तक) में उनका कुल उत्पादन क्रमशः २५,०४० (संख्या) और ११,९४७ (संख्या) था।

वर्तमान सप्लाई मांग को पूरा करने में नाकाफी है। दो लाइसेंस की गई इकाइयों के इस वर्ष या अगले वर्ष के शुरु में उत्पादन करने लगने की संभावना है। इससे स्थिति म कुछ हद तक सुधार हो जायेगा। फिर भी विदेशी मुद्रा की कठिनाई के कारण एक या दो वर्ष तक पर्याप्त मात्रा में उत्पादन होने की संभावना नहीं है।

(ग) और (घ). उत्पादन की अधिक लागत के मुख्य कारण हैं :—(१) गाड़ियों का थोड़ी मात्रा में उत्पादन और (२) देशीय तथा आयात किए गए कच्चे माल और तैयार पुर्जों की अनुपाततः अधिक लागत। उत्पादन में वृद्धि से कीमतों में कमी की जा सकती है विदेशी मुद्रा की सीमित उपलब्धि इसके रास्ते में रुकावट है । जब तक गाड़ियों में देशीय पुर्जे पर्याप्त मात्रा में इस्तेमाल नहीं होने लगते तब तक उत्पादन में सार्थक वृद्धि होना संभव नहीं है । देशीय माल की मात्रा को बढ़ाने के लिए निर्माताओं को पूंजीगत माल का आयात करने के लिए आवश्यक सुविधाएं दी गई हैं। जिस समय देशीय माल की मात्रा ९० प्रतिशत के लगभग पहुंच जायेगी तब उत्पादन में वृद्धि संभव हो सकेगी और इस प्रकार उनकी उत्पादन लागत और विक्रय मूल्य में कमी की जाना सम्भव होगा।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं हैवी इंडस्ट्रीज मंत्रालय के पत्र संख्या ए० ई० ३०५/१३ ( ) ६२ दिनांक २० मार्च की ओर मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं, जिसमें कहा गया है कि वैस्पा और लेम्ब्रटा को एक ही रंग में बनाया जाए, लेकिन अब भी उनको दो रंगों में बना कर ज्यादा दाम चार्ज किया जा रहा है जैसा कि वाउचर्स से विदित होता है । मैं जानना चाहता हूं कि कम्पनी मंत्रालय के आदेश का पालन क्यों नहीं कर रही ?

श्री प्र० चं० सेठी : आम तौर पर कुछ लोग दो रंगों में पसन्द करते हैं इसलिए दो रंगों में बनाया जाता था, लेकिन अगर मंत्रालय की आज्ञा के बाद ऐसा हुआ है तो उसकी ओर ध्यान दिया जाएगा।

†**श्री म० ला० द्विवेदी**: मंत्रालय ने निश्चय ही निम्न उल्लेख किया है :

> "यह भी निश्चय किया गया है कि वर्तमान संकट का ध्यान रख कर दोनों वैस्पा और लेम्ब्रटा इस के बाद एक ही रंग के बनने तथा बिकने चाहियें।"

और इतने पर भी वे एक स्कूटर पर रंग के लिए ३० रुपये अधिक लेते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : हम नहीं जानते कि यह आदेश देने से पहिले या बाद में उत्पादन का भाग बनता है, परन्तु हम निश्चय ही इसकी जांच करेंगे और यदि उत्पादन आदेश देने के बाद हुआ है, तो हम कार्यवाही करेंगे।

†**श्री म० ला० द्विवेदी** : इस पत्र में मिनिस्टर साहब ने लिखा था कि वैस्पा और लैम्ब्रटा की कीमत १८८४ रुपए ही होगी। लेकिन वैस्पा वाले १९०५ चार्ज कर रहे हैं और लोगों को कुल मिलाकर करीब २८०० रुपए देने पड़ते हैं। इस पत्र में लिखा है कि वैस्पा और लेम्ब्रटा की कीमतें घटायी जायेंगी। लेकिन इस सम्बन्ध में अभी कुछ नहीं हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि मंत्रालय कीमतों को कम करने के लिए क्या कर रहा है?

†**श्री प्र० चं० सेठी** : अध्यक्ष महोदय, जहां तक कीमतों का सवाल है उन पर कोई स्टेट कंट्रोल नहीं है। जहां तक लैम्ब्रटा स्कूटर की कीमत का सवाल है, वह १८८३ रुपए फिक्स की गयी है। उत्पादन के पीछे जब कस्टमस अफसर जाता है तो उसकी कीमत तय की जाती है। लेकिन अगर कस्टम्स एक्साइज में बढ़ोतरी हो जाए या कम्पोनेन्टँस के भाव में या शिपिंग और फ्रैट में बढ़ोतरी हो जाए, तो उनके आधार पर कीमत को स्केल अप कर दिया जाता है।

†**श्री स० चं० सामन्त** : विवरण से पता लगता है कि निर्माताओं को पूंजी वस्तुओं का आयात करने की आवश्यक सुविधायें दी गई हैं ताकि गाड़ियों में स्वदेशी पुर्जों की मात्रा बढ़ाई जा सके। अब भी मैं देखता हूं कि १९६३ के पहिले ६ महीने का उत्पादन उत्साह-वर्धक नहीं है। इसमें क्या अड़चनें हैं?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : इसका उद्देश्य स्वदेशी पुर्जो में सुधार करना है। जब तक उनका उत्पादन आरम्भ होगा, तब तक हमें आयात करना होगा और इसके लिए हमारे पास विदेशी मुद्रा पर्याप्त मात्रा में नहीं है। यही कारण है कि चालू वर्ष में उत्पादन कम हो गया है।

श्री ओंकारलाल बेरवा : सरकार ने स्कूटर बेचने के लिए कुछ कम्पनियों को लाइसेंस दे रखा है, और वे परमिट सिस्टम पर बेचे जाते हैं। और इसमें से काफी मात्रा में ब्लैक में बिकते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस परमिट सिस्टम को हटाने के लिए सरकार कुछ कार्रवाई कर रही है जिससे ये ब्लैक में न जाएं?

श्री प्र० चं० सेठी : इनकी उत्पादन क्षमता ६०,००० रखी गयी है। लेकिन १९६२ में केवल २५,००० का उत्पादन हुआ। ऐसी सूरत में जो लोग लेने के लिए अर्ज़ी देते हैं उनको क्रानालाजीकल आर्डर में मिलता है।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : यहां बताया गया है कि जिन परियोजनाओं के लिए लाइसेंस दिये गये हैं। उनमें से पांच पहिले से ही कार्य कर रहे हैं और तीन में अभी उत्पादन आरम्भ नहीं हुआ है। क्या उत्पादन आरम्भ होने के लिए कोई अन्तिम तारीख निर्धारित की गई है और क्या उनसे कह दिया गया है कि यदि वे निर्धारित समय का पालन नहीं करेंगे तो उनका लाइसस रद्द कर दिया जायेगा?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : साधारणतया हम यथोचित समय देते हैं और यदि वे उत्पादन आरम्भ करने की कार्यवाही नहीं करते तो हम लाइसेंस रद्द कर देते हैं। वास्तव में एक उत्पादक को नोटिस दे दिया गया है कि वह अपना लाइसेंस छोड़ दे।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री भानु प्रकाश सिंह : क्या मंत्री महोदय यह जानते हैं कि स्कूटर्स के सम्बन्ध में काला बाजार चल रहा है, यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री प्र० चं० सेठी : जैसा कि मैं ने शुरू में बतलाया स्कटर्स प्रोड्यूसर्स के जो नियक्त किये हुए डीलर्स हैं उन के यहां से यह क्रोनोलाजिक्ल आर्डर में मिलते हैं। इस तरह की कोई शिकायत अभी मेरे नोटिस में तो आई नहीं है ।

श्री रामेश्वरानन्द : स्कटर वालों से जब हम बाचतीत करते हैं तो यह भावना निकलती है कि देश में बनने वाले स्कूटर्स विदेशों में बने स्कूटरों की अपेक्षा घटिया किस्म के हैं। वे लोग कहते हैं कि पुराने विदेशों में बने स्कूटरों की अपेक्षा देश में बने यह स्कूटर्स घटिया हैं। इस भावना को बदलने के लिए सरकार क्या कोई यत्न कर रही है ताकि यहां पर बन रही मोटरसाइकलें और स्कूटर्स अच्छे हों और विदेशों में पुराने बने हुए स्कूटरों से लोग उन्हें घटिया न समझें ?

श्री प्र० चं० सेठी : जहां तक मजबूती और किस्म का सवाल है यह उन से घटिया नहीं है क्योंकि उनको बनाने वाली वही विदेशी मूल कम्पनियां हैं और वही टैक्नीशियंस उसी किस्म की डिजाइंस के स्कूटर्स यहां तैयार कर रहे हैं ।

श्री प्र० चं० बरुआ : हाल में जापानी और चैकोस्लावाकिय के सहयोग से कुछ सस्ते स्कूटर बने हैं । क्या यह सच है कि उनमें कुछ निश्चित दोष हैं और यदि हां, तो वे क्या हैं और दोनों की जांच करने के लिए क्या निश्चित कार्यवाही की गई है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** मेरे पास चैकोस्लावाकिया के सहयोग संबंधी जानकारी नहीं है । यदि माननीय सदस्य जानना चाहें तो पृथक पूर्व सूचना दे दें ।

लन्दन में व्यापार मंत्रियों का सम्मेलन

\+

†*२५०. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री प्र० के० देव :
श्री श्री नारायण दास :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री वारियर :
श्री बूटा सिंह :

क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई के दूसरे सप्ताह में लन्दन में हुए व्यापार मंत्रियों के सम्मेलन में भारत ने भाग लिया था ;

(ख) यदि हां, तो अविकसित देशों के लिए मंडियां खोलने के लिए क्या निर्णय किये गये ; और

(ग) यूरोपीय सांझा बाजार में ब्रिटेन के सम्मिलित न होने पर सम्मेलन की क्या प्रतिक्रिया हुई और इसका भारतीय व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

†**अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) जी हां ।

(ख) और (ग). सम्मेलन के बाद जारी की गई विज्ञप्ति की एक प्रति पटल पर रखी जाती है । [पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० १५२७/६३] ई० ई० सी० और

†मूल अंग्रेजी में

ब्रिटेन की वार्ता के फलस्वरूप यूरोपीय साझा बाजार में ब्रिटेन सम्मिलित न हो सकने के कारण, इन देशों में भारतीय व्यापार के प्रति उनके रवैये में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** बैठक में भारत ने क्या मुख्य प्रस्ताव पेश किये थे और लन्दन-सम्मेलन में किये गये निश्चयों में उन्हें कहां तक शामिल किया गया है और प्रशुल्क वार्ता के "कनेडी राउण्ड" की प्रक्रिया पर विचार विमर्श करने के लिए हुए जनेवा सम्मेलन में उन्हें कहां तक स्वीकार किया गया ?

श्री मनुभाई शाह : सम्मेलन में मुख्य प्रस्ताव यह था कि राष्ट्र मण्डल के व्यापार भागीदारों को मिले हुए किसी भी अधिमान को उस समय तक कम या समाप्त न किया जाये जब तक अधिमान्य परिवर्तन के अन्तर्गत आने वाली कोई भी विशिष्ट पण्य वस्तु के तत्स्थानी लाभों की उचित पूर्त्ति न हो जाये। इसे पूर्णतया स्वीकार कर लिया गया है हालांकि आरम्भ, में कोई आधार न था। इसके परिणामस्वरूप केवल चाय पर, जिससे अधिमान हटाया जायेगा, प्रभाव पड़ेगा। हमें ५ प्रतिशत अधिमान मिला हुआ है और उसके मुकाबले हमें २२ प्रतिशत शुल्क वापस मिलती है जो यूरोपीय साझा बाजार के देशों में हमारी चाय पर लगा था और यह घटकर ५ प्रतिशत रह जायेगा। साधारण रूप में हमारी मुख्य मांग यह थी। हमने अन्य अनेक बातें उठाई और विज्ञप्ति में उनका पूर्ण उल्लेख है। व्यापार तथा प्रशुल्क संबंधी सामान्य करार पर इसके प्रभाव के बारे में यह बात है कि राष्ट्रमण्डलीय व्यापार मंत्री सम्मेलन में प्राय जो भी हमने स्वीकार किया था उसे व्यापार तथा प्रशुल्क संबंधी सामान्य करार के देशों ने भी स्वीकार किया।

†**श्री श्रीनारायण दास :** क्या प्रारम्भिक उत्पादों पर औद्योगीकृत देशों द्वारा लगाये जाने वाले प्रतिबन्धों के बारे में कोई हल मालूम हुआ और यदि हां, तो वह हल क्या है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** यह बात राष्ट्रमण्डल मंत्री सम्मेलन में नहीं हुई जो कि अब प्रश्न का विवरण है। यह बात व्यापार तथा प्रशुल्क संबंधी सामान्य करार के देशों के सम्मेलन में हुई थी। यह प्रश्न उसमें उठाया गया था और मैंने प्रारम्भिक उत्पादकों के मत प्रस्तुत किये कि कोई प्रशुल्क या मात्रा का प्रतिबन्ध न होना चाहिये।

"इलैक्ट्रोड्स" का अभाव

†***२५१. श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **आर्थिक और प्रतिरक्षा समन्वय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समय से इंजीनियरी उद्योगों में प्रयोग के लिये 'इलैक्ट्रोड्स' की भारी कमी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका रेलवे वैगनों तथा प्रतिरक्षा के लिए आवश्यक अन्य वस्तुओं के उत्पादन पर कितना प्रभाव पड़ा है ?

†**आर्थिक और प्रतिरक्षा समन्वय मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) :** (क) और (ख) प्रतिरक्षार्थ उद्योगों की बढ़ी हुई आवश्यकताओं के परिणामस्वरूप "वैलडिंग इलैक्ट्रोड्स" की मांग एकदम बढ़ जाने से इंजीनियरी उद्योगों के कुछ क्षेत्रों में 'इलैक्ट्रोड्स" की कमी बढ़ गई है। जो दो वैगन निर्माताओं की ओर से अभ्यावेदन प्राप्त हो गया है कि "इलैक्ट्रोड्स" की उपलब्धता कम है, समूचे रूप में रेलवे वैगनों की उत्पादन-दर पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ा है। सरकार ने "इलैक्ट्रोड्स" की बढ़ी मांग पूरा करने के लिए अनेक कार्यवाही की हैं और उनका उत्पादन निरन्तर बढ़ रहा है।

---

†मूल अंग्रजी में

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या कोई योजना विचाराधीन है जिससे, इलैक्ट्रोड्स के लिए उत्पादिता क्षमता में वृद्धि होने तक, पर्याप्त स्टाक बनाये जा सके ताकि इस प्रकार के अस्थायी अभाव न हों ?

†**श्री जगन्नाथ राव** : जी, हां । मंत्रालय ने यह देखने के लिए कुछ कार्यवाही की है कि इलैक्ट्रोड्स पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो । उदाहरणार्थ, ३० लाख रु० के मूल्य के आयात लाइसेंस दिये जा रहे हैं । दूसरे, रेलवे बोर्ड ने विश्व बैंक ऋण के अधीन ४००० टन इलैक्ट्रोड्स इस्पात छड़ें आयात करने की व्यवस्था की है । तीसरे, लोहा और इस्पात नियन्त्रक ७००० टन इलैक्ट्रोड्स इस्पात छड़ें बनाने के लिए कार्यवाही कर रहा है जो कि ब्रिटेन ऋण के अधीन आयात की जा रही हैं ? चौथे, वेल्डिंग इलैक्ट्रोड इस्पात छड़ों के उत्पादन के लिए देश में निर्माताओं के साथ व्यवस्था की जा रही हैं । ये छड़ें उद्योग की स्वीकार्य कुछ वस्तु विवरण भेद वाली होंगी ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : मेरा निवेदन है कि जो उत्तर दिया जा रहा है वह विवरण के रूप में दे दिया जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं उनसे इसे पटल पर रखने के लिए कह दूंगा ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या यह सच है कि इलैक्ट्रोड के भीतर का चक्करदार तार अभी तक देश में नहीं बनता है और इस प्रकार क्या कोई विशिष्ट लाइसेंस दिये गये हैं या इलैक्ट्रोड्स में प्रयुक्त आयातीत अंश के निर्माण के लिए कोई परियोजना आरम्भ की जा रही है ?

†**श्री जगन्नाथ राव** : यह सच है कि इन इलैक्ट्रोड का मुख्य अंश, अर्थात् चक्करदार तार आयात होता है और आशा है कि विदेश में इस तार का निर्माण होगा ।

†**श्री यशपाल सिंह** : क्या यह सही है कि रूड़की युनिवरसिटी की तरफ से यह औफर किया गया था कि अगर उसे इनकरैजमेंट मिले तो वह एलैक्ट्रोड्स के प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं और इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं और यह कि युनिवरसिटी को इसके लिए इंसैंटिव नहीं मिला ?

†**श्री जगन्नाथ राव** : जी नहीं । आजकल छः कारखाने इलैक्ट्रोड बना रहे हैं और नौ अन्य फर्मों को लाइसेंस दे दिये गये हैं और चार अन्य फर्मों को भी इन्डैंट पत्र दे दिये गये हैं ।

†**श्री प्रिय गुप्त** : भारत में औद्योगीकरण के समय से वेल्डिंग की बड़ी मांग रही है और इस कारण क्या मंत्रालय ने भारत में इन इलैक्ट्रोड्स तथा अन्य एलीमेंट वाले इलैक्ट्रोड्स के उत्पादन के लिए कोई निर्माण कारखाना बनाया है ?

†**श्री जगन्नाथ राव** : योजना आयोग ने १,०८० चालू फीट क्षमता निर्धारित की है और आशा है कि इन कारखानों के बनने पर मांग पूरी हो जायगी ।

श्री रामेश्वरानन्द : यह विद्युत् की न्यूनता के कारण हमारे उत्पादन पर प्रभाव पड़ रहा है तो क्या विद्युत् वस्तुतः न्यून है अथवा इस विद्युत् शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महादय : यह एलक्ट्रोड्स के सम्बन्ध में है ।

†**श्री वारियर** : सरकार को इन कारखानों में कब तक इलैक्ट्रोड्स तथा आवश्यक वस्तुओं, जैसे चक्करदार तार, आदि का उत्पादन आरम्भ होने की आशा है ?

†**वित्त और प्रतिरक्षा समन्वय मंत्रालय में संभरण मंत्री (श्री हाथी)** : हम १९६५ तक लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे ।

गैर सरकारी क्षेत्र के इस्पात के कारखानें

+

†२५२. **श्री प्र० चं० बरुआ** :
श्री सरजू पाण्डेय :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री २६ अप्रैल, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या १०५४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों के विस्तार की योजना के बारे में इस बीच अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) विस्तार के लिए सिद्धान्ततः सामान्य स्वीकृति दे दी गई है परन्तु अन्तिम स्वीकृति तभी दी जायेगी जब प्राडक्ट मिक्स (तैयार माल की किस्म) और विस्तार के लिए वित्त व्यवस्था करने के बारे में स्पष्ट रूप से फैसले हो जायेंगे । कम्पनियों द्वारा तैयार की गई रिपोर्टों तथा भारतीय और विदेशी मुद्रा की अनुमानित लागत के आधार पर इन मामलों पर शीघ्र ही विचार किया जायेगा ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या गैर-सरकारी क्षेत्र के विद्यमान इस्पात संयंत्रों ने अपने क्षमता बढ़ाने का कोई प्रस्ताव किया है और यदि हां, तो कितनी मात्रा में वृद्धि करने की अनुमति दी जायेगी ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : २० लाख मीट्रक टन से बढ़ाकर ३० मीट्रक लाख टन करने का टिस्को का प्रस्ताव और १० लाख मीट्रक टन से बढ़ा कर २० लाख मीट्रक टन करने का इंडियन आयरन का प्रस्ताव है ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या गैर-सरकारी क्षेत्र के इन इस्पात कारखानों को कोई सरकारी सहायता दी जायगी ; यदि हां तो कितनी सहायता दी जायेगी ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : हम उत्तर दे चुके हैं कि उनके निश्चित प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर यह विचार किया जायेगा कि सरकार क्या सहायता दे सकती है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : विस्तार के लिए टिस्को को १० करोड़ रु० का ऋण दिया गया था । क्या सरकार को वह राशि अब तक प्राप्त हो गई है ; यदि नहीं, तो उसके प्राप्त न होने के क्या कारण हैं ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : यह राशि प्राप्त नहीं हुई है । आजकल इस पर सरकार और टिस्को के बीच विचार-विमर्श हो रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रश्नों के लिखित उत्तर

लोहा

*२४४. **श्री बाल्मीकी :** क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश को लोहे में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं ; और

(ख) इस काम के कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) : कच्चे लोहे के उत्पादन को बढाने के लिये सरकारी और निजी क्षेत्र की प्रायोजनाओं में अतिरिक्त क्षमता लाइसेंस की जा रही है । चौथी योजना की प्रत्याशा में भिलाई में एक धमन भट्टी लगाने का भी विचार है । बहुत सी बड़ी और छोटी भट्टीयां लगाने के बारे में विचार किया जा रहा है । इस साल के अन्त तक पक्के फैसले किए जाने की संभावना है ।

मोटरों के पुर्जे

†२५३. **श्री मोहन स्वरूप :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री गुलशन :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री बड़े :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी ह कि देश में मोटरों के पुर्जों, टायरों व ट्यूबों की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि बाजार में इन चीजों की कमी है और इनको चोर बाजार में बेचा जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति सुधारने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) सरकार को कीमतों में हुई कथित वृद्धि के बारे में कोई भी शिकायतें नहीं मिली हैं ।

(ख) मोटरों के टायरों और ट्यूबों की कमी नहीं है तथा इनका इतना उत्पादन होता है कि देश की मांग पूरी कर के निर्यात के लिये भी फालतू माल बच जाता है । जहां तक मोटरों के पुर्जों का सम्बन्ध है देश में बढ़ता हुआ उत्पादन भी आवश्यकता को देखते हुए कम है किन्तु पुराने आयातकों तथा वास्तविक उपयोक्ताओं को ही इनका आयात करने की अनुमति दी जाती है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से स्थापित परियोजनायें

†*२५४. **श्री हेम राज :**
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री राम रतन गुप्त :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चेकोस्लोवाकिया की सरकार के सहयोग से तीसरी योजना की अवधि में कौन-कौन सी परियोजनाएं और किन-किन स्थानों पर स्थापित की जा रही हैं ;

(ख) उन परियोजनाओं की लागत कितनी है और क्या चेकोस्लोवाकिया की सरकार भारत सरकार को ऋण दे रही है ; और

(ग) उन्हें स्थापित करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख). २४ नवम्बर, १९५९ के चेकोस्लोवाकिया सहयोग ऋण करार (जिसकी प्रतियां संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध हैं) से तीसरी योजनावधि में निम्नलिखित परियोजनायें स्थापित की जा रही हैं। पूंजीगत व्यय के अनुमान नीचे दिये जाते हैं :—

परियोजनायें	स्थापना स्थान	पूंजीगत लागत के अनुमान
		(करोड़ों रुपये)
१. ढलाई तथा गढ़ाई कारखाने का तीसरा क्रम	रांची (बिहार राज्य)	२४·६६
२. नया मशीनी औजार कारखाना	तदेव	२३·३०
३. हाई प्रैशर बायलर प्लांट	तिरुचिरापल्लि (मद्रास राज्य)	१८·००
४. हैवी पावर इक्विपमेंट प्लांट	रामचन्द्रपुरम, हैदराबाद के निकट (आंध्र प्रदेश)	२७·५०

(ग) इन परियोजनाओं के ब्यौरेवार परियोजना प्रतिवेदन स्वीकार कर लिये गये हैं तथा मशीन और उपकरण के संभरण के लिए तथा कारखाने की स्थापना के प्रविधिक सहयोग के ठेके में मैसर्स टेक्नोएक्सपोर्ट, प्रेग में कर दिए गए हैं। इन ठकों की प्रतियां संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

रबड़ का कारखाना

†*२५५. **श्री प० कुन्हन** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी सहयोग से रद्दी रबड़ से रबड़ तैयार करने के लिए केरल में एक कारखाना खोलने के लिए सरकार ने किसी गैर-सरकारी फर्म को लाइसेंस दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उस फर्म का नाम क्या है ;

(ग) कारखाने की अनुमानित लागत कितनी है ; और

(घ) इस कारखाने में उत्पादन कब से शुरू होने की आशा है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख) मैसर्स जयहिन्द एजेंसीज, कोचीन में बताया है कि सरकार उनको अमरीकी साथ के सहयोग से केरल में एक रबड़ बनाने का कारखाना स्थापित करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस देने को तैयार हैं यदि वह सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने योग्य शर्तों पर कारखाना तथा मशीनें आयात करने में समर्थ हों।

(ग) लगभग १५ लाख रुपये।

(घ) औद्योगिक लाइसेंस दिये जाने के बाद लगभग दो वर्षों में कारखाने में उत्पादन आरम्भ हो जाने की आशा है।

संयुक्त राष्ट्रसंघ सहायता 'क्लब'

†*२५६. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगले वर्ष होने वाले व्यापार तथा विकास सम्मेलन के लिए जनेवा में आयोजित ३२ राष्ट्रों की प्रारम्भिक बैठक में भारतीय प्रतिनिधि ने संयुक्त राष्ट्रसंघ सहायता 'क्लब' बनाये जाने का प्रस्ताव रखा था ; और

(ख) यदि हां, तो अन्य प्रतिनिधियों की क्या राय थी ?

†**अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कच्चा पटसन

†*२५७. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :**
श्री द्वारका दास मंत्री :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कच्चे पटसन का इस मौसम के लिए निर्धारित किया जान वाला न्यूनतम मूल्य कब घोषित किया जाएगा ;

(ख) प्राथमिक उत्पादकों के लाभार्थ पटसन पैदा करने वाले देहाती इलाकों के बीचोबीच खरीद केन्द्र कायम करवाने के लिये राज्य व्यापार निगम द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ; और

(ग) पश्चिम बंगाल में ऐसे कितने केन्द्र खोलने का विचार है ?

†**अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) ८ अप्रैल, १९६३ को सभा में आगामी ऋतु में न्यूनतम मूल्य घोषित कर दिया गया था और किसी परिवर्तन के होने तक यही नीति रहेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस समय राज्य व्यापार निगम राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ जोकी राज्यों में अपैक्स सहकारी समितियों का प्रतिनिधि है, के द्वारा अपनी खरीददारी करता है। निगम के सुझावों के अनुसार चालू मौसम में माध्यमिक बाजारों से समाहार केन्द्रों में खरीददारी की जायेगी। इन माध्यमिक बाजारों को जूट उगाने वाले राज्यों की कई सौ प्राइमरी विपणन समितियों से जोड़ दिया जायेगा।

(ग) १०० प्राइमरी विपणन समितियों से लगे हुए ३२ विपणन केन्द्रों के पश्चिम बंगाल में शीघ्र ही खुल जाने की आशा है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

†*२५८. **डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :**
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने जुलाई में हैदराबाद में बोलते हुए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को दफ्तरों में होने वाले विलम्बों, सार्वजनिक वाद-प्रतिवाद तथा राजनीतिक हस्तक्षेप के शिकंजे से विमुक्त करने की आवश्यकता पर बल दिया था;

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में यह प्रवृत्तियां किस सीमा तक तथा किस ढंग में दिखाई देती हैं; और

(ग) वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) से (ग) इस्पात और भारी उद्योग मंत्री ने हैदराबाद में अपने भाषण में बताया था कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का प्रशासन सुधारा जाना चाहिए तथा यह भी बताया था कि औद्योगिक इकाइयों को चलाने के लिए सरकारी प्रक्रिया ठीक नहीं होती है। इन उपक्रमों का इतिहास देखने से मालूम होता है कि यह सच है कि इन उपक्रमों में सरकारी प्रक्रिया अपनाने की प्रवृत्ति है। हाल में हमें पूरे मामले पर वरिष्ठ सरकारी कर्मचारियों की बैठक में चर्चा हुई थी। इन अधिकारियों से कहा गया था कि आवश्यक सुधार किस प्रकार किए जा सकें इसकी जांच करें। इस सरकारी समिति की सिफारिशें विचाराधीन हैं।

निर्यात

†*२५९. **श्री मुरारका :**
श्री रवीन्द्र वर्मा :

क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या सरकार निर्यात को बढ़ावा देने की दृष्टि से हमारी निर्यात समस्याओं का सर्वेक्षण करने के लिये विदेशी विशेषज्ञों को बुलाने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो वे किन किन देशों से बुलाये जायेंगे ?

†**अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख) जी हां। ब्यौरे बनाये जा रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैथलीटेड स्प्रिट

†*२६०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में मैथीलेटेड स्प्रिट की भारी कमी हो गई है और उसका मूल्य १ रुपया प्रति बोतल से बढ़ कर २ रुपया ५० नये पैसे प्रति बोतल हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) कीमत को कम रखने के लिए प्राधिकारियों द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं, अथवा उठाये जाने का विचार है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). अलकोहल का औद्योगिक कार्यों के लिए उपयोग बढ़ जाने के कारण उत्तर प्रदेश से मैथिलेटेड स्प्रिट का निश्चित संभरण जुलाई १९६३ के अन्तिम भाग में नहीं हुआ था जिस के कारण इन के खुदरा मूल्य बढ़ गये थे। इस बीच उत्तर प्रदेश से इस की मात्रा मिल गई है तथा इस के मूल्य स्थिर हो गये हैं।

(ग) मूल्यों को कम करने के लिए निम्नलिखित कार्यवाही की गई है ।

(१) उत्तर प्रदेश से स्प्रिट का नियमित संभरण करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(२) इसको खुदरा बेचने वालों को स्पष्टतया बता दिया गया है कि इसका विक्रय मूल्य उत्पादन-शुल्क अधिकारियों द्वारा समय समय पर निहित सीमा से अधिक नहीं चाहिए ।

(३) व्यापारियों को भांडार तथा लेखों का उत्पादन शुल्क कर्मचारी करते हैं जिस से कृत्रिम कमी न आ जाये ।

(४) खुदरा व्यापारियों को आदेश दे दिये गये हैं कि वह उपलब्ध भांडार को अपनी दुकानों में स्पष्टतया घोषित करें ।

(५) गैर-सरकारी व्यक्तियों के पास मात्रा की सीमा व खुदरा व्यापारियों के पास स्प्रिट की सीमा बनाई जा रही है ।

पादप–रासायनिक परियोजना

†*२६१. **श्री प्र० चं० बरुआ** :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री वारियर :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री मणियंगाडन :
श्री अ० व० राघवन :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री मुरारका :
श्री कपूर सिंह :
श्री बूटा सिंह :

---

†मूल अंग्रेजी में

¹Phyto-Chemical Project.

श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री मे० क० कुमारन :
श्री प० कुन्हन :
श्री गुलशन :

क्या **उद्योग** मंत्री १९ अप्रैल, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ९४१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेरियामंगलम पादप-रासायनिक परियोजना में अपनाई जाने वाली प्रौद्योगिकीय प्रक्रियाओं के ब्योरों को इस बीच अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या मशीनों के निर्माण और संभरण के लिये किसी ठेके पर हस्ताक्षर किये गये हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) और (ख). जी नहीं । यह विचाराधीन है ।

नैपाल को परिवहन सुविधायें

†*२६२. श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री बसुमतारी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री कजरोलकर :

क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री १९ अप्रैल, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या २०८९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच नेपाल सरकार के इस अनुरोध पर नर्णय कर लिया है कि नेपाल से भारत हो कर माल के आने जाने विशेषतया नेपाल से पाकिस्तान को तथा पाकिस्तान से नेपाल को माल भेजने की अधिक सुविधायें दी जायें और;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

†**अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). हाल ही में भारत आये नेपाली शिष्टमंडल से पूर्ण तया पश्चिय पाकिस्तान सीमा पर राधिकापुर तथा वगहा से भारतीय — नेपाली सीमा तक के स्थानों तक परिवहन सुविधाओं के बारे में बातचीत हुई थी । भारतीय शिष्टमंडल ने दौरा करने वाले शिष्टमंडल को आश्वासन दिया था कि भारत सरकार १९६० की भारत नेपाल व्यापार तथा परिवहन संधि के अधीन परिवहन व्यापार के लिये नेपाल को उपलब्ध सुविधायें तथा आवश्यक व्यवस्था के लिये तैयार है । नेपाली शिष्टमंडल से अनुरोध किया गया था कि अनुमानित व्यापार की मात्रा तथा वैगनों की आवश्यकतायें और पहुंचने के स्थान आदि बतायें जिस से भारत के अधिकारी सुविधाओं के बारे में निश्चय कर सकें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रासायनिक मध्यवर्ती पदार्थ निर्माण परियोजना

†*२६३. **श्री वारियर :**
श्री वासुदेवन नायर :
श्री मा० ना० स्वामी :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'वायर' नामक पश्चिम जर्मनी की सार्थ के सहयोग से चलाई जाने वाली प्रस्तावित रासायनिक मध्यवर्ती पदार्थ निर्माण परियोजना को छोड़ दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी नहीं

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता है।

आर्थिक सहयोग

†*२६४. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री हेम राज :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री अ० व० राघवन :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और यूरोपीय 'समुदाय' द्वारा आपस में आर्थिक सहयोग बढ़ाने के बारे में कोई संयुक्त निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

†**अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) और (ख). जी नहीं। ब्रिटेन तथा यूरोपीय साझा बाजार की वार्ता समाप्त हो जाने के बाद यह बताया गया था कि भारत, पाकिस्तान तथा लंका जैसे राष्ट्रमंडलीय देशों से विस्तृत व्यापार करार करने के प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा। यूरोपीय साझा बजार में हमारे प्रतिनिधि अधिकारियों से इस प्रश्न पर लगातार बातचीत करते रहे हैं। यह बताया गया कि यूरोपीय साझा बाजार के देशों की मंत्री परिषद् ने २९ जुलाई, १९६३ को अपनी बैठक में विचार किया था और उन्होंने आयोग के प्रविधिक अधिकारियों से कहा है कि इस से संबंधित विभिन्न समस्याओं का ब्योरेवार अध्ययन करें। परिषद् इस पर इस कार्य में बाद में सभी निर्णय लेगी।

हिन्दु धार्मिक धर्मस्व आयोग

*२६५. **श्री सरजू पाण्डेय :**
श्री हेम राज :

क्या **विधि मंत्री** २६ अप्रैल, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या १०४९ के उत्तर के संबंध में

†मूल अंग्रेजी में

यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्य सरकारों ने हिन्दू धार्मिक धमस्व आयोग के प्रतिवेदन पर अपनी राय भेज दी है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कोई निर्णय कर लिया है ?

विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन): (क) आसाम, केरल, मध्य प्रदेश और पश्चिमी बंगाल के सिवा सभी राज्य सरकारों ने हिन्दू धर्मस्व आयोग की रिपोर्ट पर अपनी राय भेज दी । मणिपुर, दादरा और नागरहवेली, गोआ और पांडीचेरी, के सिवा और सभी संघराज्य क्षेत्रों के प्रशासकों के उत्तर भी प्राप्त हो गये हैं। जिन राज्य सरकारों ने अभी तक अपनी राय नहीं भेजी है उनको तार द्वारा याद दिलाई गयी है ।

(ख) रिपोर्ट पर अब तक प्राप्त रायों के आधार पर विचार किया गया है किन्तु अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है क्योंकि कुछ राज्य सरकारों की रायों का इन्तजार किया जा रहा है।

मशीन निर्माण का उद्योग

†*२६६. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मशीन निर्माण उद्योग सम्बन्धी भारतीय उत्पादकता दल ने, जिसने हाल में ही रूस तथा चैकोस्लोवाकिया का दौरा किया था, भारत में मशीन निर्माण उद्योग के विकास के बारे में कोई सिफारिशें की हैं ;

(ख) यदि हां तो सिफारिशों की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) जी हां ।

(ख) मशीन निर्माण उद्योग हल को प्रतिवेदन की प्रति १६ अगस्त, १९६३ को सभा-पटल पर रख दी गई थी । दल की सिफारिशों का सारांश प्रतिवेदन के पृष्ठ ३५ से ३७ पर दिया गया है ।

(ग) सरकार ने सिफारिशों पर विचार कर लिया है ।

विदेशों में सप्लाई मिशन

†*२६७. **श्री मुरारका :**
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या आर्थिक और प्रतिरक्षा समन्वय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मास्को तथा ड्यूज़लडोर्फ में दो नये सप्लाई मिशन खोल रही है ;

(ख) यदि हां, तो ये मिशन किन-किन क्षेत्रों के लिए होंगे ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इन नये मिशनों का कार्यक्षेत्र क्या होगा तथा इनका आई० एस० डी०, लन्दन तथा वाशिंगटन स्थित सप्लाई मिशन के कार्यकरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

†**आर्थिक तथा प्रतिरक्षा समन्वय मत्रालय में संभरण मंत्री (श्री हाथी)** : (क) प्रश्न अभी आरंभिक स्थिति में है तथा अब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता ।

केरल में शुद्ध मापक यंत्र बनाने का कारखाना

†*२६८. **श्री प्र० चं० बरुआ** :
श्री प० कुन्हन :
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री विभूति मिश्र :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष मई में भारत तथा रूस के बीच केरल में पालघाट के निकट एक शुद्ध मापक यंत्र बनाने के कारखाने की स्थापना के बारे में एक करार हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो करार की मुख्य शर्तें क्या हैं ; और

(ग) योजनाओं की रूप-रेखा क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : भारत सरकार तथा रूस सरकार में २५, मई १९६३ को एक करार हुआ था जिसके अनुसार रूस सरकार दूसरा शुद्ध मापक यंत्र बनाने के कारखाने की स्थापना के लिए भारत को आर्थिक तथा प्रविधिक सहायता देगा । ९ नवम्बर, १९५७ के भारत रूस करार के अधीन भारत सरकार के दिए गए शेष ऋण में से प्रविधिक सहायता के लिए धन दिया जायेगा ।

दूसरा शुद्ध मापक यंत्र कारखाना केरल में बनाया जायेगा तथा उस में यांत्रिक, गैसिनी तथा प्रचालित यंत्र का निर्माण होगा ।

पाकिस्तानी कपास

†*२६९. **श्री मुरारका** :
श्री रवीन्द्र वर्मा :

क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पाकिस्तानी कपास का आयात करने के लिये बातचीत कर रही है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसकी मात्रा क्या होगी ; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). पाकिस्तान सरकार से नया व्यापार करने के बारे में बातचीत करने के लिए व्यापार प्रतिनिधि मंडल कराची गया है प्रश्न में उल्लिखित मामलों समेत सभी प्रश्नों पर बातचीत होगी ।

नवीन औद्योगिक एकक

†७४३. **श्री कर्णी सिंहजी :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में, विशेषकर बीकानेर , चुरू, और गंगानगर के जिलों में तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित नवीन औद्योगिक एककों के नाम क्या हैं ;

(ख) अब तक कितनी प्रगति की गई है, और

(ग) सरकार ने कुल कितनी राशि मंजूर की है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) तीसरी योजना अवधि में राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्रों और बस्तियों में १८६ नवीन औद्योगिक एकक स्थापित किये गये हैं। एककों के नामों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० १५२८/६३ ।**] औद्योगिक बस्तियों एवं क्षेत्रों के बाहर स्थापित किये गये नवीन औद्योगिक एककों सम्बन्धी सूचना राजस्थान के उद्योग निदेशक द्वारा एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभापटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) १०६ एककों ने उत्पादन आरम्भ किया है ।

(ग) ७२,९९००० रुपये की राशि बस्तियों के निर्माण, औद्योगिक क्षेत्रों के विकास, छोटे पैमाने के उद्योगों को ऋण देने के लिये अनुदानों पर खर्च की गई है। इस में बीकानेर, चुरू और गंगा नगर जिलों में खर्च हुई ८९,७००० रुपये की राशि शामिल है ।

योजना कर्मचारियों का प्रशिक्षण

†७४४. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना कर्मचारियों को बंगकोक में इकेफ की योजना के अन्तर्गत एशियाई आर्थिक विकास एवं योजना संस्था में प्रशिक्षण के लिये भेजे जा रहे हैं ?

(ख) यदि हां, तो इस प्रशिक्षण योजना की विशेष रूप रेखा क्या है ?

(ग) भारत के कितने कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा, और

(घ) प्रशिक्षण का व्यय कौन वहन करेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ग). इंकेफ सचिवालय जनवरी, १९६४ में एशियाई संस्था द्वारा पेश किया गया पहला भूल प्रशिक्षणक्रम आरंभ करने का विचार करता है। १९६४ के प्रशिक्षण क्रम के लिये, तीस प्रशिक्षण स्थान इस संस्था की बजट व्यवस्था के अन्तर्गत होंगे। (भारत समेत) सदस्य सरकारों को कहा गया है कि वे प्रथम बुनियादी प्रशिक्षण क्रम में भाग लेने के लिये संस्था के निदेशक द्वारा चुने जाने के लिये प्रत्येक सरकार छः छात्रों के नाम भेजे। इस संस्था में प्रशिक्षण पाने के लिए भारत से लोगों को चुनने का प्रश्न इस समय विचाराधीन है।

(ख) एशियाई संस्था सदस्यों तथा संबद्ध सदस्य देशों को उन की राष्ट्रीय निकाय योजनाओं को बनाने और कार्यान्वित करने के प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्श देने का काम करेगी।

(घ) प्राविधिक सहायता कार्य का संयुक्त राष्ट्रीय ब्यूरो छात्रवृत्ति काल में वाहन ५२०० (लगभग अमरीकी डालर २५०) की मासिक छात्रवृत्ति देता है। यह बेगाकोक तक जाने तथा लौटने की यात्रा के लिये भी खर्च देता है और प्रशिक्षण कार्यक्रम से सम्बन्ध रखने वाली पुस्तकों को खरीदने के लिये अनदान भी देता है और प्रारंभिक व्यय के लिये भत्ता देता है। छात्रवृत्तियों की शर्त यह है कि सरकारें या अन्य संबद्ध नियोजक अभिकरण प्रशिक्षण की अवधि में जो ९ से १० महीने की होगी छात्रों को वेतन देते रहेंगे।

औद्योगिक सहकारी सस्थायें

†७४५. **श्री रामचन्द्र उलाका** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में इस समय कितनी औद्योगिक सहकारी संस्थायें काम कर रहीं हैं; और

(ख) वे किस प्रकार की संस्थायें हैं और उनकी उत्पादन क्षमता कितनी है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

छोटे पैमाने के उद्योग

†७४६. **श्री रामचन्द्र उलाका**: क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के किसी पैमाने के उद्योग को लघु उद्योग सेवा संस्था से सहायता मिल रही है; और

(ख) यदि हां, तो कितने उद्योगों को और किसी प्रकार की सहायता पिछले तीन वर्षों में अब तक दी गई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी हां। लघु उद्योगों की परिचालन के अन्दर पड़ने वाले सभी उद्योगों को इस संस्था से सहायता प्राप्त करने का हक है।

(ख) १९६०–६१ से १९६२–६३ तक के वर्षों में इस प्रकार सहायता दी गई है ?

(१) विशुद्ध प्राविधिक सलाह २१५२ पक्षों को

(२) नवीन उद्योग आरंभ करने के लिये सूचना ...९५४ पक्षों को

†मूल अंग्रेजी में

(३) प्राविधिक मार्गदर्शन के लिए अधिकारियों का आगमन २८२३

(४) अन्य सहायता ७८३

लघु औद्योगिक एकक

†७४७. **श्री राम चन्द्र उलाका :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१–६२ में उड़ीसा में औद्योगिक विस्तार सेवा से कितने लघु औद्योगिक एककों को लाभ पहुंचा है ?

(ख) उनको उक्त अवधि में कितना ऋण दिया गया; और

(ग) उड़ीसा में छोटे एककों का स्वरूप कैसा है और उनके विकास की गुंजाइश क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :**

		१९६१–६२
(क)	१. फैक्टरी एककों की संख्या .	७०५
	२. जिन पक्षों को प्राविधिक सहायता दी गई	८५४
	३. जिन पक्षों को नवीन उद्योग आरंभ करने के लिए सूचना दी गई	३०३
	४. जिन पक्षों को अन्य सहायता दी गई	१५३

(ख) ३०५३१३ रुपये की राशि ऋण के रूप में राज्य सरकार द्वारा १९६१–६२ में उड़ीसा में उद्योगों को सरकारी सहायता के अन्तर्गत दी गई।

(ग) **एक विवरण संलग्न है [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १५२९–६३]।**

उद्योगों का विकास

†७४८. { **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६२–६३ में उड़ीसा में लघु उद्योगों तथा कुटीर उद्योगों के विकास की कोई योजनायें मंजूर की गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन पर कितना धन खर्च किया गया है या खर्च करने का विचार है और योजनाओं का स्वरूप क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) और (ख). राज्य सरकार द्वारा उड़ीसा में १९६२–६३ में लघु उद्योगों के विकास पर ७६.४९ करोड़ रुपये का अनुमानित व्यय किया गया था। इस के अतिरिक्त ४४.०५ लाख रुपये अन्य राज्य में खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग द्वारा खर्च किये गये थे।

---

†मूल अंग्रेजी में

योजनाओं के नाम

१. हथ करघा

२. दस्तकारी

३. लघु उद्योग

४. औद्योगिक बस्तियां

५. रेशम के कीड़े पालने का उद्योग

६. जटा उद्योग, और

७. खादी और ग्राम उद्योग

औद्योगिक सहकारी संस्थायें

†७४९. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री राम चन्द्र उलाका :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में इस काम की कितनी औद्योगिक सहकारी संस्थाएं हैं; और

(ख) वे किस स्किस्म की हैं और उनकी उत्पादन क्षमता कितनी है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

राजस्थान में छोटे पैमाने के उद्योग

†७५०. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री राम चन्द्र उलाका :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के किन्हीं छोटे पैमाने के उद्योगों को लघु उद्योग सेवा संस्था से सहायता प्राप्त होती है; और

(ख) यदि हां, तो कितने उद्योगों को और किस प्रकार की तथा कितनी सहायता गत तीन वर्षों में प्राप्त हुई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) जी हां । छोटे पैमाने के उद्योगों की परिभाषा में आने वाले सभी एकक इस संस्था से सहायता पाने के हकदार हैं ।

(ख) १९६०–६१ से १९६२–६३ तक दी गई सहायता इस प्रकार है :

(१) विशुद्ध प्राविधिक सलाह . . . ६२२७ पक्ष

(२) नवीन उद्योग आरंभ करने के लिये सूचना. . .४४२५ पक्ष

(३) प्राविधिक मार्ग दर्शन के लिये अफसरों का दौरा ३४२८

(४) अन्य सहायता . . . ३६०२ एकक ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस्पात का आयात

†७५१. श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६२–६३ में इस्पात के आयात के लिये राजस्थान को दी गई विदेशी मुद्रा की अधिकतम सीमा क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : इस काम के लिये राजस्थान के लिये विदेशी मुद्रा की सीमा २६.६४ लाख रुपये थी ।

मैसूर का रेशम उद्योग

७५२. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर रेशम उद्योग संघ ने एक स्मरण-पत्र पेश किया है जिसमें यह मांग की गई है कि इस उद्योग के संरक्षण को और दस वर्ष तक जारी रखा जाये ।

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क). और (ख) मैसूर शिल्क एसोसियेशन ने प्रशुल्क आयोग को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है जिसमें संरक्षण जारी रखने का निवेदन किया गया है । इसका कारण उसने यह बताया है कि भारत में कच्ची रेशम के भाव बहुत ऊंचे होने के कारण यह उद्योग प्रशुल्क में संरक्षण दिये बिना विदेशों से प्रतिद्वंदिता नहीं कर सकता ।

(ग) प्रशुल्क आयोग इस मामले पर विचार कर रहा है ।

नमक

७५३. श्री रामचन्द्र उलाका : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कितना नमक तैयार होता है, और इसकी आवश्यकता कितनी है । और

(ख) उड़ीसा में वार्षिक उत्पादन कितना है और आवश्यकता कितनी है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) क्रमशः लगभग ४० लाख टन और ३७ लाख टन ।

(ख) क्रमशः लगभग ४५,००० टन और १,२३,००० टन ।

विदेशों में कुटीर और लघु उद्योगों के लिये प्रशिक्षण

†७५४. श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में लघु उद्योगों और कुटीर उद्योगों के प्रशिक्षण के लिये राजस्थान से कितने लोग विदेश भेजे गये हैं; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) किन किन देशों को ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

भारत का निर्यात व्यापार

†७५५. { **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री १३ अप्रैल, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १८१९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत की निर्यात व्यापार, सम्बन्धी वे यथार्थ कठिनाइयां जिन पर 'इकाफे' के १९वें सत्र में चर्चा हुई थी क्या क्या हैं ;

(ख) इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये मीटिंग में क्या सिफारिशें की गई हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इन सिफारिशों का परीक्षण किया है ; और

(घ) इस परीक्षण का क्या परिणाम है और इन सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए कठिनाइयों को हल करने के लिये क्या कार्यवाही की जायेगी ?

†**अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) भारत के निर्यात व्यापार के सम्बन्ध में किन्हीं विशिष्ट कठिनाइयों पर 'इकाफे' के १९वें सत्र में कोई विस्तृत चर्चा नहीं हुई ।

(ख) से (घ). उत्पन्न नहीं होते ।

फेरों धातुओं का निर्यात[1]

†७५६. { **श्री वारियर :**
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिका में फैरो धातुओं के निर्यात पर्याप्त में कमी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी ; और

(ग) निर्यात में कमी की इस प्रवृत्ति को रोकने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

†**अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). फैरो धातु का आजकल निर्यात नहीं किया जा रहा है । केवल एक ही फैरो मिश्रित धातु का निर्यात अमेरिका में किया जा रहा है वह है—फैरो मैंगनीज । अमेरिका में फैरो मैंगनीज के १९६०–६१ के लिये आंकड़े इस प्रकार हैं :—

वर्ष	मात्रा मीट्रिक टनों में
१९६०–६१	४७,०००
१९६१–६२	५६,०००
१९६२–६३	८,०००

†मूल अंग्रेजी में

[1]Export of Ferro Metals,

(ग) अदला बदली सौदों के आधार पर अमेरिका में फैरो मैंगनीज का निर्यात बढ़ाया जा रहा है । भारत के राज्य व्यापार निगम अमेरिका के वस्तु ऋण निगम के अदला बदली समझौते के अन्तर्गत १३०,००० मीट्रिक टन फैरो मैंगनीज अमेरिका में निर्यात करने की संभावना है ।

फर्टीलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड का विस्तार

†७५७. **श्री वारियर :**
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर, लिमिटेड के विस्तार कार्यक्रम का तीसरा चरण पूरा हो गया है ; और

(ख) क्या अमोनियम क्लोराइड संयन्त्र में उत्पादन पहले ही प्रारम्भ कर दिया गया है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड के विस्तार कार्यक्रम का तीसरा चरण १९६५-६६ में पूरा होने की आशा है ।

(ख) फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर में अमोनियम क्लोराइड का उत्पादन १९५५ से किया जा रहा है । इसकी वर्तमान उत्पादन क्षमता ८,००० प्रति वर्ष है । विस्तार का तीसरा चरण पूरा होने पर यह बढ़ कर २५,००० टन प्रति वर्ष हो जायेगा ।

लोहे की ढ़ली हुई वस्तुओं का निर्यात

†७५८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी यूरोपीय देशों की ढली हुई वस्तुओं का निर्यात किये जाने की कोई संभावना है ;

(ख) क्या उसके लिये मण्डियों की खोज कर ली गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). इंजीनियरिंग निर्यात संवर्द्धन परिषद के एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने जिसने कि हाल ही में पश्चिमी यूरोप का दौरा किया था यह सूचना दी है कि पश्चिमी यूरोप कुछ इंजीनियरिंग वस्तुओं के लिये अवसर प्रदान करता है जिनमें कि मशीनी औजारों और मशीन बनाने वाले उद्योगों के लिये कोई लोहे तथा इस्पात की ढली हुई वस्तुएं तथा अन्य पुर्जे और हिस्से भी सम्मिलित हैं ।

२. प्रचार के कुछ उपायों की जांच की जा रही है, जैसे कि : पश्चिम यूरोप के व्यापारिक मेलों में भाग लेना ; यूरोपीय व्यापारियों द्वारा भारत के दौरों को प्रोत्साहन देना और भारतीय व्यापारियों द्वारा यूरोपीय देशों के दौरों को प्रोत्साहन देना; और संयुक्त उपक्रमों की स्थापना आदि ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नीरा

†*७५९. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'नीरा' (ताड़ के वृक्षों का मीठा रस) के उत्पादन को बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ; और

(ख) उनके ब्यौरे क्या हैं और इस मामले में कितनी सफलता प्राप्त हुई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). नीरा तथा ताड़-गुड़ के उत्पादन को बढ़ाने की दृष्टि से खादी तथा ग्राम उद्योग आयोग निम्नलिखित प्रयत्न कर रहा है :—

(१) च्यावकों को चुआने के लिये पर्याप्त संख्या में वृक्षों की व्यवस्था करना ;

(२) सुधारे हुए उपकरणों तथा औजारों का प्रयोग प्रारम्भ कराना ; और

(३) वृक्षों को अधिक कुशलतापूर्वक चुआने के लिये सुधरी हुई विधियों को लागू कराना ।

इस ध्येय को दृष्टिगत रखते हुए आयोग ने निम्नलिखित व्यवस्था की है :

(क) च्यावकों को सहकारी संस्थाओं के रूप में संगठित होने के योग्य बनाने के लिये उन्हें ऋण देना ;

(ख) नीरा, ताड़-गुड़ तथा ताड़ वृक्षों के अन्य उत्पादों के उत्पादन तथा विक्रय को करने के हेतु कर्मवाहक पूंजी के लिये सहकारी संस्थाओं को ऋण देना ;

(ग) नीरा तथा ताड़ उत्पादों के उपभोग को लोकप्रिय बनाने के लिये प्रचार यूनिटों की स्थापना करना ;

(घ) अधिक अच्छे औजारों तथा उपकरणों का प्रयोग करने और चुआने के सुधारे हुए ढंगों में केन्द्रीय तथा राज्य प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण देना ;

(ङ) नीरा के परिरक्षण के वैज्ञानिक ढंगों और ताड़ गुड़ तथा अन्य उत्पादों के निर्माण कार्य में भारतीय ताड़ गुड़ शिल्प भवन, दहानू (महाराष्ट्र) तथा अन्य चुने हुए केन्द्रों पर प्रशिक्षण देना ।

२. इसके अतिरिक्त, च्यावकों को पर्याप्त संख्या में वृक्षों की व्यवस्था करने योग्य बनाने के लिये आयोग ने एक समान तथा अधिक सरल उत्पादन शुल्क नीति के प्रश्न की जांच करने के लिये हाल ही में एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की है । राज्य सरकारों से प्रार्थना की गई है कि वे च्यावकों को भाड़े पर वृक्ष दिये जाने के लिये प्रभारों के विनियमन के प्रश्न की जांच करें क्योंकि वृक्षों का भाड़ा नीरा तथा ताड़ वृक्ष के अन्य उत्पादों के उत्पादन की लागत का एक मुख्य अवयव है । राज्य सरकारों से भी यह भी प्रस्ताव किया गया है कि, जहां तक सम्भव हो सके, वे अपने वृक्षों को नीरा के चुआये जाने के लिये च्यावकों की सहकारी संस्थाओं को मामूली भाड़ों पर दें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

३. इन कदमों के परिणामस्वरूप, नीरा का विक्रय १९५३–५४ में हुए ५०.५५ लाख लिटर के विक्रय से बढ़ कर १९६२–६३ में १९९.२० लाख लिटर हो गया है। ताड़ की चीनी और ताड़ की मिश्री जैसे ताड़ के खाद्य उत्पादों और चटाइयां, रेशे वाले ब्रुश आदि जैसे ताड़ के अरवाध उत्पादों का उत्पादन जो कि १९५३–५४ में लगभग नगण्य था १९६२–६३ में बढ़ कर लगभग ४ लाख ३६ हजार रुपयों के मूल्य का हो गया है।

भारतीय दस्तकारी की वस्तुयें

†७६०. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सभी प्रकार की भारतीय दस्तकारी की वस्तुओं की अदन में भारी मांग है ;

(ख) यदि हां, तो उनके निर्यात को बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) मण्डी की मांग के कब पूरे हो जाने की संभावना है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) अदन में भारतीय दस्तकारी की सभी प्रकार की वस्तुओं की मांग है। १९६२–६३ में अदन को १९,१५,८९७ रुपये के मूल्य की दस्तकारी की वस्तुएं निर्यात की गई थीं।

(ख) और (ग). दस्तकारी की वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने की दृष्टि से, अधिक प्रोत्साहनों की व्यवस्था करने के लिए दस्तकारी की वस्तुओं की निर्यात संवर्द्धन योजना हाल ही में पुनरीक्षित की गई है। अखिल भारतीय हथकरघा वस्त्र विपणन सहकारी समिति द्वारा 'स्टीमर पाइन्ट' पर स्थापित किये जाने वाले डिपो के माध्यम से दस्तकारी की वस्तुओं के विक्रय की व्यवस्था करने के लिये एक प्रस्ताव भारतीय दस्तकारी तथा हथकरघा वस्तुयें निर्यात निगम लिमिटेड के विचाराधीन है। तथापि, किस समय तक बाज़ार की पूरी मांग को पूरा करना सम्भव हो सकेगा इसका निश्चित अनुमान बता सकना सम्भव नहीं है।

रेफ्रिजरेटर

†७६१. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में निर्मित रेफ्रिजरेटरों के निर्यात के लिये कोई क्षेत्र है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके बाजार को खोजने के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

†**अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) मुख्यतया उत्पादन की ऊंची लागत और परिणामस्वरूप भारतीय निर्यातकों द्वारा बताई गई अप्रतिस्पर्द्धात्मक कीमतों तथा उपभोक्ताओं द्वारा इसी सुविख्यात विदेशी किस्मों को अधिक अच्छा समझा जाने के कारण, भारतीय रेफ्रिजरेटरों के निर्यात का क्षेत्र सीमित है।

(ख) तदपि, विदेशों में इनकी मंडियों की खोज करने के लिये भारतीय निर्माण-कर्ताओं द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं। हमारे रेफ्रिजरेटरों की प्रतिस्पर्द्धात्मक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिये, रियायती मूल्यों पर लोहे तथा इस्पात की स्वदेशी वस्तुओं के आवंटन के अतिरिक्त, निर्यातकों को उनके निर्यातों, के बदले में उन कच्चे मालों तथा पुर्जों आदि को जो कि स्वदेश में उपलब्ध नहीं हैं आयात करने की अनुमति दे

†मूल अंग्रेजी में

दी गई है । उनकी वस्तुओं को विदेशी प्रदर्शिनियों, मेलों तथा प्रदर्शन-कक्षों में दिखाये जाने में और उनका विदेश में प्रचार करने में भी निर्यातकों की सहायता की जाती है ।

दुर्गापुर इस्पात सयंत्र

†७६२. **श्री सुबोध हसंदा :** क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्गापुर इस्पात परियोजना में जो अस्थायी कर्मचारी पिछले ३ अथवा ४ वर्षों से कार्य कर रहे हैं क्या उनकी सेवाओं को विनियमित करने की सरकार की कोई योजना है ;

(ख) यदि नहीं, तो उन्हें किस प्रकार के लाभ प्रदान किये जायेंगे ; और

(ग) क्या यह सच है कि कर्मचारियों ने इसलिये कुछ समय के लिये पड़ताल की थी क्योंकि उनकी सेवाओं को मान्यता नहीं दी गई थी ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) :** (क) मशीनों को चलाने के कार्य में, जो कार्य आवश्यक रूप से अस्थायी रूप का होता है अथवा स्थायी कार्य में जो अस्थायी वृद्धि होती है केवल उसी के लियें अस्थायी आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है । स्थायी कार्य में अस्थायी वृद्धि के सम्बन्ध में जो व्यक्ति एक अथवा अधिक पदों पर १२ महीने की निरन्तर सेवा पूरी कर लेते हैं उन्हें स्थायी कर्मचारियों के रूप में मान लिया जाता है । तथापि, निर्माण पक्ष में अस्थायी कर्मचारियों को, विशेष रूप से दैनिक मजदूरी पर रखे जाने वाले संनामावलि वाले कर्मचारियों, को, स्पष्ट कारणों से ही स्थायी रोजगार नहीं दिया जा सकता । जहां तक सम्भव है उन्हें नियमित पदों पर खपाने के सम्बन्ध में विचार किया जाता है ।

(ख) छंटनी किये गये कर्मचारियों को विधि के अधीन अनुमन्य लाभ दिये जाते हैं।

(ग) जी, नहीं ।

पश्चिम बंगाल के लिये सीमेंट

†७६३. **श्री सुबोध हसंदा :** क्या **इस्पात और भारी** उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल के लिये सीमेंट के अपेक्षित अभ्यंश की मंजूरी नहीं दी गई थी जिसके कारण उस राज्य में सीमेंट की भारी कमी हो गई ; और

(ख) क्या अब पश्चिम बंगाल के लिये अधिक सीमेंट मंजूर करने का सरकार का विचार है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :** (क) राष्ट्रीय आपात के कारण सीमेंट की अधिक बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये राज्यों तथा केन्द्रीय प्राधिकारों के सीमेंट के सामान्य त्रैमासिक आवंटनों में सरकार को कटौती

†मूल अंग्रजी में

करनी पड़ी। राज्य अभ्यंश के अधीन १,३४,४०० टन सीमेंट के सामान्य त्रैमासिक आवंटन के विरुद्ध पश्चिम बंगाल सरकार को निम्नलिखित आवंटन किया गया था :

अवधि	मात्रा (मैट्रिक टनों में)
जनवरी-मार्च, १९६३	१,००,८००
अप्रैल-जून, १९६३	१,१४,२४०
जुलाई-सितम्बर, १९६३	१,२०,९००

(ख) सीमेंट के उत्पादन में भारी वृद्धि के बिना राज्य के अभ्यंश में वृद्धि करना कठिन है ।

रेल की पटरियों का निर्यात

†७६४. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सूडान को रेल की पटरियों का निर्यात कर रहा है, विशेष रूप से उनका जो कि भिलाई इस्पात संयंत्र में बनाई गई है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)**: सूडान को १२५०० टन रेल की पटरियों का निर्यात करने के लिये एक प्रस्ताव हिन्दुस्तान स्टील्स द्वारा स्वीकृत कर लिया गया है। रेल की पटरियां भिलाई इस्पात संयंत्र में बनाई जायेंगी।

कुटीर उद्योग

७६५. **श्री बाल्मीकी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, १९५८ से जुलाई, १९६३ के अन्तिम सप्ताह तक कुटीर उद्योगों के लिये राज्यों को कितना ऋण दिया गया ;

(ख) किस राज्य को सब से अधिक ऋण दिया गया ; और

(ग) किस कुटीर उद्योग के लिये सब से अधिक ऋण दिया गया।

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) से (ग). मांगी गई जानकारी इकट्ठी करने में आवश्यकता से अधिक समय और श्रम लगेगा।

बोंनाकालू, आन्ध्र प्रदेश में सीमेंट का कारखाना

†७६६. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोनाकालू, जिला खम्माम, आंध्र प्रदेश में एक सीमेंट का कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव किस प्रक्रम पर है ;

(ख) इस कारखाने को चूना पत्थर का सम्भरण किन किन क्षेत्रों से किया जायेगा ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या लाइसेंस दे दिया गया है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) एक आशय पत्र आंध्र प्रदेश खनन निगम लिमिटेड, हैदराबाद, को दे दिया गया है जिसमें बौंकाली के निकट २,००,००० टन की वार्षिक क्षमता वाले एक सीमेंट के कारखाने को स्थापित करने की उनकी योजना स्वीकार कर ली गई है ।

(ख) प्रस्तावित कारखाने के लिये चूना पत्थर कृष्णा जिले के जग्गय्यापेट नामक स्थान से लिया जायेगा ।

(ग) जी, नहीं । निगम द्वारा अपेक्षित संयत्र और उपकरणों की संतोषजनक व्यवस्था किये जाने के पश्चात् एक औपचारिक लाइसेंस उन्हें दिया जायेगा ।

प्राग टूल्स कारपोरेशन

†७६७. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राग टूल्स कारपोरेशन लिमिटेड में खराद टेक परियोजना के लिये अपेक्षित संयंत्र और मशीनों के लिये क्रयादेश भेज दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनके कब प्राप्त होने की सम्भावना है ;

(ग) क्या हल्के और मध्यम प्रकार के पोलैंड की तरह के मशीनी औजारों का निर्माण करने के हेतु कम्पनी द्वारा एक नया यूनिट स्थापित करने के लिये विस्तृत परियोजना की जांच पूरी हो गई है ; और

(घ) यदि हां, तो किस प्रकार का निर्णय लिया गया है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) और (ख). श्रीमन्, अभी तक नहीं । दिसम्बर, १९६२ में प्राग टूल्स कारपोरेशन लिमिटेड ने अपने प्रविधिक सहयोगी मैसर्स एफ० प्राट्ट एण्ड कम्पनी, इंग्लैंड से खराद के टेकों के निर्माण के लिये अपेक्षित मशीनों के क्रयादेश भेजने की प्रार्थना की थी। इंग्लैंड की फर्म ने कुछ स्पष्टीकरण मांगे थे जो कि अब दे दिये गये हैं। आशा है कि मशीनों के लिये क्रयादेश शीघ्र ही भेज दिये जायेंगे ।

(ग) और (घ). यह निर्णय किया गया है कि जब तक प्राग टूल्स कारपोरेशन लिमिटेड की उनकी वर्तमान विस्तार योजनायें पूरी न हो जायें, तब तक उन्हें मशीनी औजारों के और किन्हीं भी मदों के निर्माण का कार्य न सौंपा जाय ।

औषधि-निर्माण संयंत्र

†७६८. **श्री भक्त दर्शन** :
डा० महादेव प्रसाद :

क्या **उद्योग** मंत्री २३ नवम्बर, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७९६ के उत्तर के

†मूल अंग्रेजी में

सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सोवियत रूस की सहायता से जो चार औषधि-निर्माण संयंत्र स्थापित किये जा रहे हैं उनमें से प्रत्येक के बारे में और क्या प्रगति हुई है ;

(ख) इन संयंत्रों के लिये सोवियत रूस से अब तक कितनी सहायता मिल चुकी है ; और

(ग) प्रत्येक संयंत्र के लिये आवश्यक इंजीनियरों, कारीगरों व अन्य कर्मचारियों की भर्ती व ट्रेनिंग के लिये कैसी व्यवस्था की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) एन्टीबायोटिक्स प्रयोजना, ऋषिकेश सिंथेटिक ड्रग्स प्रायोजना हैदराबाद और सर्जीकल इन्स्ट्रूमेन्ट्स प्रायोजना, मद्रास के संयंत्रों के कुछ महत्वपूर्ण खण्डों का निर्माण आरम्भ हो चुका है। सोवियत रूस से भी मशीनों की खेपें आनी शुरू हो गई हैं और भारत में उपलब्ध होने वाले उपकरणों के लिये भी आर्डर दिये जा रहे हैं । संयंत्र नरियमंगलम् के फाइटो-केमिकल के संयंत्र के बारे में स्थिति यह है कि इसका मामला अभी और विचाराधीन है ।

(ख) मे० टेक्नोएक्सपोर्ट, मास्को से अब तक मिली प्रविधिक सहायता का मूल्य लगभग ३.५ करोड़ रुपये है जिसमें प्रायोजना रिपोर्टें, कार्यकारी ड्राइंग्स तथा उपकरणों के आयात का मूल्य भी शामिल है ।

(ग) इन कारखानों के लिये महत्वपूर्ण प्रविधिक कर्मचारियों के प्रशिक्षण की योजना मे० टेक्नोएक्सपोर्ट के परामर्श से तैयार कर ली गई है । ये कर्मचारी तीन समूहों में जाकर सोवियत रूस में प्रशिक्षण लेंगे जिनमें से दो समूह पहले ही रूस को जा चुके हैं । इन प्रशिक्षणार्थियों का चुनाव एक अखिल भारतीय आधार पर विज्ञापन करके दिया जाता है ।

इन कारखानों के लिये आवश्यक अन्य प्रविधिक कर्मचारियों की भर्ती तथा प्रशिक्षण के ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं ।

नमक विशेज्ञों का फ्रांस का दौरा

†७६९. **श्री पें० वेंकटासुब्बया** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नमक विशेषज्ञों के एक दल को फ्रांस भेजने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो दौरे का उद्देश्य क्या है ; और

(ग) यदि दल के गठन को अन्तिम रूप दे दिया गया है तो वह क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ग). नमक के संग्रह, परिशोधन, उठाने-रखने और परिवहन की फ्रांस में नवीनतम प्रविधियों का, वहीं जा कर मौके पर, अध्ययन करने की दृष्टि से, जिससे कि उन्हें स्वदेशी उद्योग में लाभपूर्वक लागू किया जा सके, नमक तथा सहयोगी उद्योगों के प्रतिनिधियों के एक अध्ययन दल को भेजने का प्रश्न विचाराधीन

†मूल अंग्रेजी में

है । प्रतिनिधिमण्डल को भेजने अथवा इसके गठन के सिद्धान्त के सम्बन्ध में अभी तक कोई भी निर्णय नहीं किया गया है ।

केरल के हथकरघा बुनकर

†७७०. **श्री कोया :** क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रंगों, रसायन के पदार्थों और सूत के बढ़े हुए मूल्यों के सम्बन्ध में केरल के हथकरघा बुनकरों से कोई अभ्यावेदन सरकार को प्राप्त हुआ है ; और

(ख) उक्त वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

†**अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) और (ख). इस विषय पर मैसर्स कालीकट हैंडलूम फैक्टरी आनर्स एसोसिएशन से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ।

२. इस समय स्वदेश में बने रंगों और रसायन के पदार्थों के वितरण अथवा मूल्यों पर कोई नियंत्रण नहीं है परन्तु हथकरघा निर्माणकर्ता अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को सीधे ही रंगों तथा रसायन के पदार्थों के स्वदेशी निर्माणकर्ताओं से उचित मूल्यों पर ले सकते हैं। स्वदेशी स्रोतों से सम्भरण की व्यवस्था करने की दृष्टि से, अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड, बम्बई ने केरल राज्य के हथकरघा बुनकरों की रंगों और रसायन के पदार्थों की समेकित मांगों को भेजने के लिये हथकरघा निदेशक, केरल से प्रार्थना भी की है । निर्यात संवर्द्धन योजना के अधीन हथकरघा वस्त्रों के निर्यात के बदले में रंगों और रसायन के पदार्थों को आयात किये जाने की भी अनुमति है । जहां तक कपास के सूत का सम्बन्ध है, स्वैच्छिक मूल्य नियंत्रण योजना के अधीन सूत की सभी किस्मों के मूल्य निर्धारित कर दिये गये हैं ।

हथकरघा कारखानों के सूत के क्रय के लिये अर्थसहायता देना

†७७१. **श्री कोया :** क्या **अंतर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथकरघा कारखानों द्वारा किये जाने वाले सूत के क्रय के लिये अनुपाततः अर्थसहायता देने के लिये अथवा विक्रय पर छूट देने की अनुमति दिये जाने के लिये सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय लिया गया है ?

†**अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) और (ख). इस विषय पर मैसर्स कालीकट हैंडलूम फैक्टरी आनर्स एसोसिएशन से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है । भारत सरकार की नीति सहकारी क्षेत्र में हथकरघा उद्योग का विकास करने की है । यह एसोसिएशन सहकारी क्षेत्र में नहीं है अतः इसे भारत सरकार से कोई भी वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं होती । राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे उन बुनकरों तथा निर्यातकों को जो कि सहकारी क्षेत्र से बाहर हैं मान्यताप्राप्त संस्थाओं के रूप में संगठित करने के लिये कदम उठायें जिससे कि उनके लिये सूत के सम्भरण की व्यवस्था की जा सके ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खरादों का निर्यात

७७२. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री १३ अप्रैल, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ८३९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम जर्मनी और स्विटजरलैण्ड तथा नेपाल के अतिरिक्त एशिया के किन किन देशों को गत तीन महीनों में खराद मशीनों का निर्यात किया गया और उनसे कितनी स्वदेशी मुद्रा की आय हुई ?

इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : नेपाल के अतिरिक्त एशिया के किसी अन्य देश को हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड द्वारा खरादों या अन्य मशीनों का निर्यात नहीं किया गया है ।

विदेशों में मरम्मत केन्द्र

†७७३. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री २६ अप्रैल, १९६३ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या १०६४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन देशों में जहां कि सिलाई मशीनों और पंखों जैसी हमारी मशीनों का नियमित रूप से तथा बड़ी मात्रा में निर्यात किया जाता है मरम्मत केन्द्रों के खोलने के लिये कोई कसौटी निर्धारित की गई है ; और

(ख) अब तक कितने सेवा केन्द्र खोल दिये गये हैं ?

†**अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) भारतीय सार्थों द्वारा विदेशों में मरम्मत केन्द्रों के खोले जाने के लिये सरकार ने कोई कसौटी निर्धारित नहीं की है । प्रत्येक मामले के गुण दोषों के आधार पर, भारत का रक्षित बैंक विदेशों में ऐसे केन्द्रों को खोलने के लिये अथवा विक्रय-उपरान्त मरम्मत के लिये उनके अभिकर्ताओं की नियुक्ति के लिये भारतीय सार्थों को उदारतापूर्वक विदेशी मुद्रा देता है ।

(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

सीमेंट

†७७४. **श्रीमती सावित्री निगम :** क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत छः महीनों में सीमेंट की कमी और अपमिश्रण के सम्बन्ध में सरकार को कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :** देश में सीमेंट की सभी जगहों पर कमी है और राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि प्रत्येक मांग की सापेक्षिक आवश्यकता तथा पूर्ववर्हिता के आधार पर वे उपलब्ध सीमेंट की मात्राओं का वितरण करें । सीमेंट के अपमिश्रण के सम्बन्ध में अभी तक राज्य सरकारों को चार

---

†मूल अंग्रेजी में

शिकायतें प्राप्त हुई हैं । एक शिकायत सच्ची प्रमाणित नहीं हुई और शेष शिकायतों में जांचें तथा कार्यवाहियां प्रारम्भ कर दी गई हैं ।

संविधान सभा के प्रलेख

†७७५. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार संविधान सभा के महत्वपूर्ण प्रलेखों के प्रकाशन पर और/या भारत के संविधान की रचना के प्रमाणित इतिहास निकालने की किसी योजना पर विचार कर रही है ?

†**विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र)** : सरकार के विचाराधीन ऐसी कोई योजना नहीं है । फिर भी, सरकार को विदित है कि भारतीय लोक प्रशासन संस्था ने भारत के संविधान का प्रामाणिक इतिहास प्रकाशित करने का कार्य आरम्भ किया है और उन्होंने इस मामले में कुछ प्रगति की है ।

कम्पनियां

७७६. **श्री विश्वनाथ पाण्डे :**
श्री कोल्ला वेंकैया :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ अप्रैल, १९६२ से ३१ मार्च, १९६३ तक भारत में कितनी कम्पनियों की रजिस्ट्री हुई, और

(ख) ये कम्पनियां किन-किन राज्यों में बनी हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) १ अप्रैल, १९६२ से ३१ मार्च, १९६३ तक भारत में १४९७ कम्पनियों की रजिस्ट्री की गई थी।

(ख) वित्तीय वर्ष १९६२–६३ में राज्यवार रजिस्ट्री की गई कम्पनियों की संख्या बताने वाला एक विवरण साथ में नत्थी है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १५३०/६३]** ।

वकीलों की फीस

†७७७. **श्री मुरारका :**
श्री रवीन्द्र वर्मा :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन के मंत्रालय में वर्ष १९६०, १९६१ और १९६२ में कुल कितना धन वकीलों की फीस के रूप में दिया ; और

(ख) क्या वकीलों की संख्या तथा उन्हें दी गई फीस दर्शाने वाला एक विवरण पटल पर रखा जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र)** : (क)

		रु०	योग रु०
१९६०–६१	वकील की फीस .	४४,९८.००	
	वकील रखने की फीस .	१,५६,०००.००	१,६०,४९८.००
१९६१–६२	वकील की फीस . .	३,४०२.८७	
	वकील रखने की फीस .	१,५६,०००.००	१,५९,४०२.८७
१९६२–६३	वकील की फीस .	११,१३५.००	
	वकील रखने की फीस .	१,६१,४००.००	१,७२,५३५.००

(ख) विवरण संलग्न है [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० १५३१/६३**]

चाय निर्माण विधि

†७७८. **श्री प्र० के० देव :**
श्री बूटा सिंह :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन में अरबी शायर की एक फर्म ने हाल में चाय निर्माण विधि की अनेक अवस्थाओं में चाय में पानी की मात्रा का पता लगाने के लिए नमी परीक्षण उपाय निकाला है ;

(ख) क्या हमारे चाय के कारखानों में चाय के निर्माण में ऐसा ही उपाय प्रयोग होता है; और

(ग) क्या प्राचीन उपाय नये उपाय से भिन्न है और यदि हां, तो नये उपाय में क्या सुधार है ?

†**अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) प्रेस में ऐसा एक समाचार छपा था ।

(ख) जी हां ।

(ग) आजकल चाय के बागों में प्रयोग हो रहे नमी-मीटर प्रणाली नवीनतम हैं और उनसे आवश्यकता की सन्तोषजनक पूर्ति होती है । नये उपाय तथा निर्माता के दावे के बारे में अब तक प्राप्त हुए समाचारों की जांच फील्ड में होगी । नये मीटर और भारत में प्रयोग होने वाले विद्यमान उपायों में कोई मूल भेद नहीं है ।

निर्वाचन याचिकायें

†७७९. **श्री हेम राज :**
श्री श्रीनारायण दास :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामान्य निर्वाचन तथा उसके बाद संसद् और विधान सभाओं के उप-चुनावों के बाद राज्यवार कुल कितनी निर्वाचन-याचिकायें पेश की गईं और अब तक राज्यवार कितनी याचिकाओं पर निर्णय हो गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) अन्तिम निश्चयों का निर्वाचन न्यायाधिकरणों के अन्तरिम आदेश के विरुद्ध कितनी अपीलें विभिन्न उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में पेश की गईं ; और

(ग) संबंधित प्राधिकारों ने ऐसी कितनी अपीलों पर निर्णय दे दिया है ?

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)**: (क) से (ग). जानकारी देने वाले दो विवरण पटल पर रखे जाते हैं। [**पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी०—१५३२/६३**]

वनस्पति घी

७८०. श्री नवल प्रभाकर : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में वनस्पति घी के भाव मई, १९६३ में असाधारण रूप से बढ़ गये ; और

(ख) यदि हां, तो इस भाव-वृद्धि को रोकने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) दिल्ली में वनस्पति घी के भाव मार्च–अप्रैल, १९६३ की तुलना में मई, १९६३ में कुछ बढ़ गये ।

(ख) सरकार भावों के रुख पर निगाह रख रही है तथा यदि और जब आवश्यकता होगी, आवश्यक कार्यवाई करेगी।

कपड़े की मशीन का कारखाना

†**७८१. श्री रा० बरुआ** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का इन्दौर में गैर-सरकारी क्षेत्र में कपड़े की मशीन का एक कारखाना खोलने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर कितना व्यय होने का अनुमान है ;

(ग) आजकल ऐसी मशीन का कितना अभाव है ; और

(घ) इसकी कितनी पूर्ति देश में उत्पादन से हो रही है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत एक लाइसेन्स एक गैर-सरकारी फर्म को इन्दौर में निम्नलिखित वस्तुओं के निर्माण के लिए एक कारखाना खोलने के लिए दिया गया है :—

(१) ड्राइंग फ्रेम	१०० संख्या प्रति वर्ष
(२) स्पीड फ्रेम . . .	१५० संख्या प्रति वर्ष
(३) रिंग फ्रेम	६०० संख्या प्रति वर्ष
(४) तेज गतिवाली वाइंडिंग मशीन . .	५० संख्या प्रति वर्ष
(५) एक तकुआ पिरन वाइंडर . . .	५० संख्या प्रति वर्ष

(ख) परियोजना की पूंजी लागत की अभी गणना नहीं की गई है ।

†मूल अंग्रेजी में

(ग) और (घ). कपड़े की मशीनों के लागत उत्पादन का तीसरी योजना का लक्ष्य २० करोड़ रु० वार्षिक है । इसके मुकाबले में वर्तमान उत्पादन १४.५ करोड़ रू० का होता है । लगभग २० करोड़ रु० के मूल्य की कपड़े की मशीने आयात की जा रही हैं।

सीमेंट का उत्पादन

†७८२. **श्री रा० बरुआ :** क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सतना और कीमोर में सीमेंट कारखानों का उत्पादन बढ़ाने की विकास योजनायें स्वीकृत हो गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो कब लागू होंगी ; और

(ग) आजकल सीमेंट का वार्षिक उत्पादन कितना है और विस्तार के बाद कितना हो जायेगा?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :** (क) जी, हां ।

(ख) कीमोर—सफेद सीमेंन्ट के उत्पादन की विस्तार योजना अगस्त, १९६४,

पोर्टलैण्ड सीमेंट के उत्पादन की विस्तार योजना मार्च, १९६६

सतना विस्तार योजना . . . . दिसम्बर, १९६३;

(ग) कीमोर सीमेंट कारखाने की विद्यमान अधिकाधिक क्षमता लगभग ५८२,००० मीट्रक टन प्रति वर्ष है और सतना सीमेंट कारखाने की लगभग २५१,००० मीट्रक टन वार्षिक है । कीमोर में विस्तार योजनायें लगभग २५,००० सफेद मीट्रक टन प्रति वर्ष उत्पादन के लिए है और लगभग १८०,००० मीट्रक टन पोर्टलैंड सीमेंट प्रतिवर्ष उत्पादन के लिये है । सतना में विस्तार योजना की क्षमता ३३०,००० मीट्रक टन प्रति वर्ष होगी ।

आपातकालीन उत्पादन समिति

†७८३. **श्री गो० महन्ती** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूरकेला इस्पात संयंत्र के प्रबन्धक वर्ग ने एक आपातकालीन उत्पादन समिति बनाने का निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार समिति के उद्देश्यों तथा प्रयोजनों, उसकी शक्तियों और जिम्मेदारियों का ब्यौरा देने वाला एक विवरण पटल पर रखेगी ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) जी हां । रूरकेला में एक आपातकालीन उत्पादन समिति पहिले ही बनाई जा चुकी है ।

(ख) आपातकालीन उत्पादन समिति वर्तमान आपात काल में संयंत्र में उत्पादन से सीधे सम्बन्धित मामलों पर कार्यवाही करेगी और जनरल सुपरिन्टेण्डेन्ट तथा जनरल मैनेजर से निम्न उपायों द्वारा उत्पादन बढ़ाने की सिफारिश करेगी :—

(१) इतिवार और छुट्टियों में जब भी संभव हो अतिरिक्त समय काम करके ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) जहां संभव हो वहां काम की अनेक पारी चला कर ;

(३) आयुक्त क्षमता का पूर्ण प्रयोग करके ;

(४) निम्न बातों से अधि उत्पादिता करना —

(१) ढगों में सुधार करके

(२) मशीनों को ठीक रख के,

(३) सामग्री का कुशल प्रयोग करके तथा बरबादी समाप्त करके,

(४) संरक्षण सावधानियों तथा उपायों का कुशल प्रयोग करके, आदि।

(५) उत्पादन के निश्चित लक्ष्य निर्धारित करके और समय पर या यदि संभव हो तो समय से पहिले उन्हें प्राप्त करके ;

(६) लागत कम करके; और

(७) गैरहाजरी तथा 'टर्न आवर' में कमी करके।

केरल में छोटे पैमाने के उद्योग

†७८४. **श्री इम्बीचिबावा :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी योजना के पहिले दो वर्षों में केरल में छोटे उद्योगों का विकास करने के लिए राज्य को कितनी वित्तीय सहायता दी गई ; और

(ख) इस काल में कितना धन व्यय हुआ ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) और (ख). केरल सरकार ने तीसरी योजना के पहिले दो वर्षों में छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास पर निम्नांकित कुल व्यय किया :—

अनुदान	.	२५.३३ लाख रु०
ऋण	.	४३.०३ लाख रु०

इस राशि में से १९६१–६२ के लिये केन्द्रीय सहायता के लिए केरल सरकार की पात्रता क्रमानुसार १५.६० लाख और १०.७२ लाख रु० के ऋण व अनुदान की थी। १९६२–६३ में, केरल सरकार को १३.१० लाख रु० और ९.४६ लाख रु० का क्रमानुसार केन्द्रीय ऋण और अनुदान दे दिया गया है। इन आंकड़ों का अंतिम समायोजन बाद में होगा और उसका आधार १९६२–६३ के विस्तृत आकड़े होंगे।

रबड़ बागान

†७८५. **श्री वारियर :**
श्री वासुदेवन् नायर :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री ३ मई, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ११७५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में रबड़ के बाग लगाने के लिए सरकार ने जो कार्यवाही की है क्या उसके परिणाम स्वरूप अब तक रबड़ का उत्पादन बढ़ा है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो कितना बढ़ा है; और

(ग) केन्द्र ने अब तक इस संबंध में कितना व्यय किया है :

†**अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां ।

(ख) उत्पादन १९६०–६१ में २५,६९७ मीट्रिक टन से बढ़ कर १९६२–६३ में ३२,२३९ मीट्रिक टन हो गया, अर्थात् २६ प्रतिशत वृद्धि हुई है ।

(ग) १,०२,२७,११५ रु० जिनमें केरल सरकार को रबड़ पौदा लगाना निगम के लिए दिये गये ३१,३९,००० रु० भी शामिल है ?

दस्तकारी की वस्तुयें

†७८६. **श्री वासुदेवन् नायर :**
श्री वारियर :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड ने भारत के विभिन्न राज्यों के बीच दस्तकारी की वस्तुओं के पारस्परिक विनिमय की कोई योजना पेश की है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड ने १९५५ में दस्तकारी की वस्तुओं के अन्तर्राज्यीय व्यापार की एक नमूना योजना तैयार की थी और विभिन्न राज्य सरकारों तथा प्रदर्शन गृहों से उसे लागू करने की सिफारिश की थी ।

(ख) योजना की एक प्रति संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल०टी० १५३३/६३]**

मेवा

†७८७. **श्री हेम राज** : क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने अफगानिस्तान से आने वाली मेवा के लिए खन्ना देना बन्द कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ग) क्या यह भी सच है कि मेवों का मूल्य एकदम बढ़ गया है ?

†**अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां ।

(ख) अफगानिस्तान से आने वाले मेवों के लिए रवन्ना देना बन्द कर दिया गया है क्योंकि आयात भारत-अफगानिस्तान व्यापार करार में निर्धारित उच्चतम मात्रा से अधिक हो गया है ।

(ग) जी नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

फूलों का निर्यात

†७८८. {श्री हेम राज :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फूलों के निर्यात से विदेशी मुद्रा प्राप्त करने की सभावनाओं की जांच पड़ताल कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त की जा सकती है और किस फूल से प्राप्त की जा सकती है ?

†**अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) विदेशों में भारतीय फूलों की मांग अभी इतनी अधिक नहीं है कि सरकार विदेशी मुद्रा अर्जन की संभावनाओं की जांच करे।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भेषजों के पेटेन्ट

†७८९. {श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भेषजों तथा शोधित खाद्यों के लिये पेटेन्ट के नमूने की जांच करने के लिये एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो समिति के निष्कर्ष क्या हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख) पेटन्ट सम्बन्धी समूचे विधान के पुनरीक्षण पर सरकार सक्रिय ढंग से विचार कर रही है और हाल में मंत्रिमण्डल समिति ने इस मामले की जांच की थी। मैं शीघ्र ही विद्यमान पेटन्ट अधिनियम को स्थानापन्न करने वाला विधेयक सभा में उपस्थापित करूंगा।

जापान को लौह अयस्क का निर्यात

†७९०. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यपार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम १९६०, १९६१, १९६२ और १९६३ (जून १०६३ तक) में जापान को कितना लोह अयस्क बेचने तथा निर्यात करने का करार हुआ है और प्रतिवर्ष लोह-अयस्क किस दर पर बेचा गया ; और

(ख) प्रतिवर्ष कितनी मात्रा भेजी गई और उनकी दर क्या थी ?

†**अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख) जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १५३४/६३]**

†मूल अंग्रेजी में

वस्त्र लाइसेन्स आदेश

†७९१. **श्री श्याम लाल सर्राफ :**
श्री सिद्धनंजप्पा :

क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में कपड़े के फुटकर व्यापारियो ने वस्त्र लाइसेन्स आदेश को रद्द करने की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनकी मांग पर विचार किया है और उस पर कोई निश्चय किया है ?

†**अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां ।

(ख) मामला सरकार के विचाराधीन है ।

भोपाल टेक्स्टाइल मिल्स

†७९२. **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह** : क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भोपाल टैक्स्टाइल मिल्स, भोपाल के मालिकों और मजदूरों के सम्बन्ध कुछ समय से अच्छे नहीं रहे हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि मध्य प्रदेश सरकार ने हाल में इसके बारे में केन्द्र को लिखा था और इस के बारे में सलाह मांगी थी; और

(ग) यदि हां, तो आज मिल की क्या स्थिति है ?

†**अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग) भोपाल टेक्सस्टाइल मिल्स के असन्तोषजनक रूप में चलने के बारे में एक राज्य सरकार से प्राप्त हुई रिपोर्ट के फलस्वरूप केन्द्रीय सरकार ने जुलाई १९६३ में उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ की धारा १५ के अन्तर्गत एक जांच पड़ताल समिति नियुक्त की है । समिति ने अभी रिपोर्ट नहीं दी है ?

ढलवां लोहा

७९३. **श्री ओंकारलाल बेरवा :**
श्री हेमराज :
श्री दलजीत सिंह :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जालंधर तथा अन्य नगरों में ढलवां लोहा न मिलने से कई कारखाने बन्द हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो ढलवां लोहा न मिलने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) सरकार को इस बात की जानकारी है कि न केवल पंजाब बल्कि दूसरे राज्यों में भी पिघलाईघरों के लिए फोंडरी ग्रेड कच्चे लोहे की कमी है। पंजाब में स्थित फौंडरियों से कच्चे लोहे की कमी के बारे में तथा उसके फलस्वरूप निबन्धित उत्पादन की शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं। इस कमी के कारण उक्त राज्य में फौंडरियों के बन्द होने के बारे में कोई निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं है। कच्चे लोहे की सीमित उपलब्धि के कारण राज्य की अधिकतम सीमा के अन्तर्गत प्रत्येक फौंडरी की कच्चे लोहे की सीमा निर्धारित कर दी गई है। १९६३–६४ में प्रत्येक फौंडरी को उसकी निर्धारित मात्रा के अनुसार कच्चा लोहा दिया जायगा।

१९६२ में पंजाब में स्थित केन्द्रीय और राज्य सूची में सम्मिलित फौंडरियों को वर्तमान और अवशिष्ट आर्डरों के प्रति ६२,८११ मीटरी टन कच्चा लोहा सप्लाई किया गया। १९६३ की सप्लाई निम्न प्रकार थी :

	मीटरी टन
जनवरी, १९६३	४,६१७
फरवरी, १९६३	५,७४२
मार्च, १९६३	५,२४०
अप्रैल, १९६३	६,४१८
मई, १९६३	६५,४३
जून, १९६३	३,१८३
	३१,७४३

सरकार कच्चे लोहे की और अधिक क्षमता उत्पन्न करने और यहां तक कि कुछ कच्चा लोहा आयात करने के लिए कार्यवाही कर रही है लेकिन स्पष्ट है कि इन उपायों का कुछ समय के पश्चात् ही परिणाम निकलेगा।

विदेशी शराब

७९४. श्री ओंकारलाल बेरवा : क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने विदेशी शराब के आयात की अनुमति दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) १९६२ में कितनी विदेशी शराब मंगाई गई ?

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) (क) जी, हां।

(ख) भारत में विदेशी राष्ट्रिकों तथा पर्यटकों की आवश्यकता पूरी करने के लिए।

(ग) ४४७,००० लीटर।

चावल की भूसी का निर्यात

†**७९५. श्री पें० वेंकटासुब्बया** : क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक देशों में चावल की भूसी की बड़ी मांग है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस पण्य वस्तु का निर्यात व्यापार बढ़ाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) आज कल विदेशों में भारतीय चावल की भूसी की मांग बहुत कम है ।

(ख) चावल की भूसी (तेल निकली हुई) का निर्यात बढ़ाया जा रहा है और निर्माता निर्यातकर्ता को पुर्जों, मशीनों, आदि के लिए आयात लाइसेन्स के रूप में आवश्यक सहायता दी जा रही है, परन्तु इस लाइसेन्स के अन्तर्गत चावल की भूसी जो उन्होंने निर्यात की है, के ज ाज पूर्यन्त निःशुल्क मूल्य का १ प्रतिशत राशि के मूल्य का आयात हो सकता है । यह चावल की भूसी का तेल निकालने और उस का निर्यात सुविधाजनक बनाने के लिए है ।

ढलाई व गढ़ाई का दूसरा कारखाना

†७९६. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री २३ नवम्बर, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ३४७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच सरकारी क्षेत्र में दूसरा ढलाई-गढ़ाई संयंत्र स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)**: (क) और (ख) मामला अभी विचाराधीन है और शीघ्र ही इसे अन्तिम रूप दिये जाने की संभावना है ।

तम्बाकू

†७९७. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री १६ नवम्बर, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५२२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने इस बीच तम्बाकू की विभिन्न श्रेणियों के लिये न्यूनतम निर्यात मूल्य निर्धारित करने के प्रस्ताव पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में सरकार द्वारा क्या निर्णय किया गया है ?

†**अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख) २ मार्च, १९६३ को राजपत्र में जारी की गई एक अधिसूचना के अन्तर्गत फ्लू-उपचारित वरजीनिया तम्बाकू निर्यात व्यापार नियंत्रण आदेश के अधीन ले आया गया था तथा १९६३ की फसल के लिये न्यूनतम/अधिकतम निर्यात मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित कर दिय गये हैं । राज्य व्यापार निगम का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खादी एवं ग्रामोद्योग

७९८. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्य राज्यों की तुलना में केरल खादी एवं ग्रामोद्योग के विकास में पिछड़ गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में केरल के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी हां ।

(ख) कार्यान्वित करने वाली एजेन्सियों के मध्य समन्वित प्रयास का अभाव, किसी न किसी कारण से जनता की ओर से अपर्याप्त उत्साह संगठनात्मक तथा कार्य करने सम्बन्धी समस्यायें आदि कुछ ऐसे कारण थे जिनके फलस्वरूप केरल ने खादी तथा ग्रामोद्योगों ने अपेक्षाकृत कम प्रगति की है ।

(ग) तीसरी योजना के लक्ष्य पूरे करने के लिये एक कार्य-क्रम बनाने तथा चौथी आयोजना की अवधि के लिये एक योजना तैयार करने के लिये एक कार्यकारी दल गठित किया गया है । कार्यान्वित करने वाली विभिन्न एजेंसियों की गतिविधियों का सनन्वय करने की दृष्टि से अनेक प्रशासनात्मक तथा संगठनात्मक कदम उठाये गये हैं जिनमें प्रविधिक तथा परिवीक्षण कर्मचारियों का निकाय बनाना, काम काम के क्षेत्र का ठीक ठीक निर्धारण करना अदि शामिल है ।

खादी

७९९. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खादी की उत्पादन-लागत बराबर बढ़ती जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है और उसे कम करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ; और

(ग) खादी की कीमत निश्चित करते समय किन बातों को ध्यान में रखा जता है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) यह ठीक है कि खादी की कुछ किस्मों की कीमतें कभी कभी बढ़ी हैं ।

(ख) पिछले ७ या ८ साल से रुई की कीमतों तथा परिवहन की लागत बढ़ जाना इस वृद्धि का मुख्य कारण है ।

(ग) खादी की कीमतें निर्धारित करते समय (१) कच्चे माल की लागत (२) धुनाई, कताई तथा बुनाई की मजूरी (३) परिवहन, स्थापना आदि के ऊपरी खर्च तथा (४) उत्पादन तथा बिक्री के स्थान पर उत्पादन की लागत में जुड़ जाने वाले लाभों आदि को ध्यान में रखा जाता है ।

---

†मूल अंग्रजी में

मद्रास में सीमेंट का कारखाना

†८००. **श्री राम रतन गुप्त :** क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास में एक सीमेंट कारखाना स्थापित करने के लिये कोई लाइसेंस दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो किसे दिया गया है तथा कारखाने की क्षमता क्या है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :** (क) मद्रास राज्य में सीमेंट कारखानों की स्थापना के लिये अभी तक दो लाइसेंस दिये गये हैं ।

(ख) एक लाइसेंस मैसर्स इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड, मद्रास को सलेम जिले में संकरीद्रुग के समीप २००,००० टन प्रति वर्ष की क्षमता वाला एक सीमेंट कारखाना खोलने के लिये दिया गया है ; और दूसरा लाइसेंस मैसर्स चेट्टीनाड सीमेंट कारपोरेशन लि०, मद्रास को तिरुचिरापल्ली जिले में करूर के समीप ४००,००० टन प्रति वर्ष की क्षमता वाला एक सीमेंट कारखाना स्थापित करने के लिये दिया गया है ।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि०

†८०२. **श्री महेश्वर नायक :** क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की प्रसार योजना के अन्तर्ग्रस्त कारखानों की एक कड़ी स्थापित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित प्रसार की वित्तीय उपलक्षण क्या है ; और

(ग) किन राज्यों में नये कारखाने खोलने का विचार है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) :** (क) से (ग). बंगलौर स्थित दो कारखानों (एच० एम० टी० १ तथा २) के अतिरिक्त हिन्दुस्तन मशीन टूल्स लि० ने तीसरी योजनावधि के दौरान तीन और मशीनी औजार कारखाने स्थापित करने की योजना बनाई है । इनमें से एक के पिंजोर, पंजाब, में १९६३ के अन्त तक चालू हो जाने की आशा है । एक और कारखाने की केरल में एरनाकुलम के समीप कालमस्सेरी में बनाये जाने की स्वीकृति दी गई है । पांचवां मशीनी औजार कारखाना हैदराबाद में बनाने के प्रस्ताव की जांच की जा रही है । इन में से प्रत्येक कारखाने की पूंजी लागत अनुमानत: ७.५० करोड़ रुपये है जिसमें से विदेशी मुद्रा व्यय लगभग १.७५ करोड़ रुपय होगा ।

ब्रिटिश कपड़ा उद्योग

†८०३. **श्री महेश्वर नायक :** क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि इंग्लैंड में जिन मूल्यों पर भारतीय कपड़ा बेचा जा रहा है उससे ब्रिटिश कपड़ा उद्योग को चिन्ता हो रही है और उन्होंने भारतीय उद्योग को ऐसे उपाय करने के लिय कहा है जिससे ब्रिटिश मार्केट में मूल्य अस्तव्यस्त न हो जाये ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां ।

(ख) इस विषय पर ब्रिटिश कपड़ा उद्योग से बातचीत करने के लिये एक कपड़ा उद्योग प्रतिनिधिमंडल अगले महीने के दूसरे सप्ताह में इंग्लैंड जायेगा ।

इस्पात तथा लोहा कारखानें

†८०४. **श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निकट भविष्य में मैसूर राज्य में खोले जाने वाले प्रस्तावित इस्पात और लोहा कारखानों की संख्या क्या है ;

(ख) देश के अयस्क वाले अन्य क्षेत्रों की तुलना में मैसूर राज्य का सबसे अधिक अयस्क वाला क्षेत्र कौनसा है ;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार ने बेल्लारी जिलेमें हास्पेट अथवा सन्दूर में एक लोहा तथा इस्पात कारखाना खोलने का निर्णय किया है ; और

(घ) यदि हां, तो प्रस्तवित लागत तथा उत्पादन लक्ष्य क्या है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) भद्रावती में कच्चे लोहे के उत्पादन के लिये १२०,००० टन प्रतिवर्ष की क्षमता वाला एक नया यूनिट स्थापित करने का प्रस्ताव है । तीसरी पंचवर्षीय योजनावधि में मैसूर राज्य में नया इस्पात संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) मैसूर राज्य में सब से अधिक लौह अयस्क वाला क्षेत्र बेल्लारी-हास्पेट प्रतीत होता है । इस निक्षेप की देश के अन्य निक्षपों से भली भांति तुलना की जा सकती है ।

(ग) और (घ) चौथी योजनावधि में गोआ-हास्पेट प्रदेश में एक नया इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिये सुगमता अध्ययन किया जा रहा है । अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है । इस प्रकय पर संयंत्र की संभाव्य लागत बताना संभव नहीं है ।

इस्पात प्रौद्योगिकी संस्था

†८०५. **श्री महेश्वर नायक** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ सरकार एक इस्पात प्रौद्योगिकी संस्था स्थापित करने की योजना बना रही है ;

(ख) इस योजना की वित्तीय उपलक्षणायें क्या हैं ; और

(ग) क्या इसके स्थान का निर्णय कर लिया गया है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) से (ग). इंजीनियरिंग संस्थाओं में प्रशिक्षण को इस्पात उद्योग के लिये विशेषरूप से उपयुक्त बनाने के लिये उसके अभिमुखीकरण का प्रश्न विचाराधीन है । इसे एक अलग लोहा तथा इस्पात संस्था का रूप दिया जाये या किसी दूसरे तरीके से इस उद्देश्य को पूरा किया जा सकता है, इन बातों की अभी जांच

†मूल अंग्रेजी में

हो रही है । तदनुसार, ऐसी संस्था के लिये अभी कोई जगह चुनी नहीं गई है और न ही अभी कोई वित्तीय प्राक्कलन तैयार किये गये हैं ।

पंजाब में इंजीनियरिंग एकक

†८०६. **श्री हेम राज :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब सरकार ने १९६३ में अपने इंजीनियरिंग उद्योग एककों की आवश्यकता को पूरा करने के लिये तांबे, जस्ते तथा सीसे की कितनी मात्रा की मांग की है ;

(ख) अब तक कितनी मात्रा आवंटित और संभरित की गई है ;

(ग) क्या यह सच है कि कम संभरण के कारण अधिकतर इंजीनियरिंग एककों का उत्पादन कम हो गया है ; और

(घ) यदि हां, तो पंजाब के इंजीनियरिंग एककों की कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) पंजाब सरकार ने १९६३ के लिये अपनी आवश्यकताओं के बारे में कोई विशिष्ट अनुरोध नहीं किया ।

(ख) अक्तूबर १९६२,—मार्च १९६३ के दौरान किये गये आवंटनों के बारे में उपलब्ध जानकारी निम्नलिखित है :

	(आंकड़े मीट्रिक टनों में)
तांबा	१४८४
जस्ता	९७९
सीसा	१२.५

(ग) और (घ). उत्पादन कम होने के बारे में सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है । तथापि यह बता दिया जाए कि सर्वांग कमी के कारण छोटे पैमाने के एककों में वितरण के लिये विभिन्न राज्यों को अलौह धातुओं के आवंटन उनकी आवश्यकताओं से कम हैं ।

कांगड़ा में सीमेंट का कारखाना

†८०७. **श्री दलजीत सिंह :**
श्री हेम राज :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री २९ मार्च, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १३०८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब के कांगड़ा जिले में सीमेंट का कारखाना स्थापित करने में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या कारखाने के लिये स्थान अन्तिम रूप से चुन लिया गया है ; और

(ग) इसे कब स्थापित किया जायगा ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :** (क) अभी तक कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है ।

(ख) जी नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इस समय यह बताना संभव नहीं है कि कारखाना कब स्थापित किया जाएगा । अधिकतर तो यह अपेक्षित संयंत्र तथा उपकरण के लिये किये जाने वाले प्रबन्धों पर निर्भर करेगा ।

पुस्तकों का निर्यात

†८०८. **श्री बड़े** : क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६१–६२ में तथा १९६२–६३ में जून, १९६३ तक भारतीय पुस्तकों के निर्यात से विदेशी मुद्रा की कितनी राशि कमाई गई है ?

†**अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : १९६१–६२, १९६२–६३ के वित्तीय वर्षों तथा अप्रैल से जून, १९६३ तक के तीन महीनों के दौरान भारतीय पुस्तकों तथा पुस्तिकाओं (प्रकाशित) के निर्यात का मूल्य क्रमशः ७५ लाख रुपये, ६२ लाख रुपये तथा २५ लाख रुपये हैं ।

औद्योगिक विस्तार केन्द्र

†८०९. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में लघु उद्योग सेवा संस्था के अब तक स्थापित किये गये औद्योगिक विस्तार केन्द्रों का ब्योरा क्या है ; और

(ख) पंजाब राज्य के जिलों में ऐसे केन्द्र कहां कहां खोल गये हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) लघु उद्योग सेवा संस्था, पंजाब, के औद्योगिक विस्तार केन्द्रों का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

संस्था/औद्योगिक विस्तार केन्द्र का नाम	उपलब्ध सुविधायें
१. लघु उद्योग सेवा संस्था, लुधियाना	औजार प्रकोष्ठ तथा सामान्य इंजीनियरिंग प्रयोगशालायें ।
२. विस्तार केन्द्र, अम्बाला	वैज्ञानिक तरीके से कांच का सामान बनाने के लिये प्रशिक्षण सुविधायें तथा औजार प्रकोष्ठ ।
३. विस्तार केन्द्र, बटाला	सामान्य इंजीनियरिंग ।
४. ,, ,, कैथल	बढ़ई तथा लौहार का काम ।
५. ,, ,, जगाधरी	धातु परीक्षण प्रयोगशाला और विद्युत्-आवरण[1] ।
६. ,, ,, जालन्धर	खेल का सामान (परीक्षण की सुविधायें)
७. ,, ,, रिवाड़ी	जूते, विद्युत आवरण और अलौह ढलाई ।
८. ,, ,, फरीदाबाद	बढ़ई तथा लौहार का काम ।

†मूल अंग्रेजी में

[1] Electroplating.

(ख) पंजाब में औद्योगिक विस्तार केन्द्र की जिलावार स्थिति निम्नलिखित है :—

१.	जिला अम्बाला	(१) विस्तार केन्द्र, अम्बाला ।
		(२) ,, ,, जगाधरी ।
२.	,, गुरदासपुर	,, ,, बटाला ।
३.	,, गुड़गांव	(१) ,, ,, रिवाड़ी ।
		(२) ,, ,, फरीदाबाद ।
४.	,, जालन्धर	,, ,, जालन्धर ।
५.	,, करनाल	,, ,, कैथल ।
६.	,, लुधियाना	लघु उद्योग सेवा संस्था, लुधियाना ।

नया नंगल में उर्वरक कारखाना

†८१०. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उर्वरक कारखाना, नया नंगल, में उर्वरकों के उत्पादन में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) कारखाने की वर्तमान उत्पादन क्षमता क्या है ; और

(ग) मई तथा जून, १९६३ में कारखाने ने कितनी मात्रा में उर्वरकों का संभरण किया ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (ग) नंगल उर्वरक कारखाना ने फरवरी १९६१ में उत्पादन आरम्भ किया । कारखाने में उर्वरक का उत्पादन (केल्शियम अमोनियम नाइट्रेट) इस प्रकार से रहा है :—

(१)	फरवरी तथा मार्च, १९६१	१०,८४० टन
(२)	१९६१–६२	२,००,७८० टन
(३)	१९६२–६३	२,८४,३२२ टन
(४)	१९६३–६४ (३१ जुलाई, १९६३ तक)	१,२३,४०३ टन
	कुल	६,१९,३४५ टन

(ख) ३३० काम के दिनों के आधार पर कारखाने के वर्तमान उत्पादन क्षमता १,१७६ टन प्रति दिन अथवा ३,८८,००० टन प्रति वर्ष है ।

(ग) करखाने ने मई, १९६३ में लगभग ३४,७०० टन तथा जून, १९६३ में लगभग ३०,००० टन उर्वरक भेजा ।

हिमाचल प्रदेश में कपास कताई मिल

†८११. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री १५ मार्च, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७८३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में एक कपास मिल स्थापित करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ।

†**अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : पाओंटा (हिमाचल प्रदेश) में १२,००० तकुओं वाली कपास की कताई की एक नई मिल की स्थापना के लिये २९ अप्रैल, १९६३ को लाइसेंस

†मूल अंग्रेजी में

दे दिया गया है। ऐसे उपक्रमों की स्थापना के हेतु प्रभावी उपाय करने के लिये छः महीनों का समय दिया जाता है ।

हिन्दुस्तान केबल फैक्टरी

†८१. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री ब० कु० दास :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूपनारायण, पश्चिम बंगाल, में हिन्दुस्तान केबल फैक्टरी के प्रसार कार्यक्रम में आज तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिये असैनिक निर्माण का काम आगे बढ़ा है ;

(ग) कितने प्रतिशत आयातित संयंत्र और मशीनें पहुंच चुकी हैं ; और

(घ) उन फर्मों के क्या नाम हैं जो इन उपकरणों का संभरण कर रही हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) प्रसार कार्यक्रम में सन्तोषजनक प्रगति हो रही है तथा संयंत्र में इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक उत्पादन आरंभ हो जाने की संभावना है ।

(ख) जी हां ।

(ग) ३६ प्रतिशत पहुंच चुका है ।

(घ) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

१. मैसर्स गैम्ब्रेल ब्रदर्स एण्ड कम्पनी लि०, इंग्लैंड ।
२. ,, एच० टेंसले एण्ड कम्पनी लि०, इंग्लैंड ।
३. ,, विकमैन लि०, इंग्लैंड ।
४. ,, जान डाकर एण्ड कम्पनी (इंजीनियर्स लि०), इंग्लैंड ।
५. ,, सुल्लीवन लि०, इंग्लैंड ।
६. ,, हायकिन्स लि०, इंग्लैंड ।
७. ,, ब्लैकफेयर्स रोटरी कटर्स लि०, इंग्लैंड ।
८. ,, दि टर्नर एण्ड कम्पनी स्काट लि०, इंग्लैंड ।
९. ,, नार्थेम्पटन मशीनरी कम्पनी लि०, इंग्लैंड ।
१०. ,, ट्रैफाल्गर इंजीनियरिंग कम्पनी, इंग्लैंड ।
११. ,, इलेक्ट्रानिक इन्स्ट्रूमेंट्स लि०, इंग्लैंड ।
१२. ,, बारनेबी इंजीनियरिंग कम्पनी, इंग्लैंड ।
१३. ,, स्टण्डर्ड टेलीफोन्स एण्ड केबल्स लि०, इंग्लैंड ।

†मूल अंग्रेजी में

१४. मैसर्स विनगेट सिनकरो लि०, इंग्लैंड ।

१५. ,, एच० डब्ल्यू० वालान्स एण्ड कम्पनी, इंग्लैंड ।

१६. ,, इह्डोन ब्रदर लि०, इंग्लैंड ।

१७. ,, गोयबल जी० एम० बी० एच, पश्चिम जर्मनी ।

१८. ,, जोसेफ क्लेसरेपोल मासेह्निनफैब्रिक, पश्चिम जर्मनी ।

एडिन्बरा में चाय केन्द्र

†८१३. **डा० महादेव प्रसाद** : क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चाय बोर्ड ने एडिन्बरा में एक चाय केन्द्र खोलने का उपक्रम किया था ;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) इसकी वित्तीय उपलक्षणायें क्या हैं ?

†**अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). जी हां । चाय बोर्ड द्वारा १२१, प्रिंसिज स्ट्रीट, एडिन्बरा में एक चाय केन्द्र खोला गया है । इसे अनौपचारिक रूप से २७ मई, १९६३ को खोला गया था । आशा है कि २ सितम्बर, १९६३ को लन्दन में भारत के उच्चायुक्त औपचारिक रूप से इसका उद्घाटन करेंगे ।

(ग) वित्तीय उपलक्षणायें निम्नलिखित हैं :—

अनावर्ती व्यय

(१) पट्टे की लागत . . .	१३,८०० पौंड
(२) फिटिंग, सजावट आदि . .	३०,००० पौंड
कुल .	४३,८०० पौंड

आवर्ती व्यय

(१) किराया, दरें, बीमा, टेलीफोन, लेखन सामग्री .	६८ पौंड
(२) गैस, बिजली, सफाई और लांड्री .	२५ पौंड
(३) स्टाफ	१६० पौंड
(४) अवयव, किराना आदि .	९२ पौंड
कुल	३४५ पौंड

आय : (प्रति सप्ताह—१ जुलाई, १९६३ से १० अगस्त, १९६३ तक की अवधि में केन्द्र द्वारा किये गये विक्रय की लागत पर आधारित) ३२५ पौंड ।

†मूल अंग्रेजी में

औद्योगिक उत्पादन

†८१४. **डा० महादेव प्रसाद :**
श्री रामेश्वरानन्द :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष औद्योगिक उत्पादन की क्या स्थिति रही ;

(ख) क्या औद्योगिक उत्पादन की गति बढ़ाने के लिए सरकार ने कोई उपाय किये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उनका विवरण क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) औद्योगिक उत्पादन का सामान्य सूचक अंक (आधार १९५६-१००) १९६१ की तुलना में १९६२ में ७.६ प्र० श० बढ़ा है। जनवरी-अप्रैल १९६३ में हुई वृद्धि १९६२ की इसी अवधि से ८.७ प्र० श० अधिक है। जनवरी-मई, १९६३ की अवधि में, १९६२ की इसी अवधि की तुलना में अनेक वस्तुओं के उत्पादन में २० प्र० श० या इससे भी अधिक वृद्धि हुई जिनमें तैयार इस्पात, कच्चा लोहा, अलूमिनियम, मशीनी औजार, ट्रिवट्रिस्ट ड्रिल्स, रेलों के माल-डिब्बे, मोटर साइकिलें, सूखे सैल, बिजली के मोटर, बिजली के लैम्प, ए सी एस आर केबिल्स, डीजल इंजन (अचल), गन्धक का तेजाब, सोडा एश, सुपर फास्फेट्स, औद्योगिक मद्यसार, एसिटिलीन गैस, एसबस्टस, सीमेन्ट की चादरें, चमड़े के जूते तथा व्यापारिक प्लाईवुड शामिल हैं।

(ख) और (ग). सरकारी क्षेत्र के अनेक महत्वपूर्ण कारखानों में उत्पादन बढ़ाया गया। कुछ प्राथमिक वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने की आवश्यकता के कारण आयात किये गये तथा देश में ही उपलब्ध दुर्लभ कच्चे मालों का नियतन निर्धारित करना जारी रहा। सरकारी तथा निजी क्षेत्र की औद्योगिक प्रायोजनाओं को शीघ्र से शीघ्र कार्यान्वित करने के प्रयत्न किये गये।

मुद्रण यंत्र उद्योग

†८१५. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री वारियर :
श्री बूटा सिंह :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री ओंकारलाल बेरवा :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुद्रण यंत्र उद्योग के बारे में जांच करने तथा जानकारी देने के लिये सरकार द्वारा नियुक्त तालिका ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने तालिका द्वारा की गई सिफारिशों की जांच कर ली है ; और

(ग) उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) तालिका द्वारा की गई सिफारिशों को सरकार ने सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

अभ्रक का निर्यात

†८१६. श्री विश्राम प्रसाद :
श्री बृजराज सिंह :
श्री कछवाय :

क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अभ्रक के उद्योगपतियों तथा निर्यातकों ने मूल्य आलम्ब[1] की कोई नई प्रक्रिया निर्धारित करने के लिये सरकार को अभ्यावेदन भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

†**अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) और (ख) . यद्यपि यह प्रश्न अभ्रक के निर्यातकों के साथ हुई बैठकों में उठाया गया है परन्तु इस मंत्रालय को कोई औपचारिक अभ्यावेदन नहीं भेजा गया है । किस्म नियंत्रण तथा लदान-पूर्व निरीक्षण की व्यवस्था करके, वस्तुनिष्ठ स्तर निर्धारित करके और खेप आधार पर निर्यात को निरुत्साहित करके अभ्रक के निर्यात से अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा कमाने का यह मामला परीक्षाधीन है ।

कागज का उत्पादन और वितरण

†८१७. श्री यशपाल सिंह :
श्री बूटा सिंह :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री बालकृष्ण वासनिक :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कागज के उत्पादन, वितरण तथा उसकी मांग के प्रश्न की जांच करने के लिये हाल ही में उनके मंत्रालय ने कागज तदर्थ समिति की एक बैठक बुलाई थी ; और

(ख) क्या सरकार द्वारा कागज के प्रयोग में बचत की कोई गुंजाइश है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कामूनगो)** : (क) जी हां । कागज तदर्थ समिति की एक बैठक ३ जुलाई, १९६३ को हुई थी ।

(ख) समय-समय पर सभी सरकारी संगठनों का ध्यान कागज के इस्तेमाल में अधिकतम बचत करने की आवश्यकता की ओर दिलाया जा रहा है । अग्रेतर बचत करने की संभावनाओं का भी लगातार पुनर्विलोकन किया जा रहा है ।

साबुन उद्योग

†८१८. **श्री दे० जी० नायक** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नारियल और नारियल के तेल के आयात पर और प्रतिबन्ध लगा दिये हैं; और

(ख) यदि हां, क्या देश में साबुन उद्योग पर इसका प्रभाव पड़ा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Price Support.

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) माननीय सदस्य का निदश स्पष्टत: खोपरा और नारियल की गिरि से है क्योंकि नारियल का कदाचित ही कभी आयात किया गया हो। अक्तूबर, १९६२ से खोपरे के प्रत्यक्ष आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। इसके बजाय इसका आयात बनस्पति, साफ किये गये मूंगफली के तेल आदि की विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं से मिला दिया गया है। तथापि विभिन्न यथार्थ प्रयोक्ताओं में वितरण के लिये राज्य व्यापार निगम द्वारा कुछ खोपरे का आयात जारी है ।

नारियल के तेल का आयात विगत कुछ समय से नहीं किया जा रहा है । फिर भी भारत-श्रीलंका व्यापार समझौते के अन्तर्गत थोड़ी मात्रा में इसका आयात किया जा रहा है।

(ख) संगठित एककों पर इसका प्रभाव नहीं हुआ है किन्तु कुछ छोटे एकक जो निर्यात संवर्द्धन योजना का लाभ उठाने की स्थिति में नहीं हैं, उन्हें प्रतिस्पर्धात्मक आधार पर उत्पादन बनाये रखने में समुचित मात्रा में नारियल के तेल की मात्रा प्राप्त करने में कठिनाई हो गई है।

चप्पलें

८१९. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में बनी हुई चप्पलों की विदेशों में मांग है;

(ख) यदि हां, तो कितनी मांग है; और

(ग) १९६२ में चप्पलों के कितने जोड़े निर्यात किये गये और उनसे विदेशी मुद्रा की कितनी आय हुई ?

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग). चप्पलों की मांग पूर्वी यूरोपीय देशों और सऊदी अरब में है। दिल्ली में बनी हुई चप्पलों की कितनी मांग है तथा १९६२ में कितने मूल्य की और कितने परिमाण में उनका निर्यात किया गया यह ठीक-ठीक बता सकना कठिन है। इसका कारण यह है कि चप्पलों के निर्यात के आंकड़े अलग नहीं रखे जाते। चप्पलें जूतों के वर्ग में शामिल हैं ।

एकस्व विधि[1]

†८२०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक नई एकस्व विधि अधिनियमित करने का प्रस्ताव है जिसके अन्तर्गत खाद्य वस्तुयें, औषध और दवाओं के नये पेटेंट की अनुमति नहीं दी जायेगी; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). पेटेंट सम्बन्धी सम्पूर्ण विधि के पुनरीक्षण के प्रश्न पर सरकार सक्रिय विचार कर रही है और मैं शीघ्र ही इस विषय में संसद् के समक्ष एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करूंगा। माननीय सदस्य से प्रार्थना है कि वह इस विधेयक की प्रतीक्षा करें।

लोहा और इस्पात का वितरण

†८२१. **श्री कजरोलकर** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या १९६२-६३ में प्रत्येक राज्य में लोहे और इस्पात के वितरण की मात्रा बताने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जायगा ?

---

†मूल अंग्रजी में

[1]Patent Law.

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)**: विभिन्न राज्यों में १९६२–६३ में कच्चा लोहा और देशी तैयार शुदा इस्पात की प्रेषण (सप्लाई जिसमें प्रतिबंधित और प्रतिबन्धों की ढिलाई वाले वर्ग सम्मिलित हैं) बताने वाला विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—१५३५/६३**]

रूरकेला और दुर्गापुर इस्पात कारखाने

†८२२. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भिलाई इस्पात कारखाने की तुलना में रूरकेला और दुर्गापुर इस्पात कारखानों की धीमी प्रगति के कारणों की जांच करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)**: माननीय सदस्य संभवत: रूरकेला और दुर्गापुर में आनुपातिक उत्पादन की प्रगति की ओर निदश कर रहे हैं। ये दोनों कारखाने विभिन्न उत्पादनों के लिये बनाये गये थे तथा उनकी स्थापना भी भिलाई की अपेक्षा देर से की गई थी। रूरकेला में एकसा उत्पादन और जटिल संयंत्र होने के कारण यथानुपात क्षमता तक पहुंचने में स्वभावत: अधिक समय लगा है। दुर्गापुर में पहिये और धुरियां जैसी विशिष्ट चीजें बनाई जाती हैं तथा भिलाई से उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। जो कार्यवाही आवश्यक समझी गई उसकी समय समय पर पूर्ति कर दी गई ताकि इन कारखानों की स्थापना और इनमें कार्य आरम्भ करने में शीघ्रता की जा सके। यह भी उल्लेखनीय है कि सरकारी उद्योग क्षेत्र को यह तीनों कारखाने प्राय: अपनी निर्धारित क्षमता के अनुसार उत्पादन कर रहे हैं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

उत्तर प्रदेश, गुजरात और अन्य राज्यों को ढलवें लोहे का अपर्याप्त संभरण

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री बनर्जी।

डा० राम मनोहर लोहिया (फरुखाबाद) : अध्यक्ष महोदय, निजी सफाई। निजी सफाई देने के पहले मैं जानना चाहूंगा कि तीन आने और पन्द्रह आने वाली लड़ाई पर प्रधान मंत्री को कुछ कहना है ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इस तरह से हाउस की बाकायदा कार्यवाही को इन्टरेप्ट न करें। अगर वह चाहते हैं कि उस की सफाई हो, तो वह लिख कर भेजें। मैं उनसे पूछूंगा।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : मैं इस्पात और भारी उद्योग मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वे इसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

उत्तर प्रदेश, गुजरात और अन्य राज्यों को ढलवां लोहे का अपर्याप्त संभरण।

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)**: मैंने १ मई, १९६३ के अपने वक्तव्य में ढलाई घरों को ढलवां लोहा देने के बारे में स्थिति स्पष्ट की थी। अब मैं उसको दुहराता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

यद्यपि इस समय ढ़लाई लोहे की मांग का अनुमान २० लाख टन से भी अधिक है। उपलब्धता केवल ११ लाख टन है। इस सन्तुलन का मुख्य कारण यह है कि ढलाईघर क्षमता तो पिछले दो वर्ष में बढ़ गई है, किन्तु उत्पादन उतना ही रहा है। तीसरी योजना के अन्त तक १५ लाख टन उत्पादन की आशा थी, जिसमें से लगभग १० लाख टन इस्पात कारखानों से और ५ लाख निजी क्षेत्र के कच्चे लोहे के संयंत्रों में से आता था। कालिंगा को छोड़ कर, कोई लाइसेंस की हुई योजना पूरी नहीं हुई। यद्यपि ढलवां लोहे का उत्पादन नई योजनाओं के द्वारा बढ़ाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं, अगले दो वर्षों में उपलब्धता ११ लाख टन से बढ़ने की आशा नहीं है, जब तक कि कुछ आयात प्राप्त न हो।

ढ़लाईघरों की क्षमता में वृद्धि होने और उसके परिणामस्वरूप मांग बढ़ने के कारण उत्पादकों के पास लगभग १२ लाख टन के क्रयादेश पहले से पड़े हैं। इससे क्रयादेश पूरा करने में विलम्ब होता है। अतः यह निर्णय किया गया है कि १ अप्रैल, १९६३ से वितरण की पुनरीक्षत योजना लागू की जाये। इस योजना के अनुसार अत्यावश्यक मांगों को पूरा करने के पृथक पृथक कोटे निर्धारित किये गये हैं; जैसे प्रतिरक्षा —६०,००० टन, रेलवे स्लीपर निर्माण ३००,००० टन, विभिन्न सरकारी विभागों के संभरण तथा उत्सर्जन महानिदेशालय द्वारा भेजे गये क्रयादेशों की पूर्ति ३०,००० टन आदि। इस के अतिरिक्त राज्य सूची में निहित ढलाईघरों (छोटे पैमाने के) को संभरण के लिए १२०,००० टन और केन्द्र सूची में निहित ढ़लाई घरों (बड़े पैमाने के) को १७६,००० टन राज्यों के लिये १,२०,००० टन की अधिकतम सीमा को विभिन्न राज्यों में बांटा गया है। यह वितरण १९६०, १९६१ और १९६२ के वर्षों में उनकी सबसे अधिक संभरण वाले वर्ष के आधार पर किया गया। प्रत्येक ढ़लाईघर को मिलने वाली वार्षिक मात्रा को इस राज्य के लिए निर्धारित अधिकतम सीमा के आधार पर हिसाब लगाया गया है।

यह स्थिति सभी राज्यों में है, केवल उत्तर प्रदेश या गुजरात में नहीं है। १९६३-६४ में सब राज्यों को उचित हिस्सा मिलेगा।

उपलब्धता और मांग में अन्तर होने के कारण राज्य सूची के ढ़लाई घरों के अधिकार उसकी क्षमता की तुलना में कम है। तथापि वे कच्चे लोहे के साथ साथ बहुत से ढ़ले लोहे का भी प्रयोग करते हैं, जिस पर कोई नियंत्रण नहीं है, अतः ढलाईघर २० से ३० प्रतिशत क्षमता पर काम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, उन ढलाई घरों को, जिन्हें सरकार या रेलवे स्लीपरों के आदेश प्राप्त होते हैं, ६० से ७० प्रतिशत क्षमता से काम कर सकते हैं।

मैं पटल पर एक विवरण रख रहा हूं। जिसमें ढलवां लोहे का वितरण क्षेत्रवार तथा राज्यवार दिखाया गया है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश में कच्चे लोहे का कोटा २ लाख टन से घटा कर १४ या १५ हजार टन कर दिया गया है।

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : मेरे विचार में यह सत्य नहीं है। कुछ भी हो, राज्य सूची ढलाई घरों का कोटा १,४३,०० टन है। मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में कुछ कठिनाई है। कानपुर में मुझे अभ्यावेदन भी दिये गये थे और मैंने स्थिति स्पष्ट कर दी थी। ६ मासों के बाद सुधार होने की संभावना है।

†**श्री जसवन्त मेहता** (भावनगर): मैं जानना चाहूंगा कि सरकार ने निर्माताओं को पर्याप्त मात्रा में कच्चा लोहा देने के लिए क्या पग उठाये हैं?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : यह स्थिति सारे देश में ऐसी ही है। हम कच्चे लोहे का कुछ आयात कर रहे हैं और वितरण की प्रणाली का भी पुनरीक्षण कर रहे हैं।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सदन अगला कार्य लेगा—पटल पर रखे जाने वाले पत्र।

श्री बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इस तरह इन्टरेप्ट न करें। अगर वह चाहते हैं, तो लिख कर भेज दें या मेरे पास आ जायें।

श्री बागड़ी : बहुत अच्छा वह गाजियाबाद के किसानों के बारे में है।

रबड़ (दूसरा संशोधन) नियम और प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन

†**आर्थिक तथा प्रतिरक्षा समन्वय मंत्रालय में संभरण मंत्री (श्री हाथी)** : मैं श्री मनुभाई शाह की ओर से निम्न पत्रों की एक-एक प्रति पटल पर रखता हूं :—

(१) रबड़ अधिनियम, १९४७ की धारा २५ की उपधारा (३) के अन्तर्गत, दिनांक २७ जुलाई, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२४२ में प्रकाशित रबड़ (दूसरा संशोधन) नियम, १९६३ की एक प्रति। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० १५२२/६३]**

(२) प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६ की उपधारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(क) ऊनी धागे, वस्त्रों और हौजरी के सामान के उचित मूल्यों के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९६२)।

(ख) दिनांक २८ जून, १९६३ का सरकारी संकल्प संख्या १७(२६)—टेक्स (डी)/६२।

(ग) उपरोक्त (क) और (ख) में उल्लिखित दस्तावजों की एक-एक प्रति उक्त उपधारा में निर्धारित अवधि के भीतर न रखे जाने के कारण बताने वाला विवरण।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल टी—१५२३/६३]

हिन्दुस्तान नमक लि० के ज्ञापन और अन्तर्नियम

†**श्री हाथी** : श्री कानूनगो की ओर से हिन्दुस्तान नमक लि०, जयपुर के ज्ञापन और अन्तर्नियमों की एक प्रति पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—१५२४/६३]

---

†मूल अंग्रेजी में

पांडिचेरी सीमेंट नियंत्रण आदेश

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : अत्यावश्यक पण्य अधिनियम १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत दिनांक १५ जुलाई, १९६३ के पांडिचेरी गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या २३२२—६३ कान की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जिस में पांडिचेरी सीमेंट नियंत्रण आदेश, १९६३ दिया हुआ है ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी—१५२५/६३]

विधेयक पर राय

†**श्री जं० ब० सिं० बिष्ट** (अलमोड़ा) : मैं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, १९५६ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक के बारे में जिसे २२ जून, १९६२ को सभा के निदेश से उस पर राय जानने के लिए परिचालित किया गया था, राय के पत्र संख्या ३ को सभा पटल पर रखता हूं ।

सभा का कार्य

आगामी सप्ताह के लिऐ सरकारी कार्य

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह)** : आप की अनुमति से मैं २६ अगस्त, १९६३ को आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य की घोषणा करता हूं :

(१) आज के आदेश पत्र से बची हुई काम की मद पर विचार

(२) व्यक्तिगत चोट (प्रतिकर बीमा विधेयक, १९६३ पर विचार तथा उसे पारित किया जाना

(३) निम्न विधेयकों पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार और उनका पारित किया जाना :

(क) भारतीय वस्तु विक्रय (संशोधन) विधेयक, १९६२

(ख) विशेष विवाह (संशोधन) विधेयक, १९६३

(ग) औद्योगिक रोज़गार (स्थायी आदेश) संशोधन विधेयक, १९६२

(घ) व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, १९६३

(ङ) कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक, १९६३

(च) पूर्वी पंजाब तथा हकीम (दिल्ली) संशोधन विधेयक, १९६३

(४) सरकारी भूगृहादि (अवैध रूप से कब्ज़ा करने वालों का निष्कासन) विधेयक, १९६३ पर विचार तथा उसको पारित किया जाना ।

(५) सोमवार, २६ अगस्त, १९६३ को ३ म० प० बजे श्री म० ला० द्विवेदी द्वारा एक प्रस्ताव पेश किये जाने पर वर्ष १९६१–६२ के लिये भारत के राज्य व्यापार निगम के वार्षिक प्रतिवेदन पर चर्चा ।

(६) मंगलवार २७ अगस्त, १९६३ को प्रश्नों को निपटाये जाने के बाद अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित आदिम जातियां आयोग के प्रतिवेदन पर आगे चर्चा ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : मैं अनुभव करता हूं कि चूंकि चीनी का प्रश्न बहुत महत्व-पूर्ण है, इस पर चर्चा की अनुमति दी जाये। दूसरे मैं यह पूछना चाहता हूं कि रुयबी एंड न्यू एशियाटिक इन्शुरेन्स कम्पनी के बारे में चर्चा के लिए माननीय मंत्री क्यों तैयार नहीं हैं ?

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों सम्बन्धी समिति के बारे में जो संकल्प है, उसके सम्बन्ध में क्या स्थिति है ?

†**श्री शिव मूर्ति स्वामी** (कोप्पल) : गुलहाटी आयोग के प्रतिवेदन पर भी बहस होनी चाहिये।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : मैं भी सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के बारे में संकल्प की सूचना चाहता हूं ।

†**श्री सत्यनारायण सिंह** : चीनी की स्थिति के बारे में मंत्रालय ने राज्य-सभा में चर्चा करना मान लिया है, किन्तु इस सदन में नहीं माना । मैं फिर मंत्रालय से पूछूंगा और सरकार की प्रतिक्रिया आपको बताऊंगा ।

दूसरे मामले की चर्चा के लिए वित्त मंत्रालय तैयार नहीं है, क्योंकि इस पर सामान्य चर्चा और वित्त विधेयक के दौरान चर्चा हो चुकी है ।

जहां तक सरकारी उपक्रम सम्बन्धी समिति का सम्बन्ध है, आपसे और राज्य सभा के सभापति से सलाह करूंगा और जो भी निर्णय होगा, सदन के सामने रख दिया जायेगा ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : वित्त मंत्रालय सहमत हो या न हो, प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने का वचन दिया गया था, किन्तु इसे रखा नहीं गया ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं देखूंगा कि क्या वचन दिया गया था या नहीं । गुलहाटी आयोग के प्रतिवेदन के बारे में, वे स्थिति को जान कर बतलायें ।

†**श्री सत्यनारायण सिंह** : मेरे विचार में इसे प्रस्ताव के रूप में स्वीकार नहीं किया गया । यदि यह उसमें है, तो मैं इस पर विचार करूंगा ।

श्री मोहन स्वरूप (पीलीभीत) : अध्यक्ष महोदय, मैं ज़रा सी एक बात पूछना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : अब नहीं ।

श्री मोहन स्वरूप : मैं शूगर के ही बारे में पूछना चाहता हूं । आपने एडमिट किया था . . .

अध्यक्ष महोदय : वह पूछा गया था और आपने शायद उस वक्त ध्यान नहीं दिया ।

व्यक्तिगत चोट (प्रतिकर बीमा) विधेयक

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरमन्** : श्रीमान्, श्री गुलजारीलाल नन्दा की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि व्यक्तिगत चोट लगने वाले श्रमिकों को प्रतिकर देने का दायित्व नियोजकों पर डालने और उस दायित्व के लिए नियोजकों का बीमा करने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि व्यक्तिगत चोट लगने वाले श्रमिकों को प्रतिकर देने का दायित्व नियोजकों पर डालने और उस दायित्व के लिए नियोजकों का बीमा करने की व्यवस्था करने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित कहने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरमन् :** मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), १९६३–६४

†**अध्यक्ष महोदय :** अब हम वर्ष १९६३–६४ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगों (रेलवे) पर चर्चा आरम्भ करेंगे ।

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** १९६३–६४ की इन मांगों के बारे में यह कहना आवश्यक है कि ये अतिरिक्त राशियां इस अवस्था पर लेने के लिए नहीं हैं, अब मूल रेलवे बजट बनाने में कोई त्रुटियां नहीं थीं । इन दो अनुपूरक मांगों के अन्तर्गत जो मद शामिल किये गये हैं, वे सेवा में नये उपकरणों के स्वरूप के हैं, जिनकी ओर संसद् का ध्यान दिलाना आवश्यक है । प्रत्येक मद के लिए ५०,००० रुपये रखे गये हैं, यद्यपि यह खर्चा मंजूर किये गये आय-व्ययक में से किया जा सकता है ।

प्रारम्भिक जांच पड़ताल के सर्वेक्षण में, जो अनुपूरक मांग संख्या २ में शामिल है, मार्मागाओं पत्तन के विकास के फलस्वरूप पत्तन की बड़ी रेलवे लाइन से मिलाने की आवश्यकता और सम्भावित बोकारो इस्पात कारखाने के लिए रेलवे सुविधाओं की व्यवस्था करना शामिल है । ये सब विकास कार्यवाही अभी पूरी तरह चालू नहीं हुई और इन्हें मूल रेलवे आय-व्ययक या अनुपूरक आय-व्ययक में सम्मिलित नहीं किया जा सका । इसी तरह, फरक्का पर रेल और नाव द्वारा बढ़े हुए परिवहन को पूरा करने के लिए अनुपूरक मांग संख्या १५ में जो उपबन्ध किया गया है, यह उस मूल्यांकन का परिणाम है जो प्रतिरक्षा और फरक्का बांध परियोजना प्रशासन आदि की परिवहन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया है । यहां भी सुविधाओं के विस्तार का प्रश्न अभी विचाराधीन है, ताकि फरक्का बांध बनने तक दुहरे प्रबन्ध पर खर्च न करना पड़े ।

वर्ष १९६३–६४ के लिए अनुदानों की निम्नलिखित अनुपूरक मांगें प्रस्तुत की गईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
२	विविध व्यय . .	१,५०,०००
१५	खुली लाइन कार्य परिवर्द्धन और बदली .	१,००,०००

†**अध्यक्ष महोदय :** इन पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जा सकते हैं ।

†मूल अंग्रेजी में

अनुपूरक अनुदानों (रेलवे) की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्ताविक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
				रुपये
२	१	श्री प्रभात कार	बोकारो जैसी महत्वपूर्ण लाइनों के सर्वेक्षण की प्रक्रिया	१००
१५	२	श्री प्रभात कार	फरक्का के सम्बन्ध में आयोजन का न होना ।	१००

†**अध्यक्ष महोदय** : ये कटौती प्रस्ताव सभा के समक्ष प्रस्तुत हैं ।

†**श्री नम्बियार** (तिरुचिरापल्लि) : मैं दक्षिण रेलवे के एक भाग के बारे में कहना चाहता हूं, जिसमें अधिक व्यय नहीं है ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

पुडुकोटाल विभाग पर एक आऊट एजेंसी थी जिसे अब बिना कारण के हटा दिया गया है । जिसके फलस्वरूप शहर के लोगों को, जोकि दो मील दूर है, बुकिंग के लिए बहुत कठिनाई होती है । इस सुविधा को पुनः जारी कर देना चाहिये ।

मांग संख्या १५ के बारे में, दक्षिण रेलवे पर निर्माण कार्य बहुत धीमा कर दिया गया है । विल्लुपुरम और तम्बारम के बीच विद्युतीकरण का काम बहुत धीरे कर दिया गया है । क्या इस में शीघ्रता नहीं लाई जा सकती ? विल्लुपुरम से केवल ३० मील दूर नेवेली परियोजना है । यदि नेवेली को मद्रास पत्तन के साथ नहीं मिलाया जाता, तो केवल विल्लुपुरम तक विद्युतीकरण करने का कोई लाभ नहीं होगा ।

गोलारपेट और शोरानूर के बीच लाइन को दोहरा करने के प्रश्न पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए ।

मद्रास और विजयवाड़ा के बीच अड़चन को दूर करना चाहिए । दक्षिण रेलवे इस समय घाटे पर चल रही है । इस स्थिति में भी सुधार आवश्यक है ।

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : उपाध्यक्ष महोदय, यह सप्लिमेंटरी डिमांड्स जो पेश की गई हैं उनके लिये मैं माननीय रेलवे मंत्री, सरदार स्वर्ण सिंह जी को बधाई देता हूं । आपको इसलिए मुबारकबाद देता हूं कि आपकी दिन रात की कोशिशों से और आपके भजन बन्दगी के प्रताप से रेलवे के ऐक्सिडेंट्स को कंट्रोल किया गया है । ईश्वर की कृपा से रेलवे ऐक्सिडेंट्स को हम रोक सके हैं । इसलिये मैं आप को मुबारकबाद देता हूं ।

पूना से ले कर मीराज तक . . . . .

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : ये मांग रेल दुर्घटनाओं के बारे में नहीं है । माननीय सदस्य को संगत बातें करनी चाहियें ।

श्री यशपाल सिंह : यह जो डिमान्ड दी गई है उसमें जो प्राग्रेस हुई है उसके लिये भी मैं आप को मुबारकबाद देता हूं ।

पार्लियामेंट का यह रिवाज है कि जो अच्छा काम करते हैं उनको मुबारकबाद मिलना चाहिए, उनको बधाई देनी चाहिए ।

यह जो दस बारह करोड़ रुपया गोआ तक लाइन ले जाने में खर्च होगा इसका सब से ज्यादा फायदा हम को यह होगा कि इस वक्त जो हम वहां के आयरन ओर से फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, इस लाइन के बनने के बाद उससे फायदा उठा सकेंगे ।

इसके अलावा गोआ हमारा मोस्ट इम्पारटेंट सेंटर है । गोआ की हाल में आजादी हुई है । इसकी तेजी से तरक्की करना हमारा सब से पहला फर्ज है । तो गोआ तक यह ब्राड गेज लाइन तैयार हो जानी चाहिए और इस लाइन पर जो खर्च हो उस को इस हाउस को खुशी से पास करना चाहिए । और जो मिरज से मारमा गोआ तक १८७ मील का टुकड़ा है उसको भी ब्राडगेज बनाना बहुत जरूरी है । यह डिमांड बहुत मुनासिब है और इस को हाउस को पास कर देना चाहिए । लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि जो इलाके पिछड़े हुए हैं उन इलाकों की तरफ भी ध्यान दिया जाय ।

शाहदरा से सहारनपुर की जो मीटरगेज लाइन है इससे उस इलाके की तरक्की रुकी हुई है । इसकी तरफ भी ध्यान दिया जाय । चूंकि यह प्राइवेट फर्म मार्टिन बर्न एंड कम्पनी की है, इसलिये यह हमारे समाजवाद के साथ फिट नहीं करती । जब समाजवाद का वायदा किया गया है तो जो प्राइवेट कनसर्न हैं उनको गवर्नमेंट या पबलिक कनसर्न बनाया जाय, इनको जनता की प्रापर्टी घोषित किया जाय । जब तक यह कम्पनी के हाथों में रहेगी तब तक इस इलाके की तरफ तरक्की नहीं हो सकेगी । यह इलाका हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा गन्ना और गुड़ पैदा करता है । यह मेरी कांस्टीट्यूएंसी में आता है । यू० पी० से सारे ५२ जिलों में से सबसे ज्यादा रुपया नेशनल डिफेंस फंड में इस इलाके ने दिया है । लेकिन इस लाइन को आज तक ब्राडगेज नहीं किया गया है । जरूरत इस बात की है कि इस लाइन को बड़ी लाइन करने की कोशिश की जाय, और यह जो वर्क इन प्राग्रेस है इसको फौरन पूरा किया जाय ।

इसी के साथ साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि हमको कोई ऐसा मौका नहीं मिलता कि हम अपनी दिक्कतों को आपके सामने रख सकें । यह मौका इस डिमांड के अन्दर होना चाहिए कि जो मेम्बरान की दिक्कतें हैं उनको वे आपके सामने रख सकें । उत्तर प्रदेश से जो लोग यहां बतौर मेम्बर आये हैं उनको अपनी दिक्कत आप के सामने रखने का कोई मौका नहीं है । मैंने कई दफा आप को रेलव कमेटी में भी कहा कि दो या ढाई बजे कोई एक्सप्रेस ट्रेन हरद्वार के लिए होनी चाहिए लेकिन वह आज तक नहीं हो सका ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह अलग बात है ।

श्री यशपाल सिंह : गुंटकल बहुत इम्पारटेंट प्लेस है, यह आयरन ओर का सब से बड़ा सेंटर है और इसकी तरक्की के लिए ब्राडगेज बनाने की पूरी कोशिश होनी चाहिए । साथ ही साथ जो पिछड़े हुए इलाके हैं उनके लिए भी पूरी कोशिश होनी चाहिए ।

---

†मूल अंग्रेजी में

यह डिमांड इतनी इम्पोर्टेंट है कि इस में किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए । और इस को पास कर देना चाहिए ।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया** (अडोनी) : छोटे छोटे टुकड़ों पर बड़ी लाइनें बनाने से कोई लाभ नहीं होगा । एक विशाल योजना बनाई जानी चाहिए और मारमागाओ को विकसित करना चाहिये और रास्तों को बड़ी लाइनों में परिवर्तित करना चाहिये ।

मध्य और दक्षिण रेलवे को तोड़ कर एक नया रेलवे खंड बनाना चाहिये ताकि भीड़ को और काम के भार को कम किया जा सके ।

†**श्री मुथिया** (तिरूनेलवेली) : तिरूनेलवेली–कन्या कुमारी परियोजना बहुत समय से लम्बित है । किसी न किसी कारण इसे स्थगित कर दिया जाता है । खेद है कि इसे तीसरी योजना में भी सम्मिलित नहीं किया गया । यदि यह लाइन बना दी जाये, तो हजारों लोगों को लाभ होगा और उद्योग स्थापित करने में सहायता मिलेगी ।

मीलाविटन–ट्यूटीकोरिन हार्बर लाइन के काम में विलम्ब किया जा रहा है । इस का निर्माण कार्य तुरन्त हाथ में लिया जाना चाहिए ।

श्री ओंकार लाल बेरवा (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं रेल मंत्री को धन्यवाद देता हूं कि उन्हों ने रेलवेज़ में तरक्की की है और काफ़ी जगहों पर नई रेलवे लाइनें निकाली हैं । लेकिन मुझे यह खेद के साथ कहना पड़ता है कि उन का ध्यान राजस्थान की तरफ़ बिलकुल नहीं है । पिछले १५ साल से जब से कांग्रेस गवर्नमेंट बनी है .

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह रेलवे पर सामान्य चर्चा नहीं है ।

श्री ओंकार लाल बेरवा : मैं डिमांड नम्बर १५ पर बोल रहा हूं जोकि नई रेलवे लाइंस बनाने के बारे में है ।

राजस्थान के अंदर रेल मंत्री महोदय ने नई लाइनें बिलकुल नहीं बनाईं अलबत्ता कुछ थोड़ा हनुमानगढ़ की तरफ़ लाइन बिछाई गई है । करोड़ों रुपये की सैंक्शन लेते हैं । मैं चाहता हूं कि उधर राजस्थान की तरफ़ भी कृपादृष्टि की जाय । इस बारे में राज्यपाल को भी हम ने एक आवेदन पत्र दिया था और मैं पुनः वह मांग सदन में दुहराना चाहूंगा कि कोटा से बूंदी, बंदी से देवली और देवली से नसीराबाद को रेल के जरिए मिला दिया जाय या देवली से टोंक और निवाई को रेल से मिला दिया जाय ।

अगर इस देश में सरकार वाकई समाजवादी समाज की व्यवस्था क़ायम करना चाहती है तो यह बहुत आवश्यक है कि इन पिछड़े हुए इलाकों की तरफ ध्यान दिया जाय और उन का विकास किया जाय । उन में नई रेलवे लाइनें बिछाई जायें । उन पिछड़े और अनुन्नत इलाकों की हमें तरक्की करनी होगी । ज़ाहिर है कि जब तक उन के अंदर नई लाइनें नहीं निकालेंगे तब तक उन का विकास नहीं होगा । उन में रेलवे लाइंस बिछाने से उन का शीघ्र विकास होगा । यह पिछड़ा इलाका राजस्थान का ऐसा है जहां पर रेलवे लाइनों का होना बहुत ज़रूरी है । इस बारे में राज्यपाल को भी हम ने एक ऐप्लीकेशन दी थी । उन्हों ने इसे मंजूर किया था और वायदा किया था कि हां वे इस के लिए रेल मंत्री जी से कहेंगे । अब पता नहीं उन्हों ने क्या कहा और क्या नहीं कहा । बहरहाल मैं चाहूंगा कि रेल मंत्री महोदय इस के ऊपर ध्यान दें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ओंकार लाल बेरवा]

दूसरी बात यह है कि हमारे कोटा स्टेशन पर बजरिया पर एक नाला है और जैसा झगड़ा यहां पर यमुना पुल को ले कर कारपोरेशन और रेलवे विभाग के बीच में चल रहा है जिस से यमुना पुल बीच में लटक रहा है इसी तरह का झगड़ा उस नाले को ले कर भी रेलवेज़ और हमारे निगम के बीच में चल रहा है और परिणामस्वरूप वह नाला पड़ा सड़ रहा है। रेलवे कहती है कि वह स्टेट का है और स्टेट कहती है कि वह रेलवे का है। ज़रूरत इस बात की है कि जैसे भी हो उस का फैसला किया जाय ताकि नाले को बना दिया जाय और ठीक कर दिया जाय और वह गंदगी मिट सके। इस से बजरिया की रौनक हो जायगी।

एक दिन मैंने अपने रेलवे स्टेशन के क्षेत्र का दौरा किया। मैं ने देखा कि एक एक मास्टर से ६०, ६० या १००, १०० लड़के पढ़ रहे हैं।

इन स्कूलों में आम ग़रीब लगों के बच्चे पढ़ते हैं। बड़े बड़े अफ़सरों के लड़के उन स्कूलों में नहीं पढ़ते हैं। उन के लिए ईसाईयों का एक नया स्कूल खुला है, उस का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उस स्कूल में बड़े बड़े आदमियों के लड़के पढ़ने जाते हैं। लेकिन गरीब मज़दूरों और दूसरे लोगों के लड़के उन स्कूलों में पढ़ते हैं जिस में एक, एक मास्टर के पास १००, १०० लड़के पढ़ते हैं। वहां पर लड़कों के बैठने के लिए टाट पट्टी आदि का भी इंतज़ाम नहीं है। चारों तरफ़ जंगल झाड़ियां काफ़ी बढ़ी हुई हैं। उन की सफ़ाई आदि के लिए कोई माली की व्यवस्था भी नहीं की गई है।

मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इस इलाक़े की तरफ़ अवश्य ध्यान दें।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इस बात का मांग से कोई संबंध नहीं है।

श्री ओंकार लाल बेरवा : मेरा निवेदन है कि बहुत सा रुपया मंजूर किया गया है और मैं चाहूंगा कि राजस्थान की जो अभी तक उपेक्षा की गई है, उस की ओर अवश्य ध्यान होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : वह अलग बात है।

†**डा० गायतोंडे** (गोआ, दमन और दीव) : मुझे यह जान कर प्रसन्नता है कि मर्मगाओ बन्दरगाह तक बड़ी लाइन बनाने का विचार किया जा रहा है। मैं ने इस लाइन की दिशा परिवर्तन करने का सुझाव दिया था। इस संबंध में सरकार ने कहा है कि यदि निर्णय होगा तो ऐसा किया जायेगा।

ज्ञात हुआ है कि इस सम्बन्ध में सर्वेक्षण किया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सर्वेक्षण बड़ी लाइन के मार्ग के लिए किया जा रहा है या पटान की क्षमता का पता लगाने के लिये किया जा रहा है वस्तुतः जब यह निश्चय हो गया है कि बड़ी लाइन का निर्माण किया जाना है तो अब केवल यही देखना है कि यह लाइन किस मार्ग से जायेगी।

श्री शिवमूर्ति स्वामी (कोप्पल) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी यहां पर जो २,५०,००० रुपये का सप्लीमेंटरी बजट पेश किया गया है, उस में दो दिमांड्ज़ हैं। एक डिमांड में तो साउथ बंगाल को नार्थ बंगाल और आसाम से जोड़ने के लिये ब्राड-गेज लाइन की एक बड़ी प्राजक्ट की व्यवस्था की गई है। इसके लिये मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूं और कहना चाहता हूं कि इस काम को जल्द से जल्द आगे बढ़ा कर साउथ बंगाल और नार्थ बंगाल तथा आसाम के बीच में यातायात का जल्दी इन्त-

†मूल अंग्रेजी में

जाम किया जाये। इस डिमांड में केवल एक लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। लिहाज़ा अगर और ज्यादा रुपये की आवश्यकता हो, तो वह लेकर इस काम को जल्दी ख़त्म किया जाये।

जहां तक दूसरी डिमांड का सवाल है, माननीय सदस्य, श्री बैंकटासुब्बया, ने कहा कि मर्मगोआ के बारे में स्टडी किया जाये कि वहां पर कोई पासिबिलिटीज़ हैं या नहीं। यह सुन कर मुझे ताज्जुब होता है। १९६३ तक इस एरिया में सिर्फ छोटी लाइन पर ही रेलवे चलती है। आज़ाद होने के बाद इन पन्द्रह सालों में जब भी कोई मंत्री महोदय वहां जाते हैं, तो लोगों की तरफ़ से यह मांग की जाती है कि वहां पर ब्राड-गेज लाइन बिछाई जाये। हाल ही में हमारे मंत्री महोदय, सरदार स्वर्ण सिंह, ने खुद गुजस्ता महीने खुद पांच दिन तक इस विभाग का दौरा किया। उनको महसूस हुआ होगा कि सिर्फ हास्पेट तक या मिरज तक ब्राड-गेज करना मुल्क के लिए या इकोनामिक दृष्टिकोण से ठीक नहीं होगा। जब तक हास्पेट से हुबली और लौंडा तक हम ब्राडगेज लाइन नहीं बनायेंगे, जब तक पूना, मिरज और हुबली को ब्राड-गेज से नहीं मिलायेंगे--जब तक गुंटकल से पूना तक बाया हुबली ब्राड-गेज नहीं होगा, उस वक्त तक इस एरिया में पैदा होने वाला आयरन ओर, मैंगानीज ओर और फूड ग्रैंज़ का ले जाना बहुत कठिन है। वहां पर एक तरफ तो मद्रास बन्दरगाह है और दूसरी तरफ़ बम्बई है और उन दोनों के बीच में हजारों मील का समुद्र का किनारा है, जहां पर कोई बड़ी बन्दरगाह नहीं है। हालांकि मंगलौर और मर्मगोआ को मेजर पोर्ट में तब्दील करना ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ वहां पर ब्राड-गेज को शुरू करने का प्रयत्न करना चाहिए। मुझे यह देख कर अफसोस होता है कि अभी वहां पर सिर्फ प्रिलिमिनरी सरवे हो रहा है। इस में लिखा है :--

"मीराज से मर्मगाओ तक की मीटर लाइन तथा मीराज से कोल्हापुर तक को बड़ी लाइन में बदलने के लिये"

इससे मालूम होता है कि पूना से सिर्फ़ मिरज तक अब फ़ाइनल सेटलमेंट हो गया है और वह चन्द दिनों में होने वाला है। इसका जल्द से जल्द सरवे कर के मिरज से हुबली तक ब्राडगेज बिछाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहां के मिनेरल्ज़ को ले जाने के लिए हुबली से बहुत कुछ सहूलियत हो सकती है। इसमें लिखा है :--"कि होसपेट लोंडो मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में तथा इसे गुंटकल से होसपेट की बड़ी लाइन से मिलाने के लिये" गुंटकल से हास्पेट तक और फिर लोंडा तक ले जाने का काम तेज़ी से शुरू करना चाहिए। मेरा निवेदन यह है कि तीन पंच-वर्षीय योजनाओं के बाद भी वहां पर एक माइल भी रेलवे लाइन नहीं डाली गई है। हसन-मंगलौर लाइन भी बहुत ज़रूरी हैं। कोटूर से हरपनली, हड़गली और हरिहर या हावेरी लाइन की योजना भी बहुत महत्वपूर्ण है। वहां पर फ़ाइनल लोकेशन का सरवे हो चुका है। हसन-मंगलौर का भी सरवे हो चुका है हालांकि यह सरवे १९५२ में हो चुका है और बजट में दिखाया जाता है, जिसको देख कर बड़ा आनन्द होता है, लेकिन चूंकि वहां पर काम शुरू नहीं हुआ, इस लिए दुख होता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरवे के लिए जो पैसा दिया जाता है, उस को काम में लाकर कम से कम एक माइल नई रेलवे लाइन तो बना कर दिखाई जाये। एक भी काम वहां नहीं हो रहा है। अब सुनने में आ रहा है कि मंगलौर बन्दरगाह के लिए जो सिर्फ़ पांच लाख रुपया दिया गया है, उस के बारे में यह कहा गया है कि चूंकि गोआ बढ़ रहा है, इसलिए मंगलौर को हम कम करेंगे। कहां गोआ और कहां मंगलौर। मर्मगोआ एक अलग परपज़ के लिए होगा, लेकिन उस क्षेत्र से मिनरल्ज़ आदि कम एक्सपेंस पर भेजने के लिए मंगलौर उपयुक्त होगा। मर्मगोआ की तरफ का जो आयरन ओर है, वह अलग है। वेलारी और हास्पेट मंगलौर के नजदीक हैं। उसके लिए कोटूर और हरिहर को मिलाना जरूरी है।

माननीय मंत्री जी खुद उस क्षेत्र को देख कर आये हैं। अब तक जो अन्याय वहां पर हुआ है कि एक माइल भी रेलवे लाइन वहां पर नहीं बनाई गई है, उस को देख कर यह काम जल्द से जल्द

[श्री शिवमूर्ति स्वामी]

करना ज़रूरी है। निजाम सरकार और मैसूर स्टेट ने भी उस वक्त सरवे किया था। वहां पर रायचर, गंगावती और कोप्पल को मिलाना बहुत ज़रूरी है, जिस के बीच में तुंगभद्रा का डेवेलप्ड एरिया है। वहां पर फाइनल लोकेशन की रिपोर्टस् मौजूद हैं, लेकिन फिर भी वहां पर काम नहीं हुआ। जिन कामों के सरवे हो चुके हैं, उनको एक एक करके हाथ में लेकर पूरा किया जाये, वर्ना बहुत अन्याय होगा। पूरी तरह स्टडी कर के फूडग्रेन्ज़ और आयरन ओर के लिए मर्मगोआ को इसमें शरीक किया गया है। मंत्री महोदय कोई अजनबी की तरह से उसको नहीं लाए हैं। मुझे मालूम नहीं कि श्री वैंकटासुब्बया यह क्यों कहते हैं कि यह हैफ़ज़र्ड प्लान है। यह कोई हैफ़ज़र्ड प्लान नहीं है, बल्कि यह एक बहुत अच्छी प्लान है और इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाये।

†**श्री जो० ना० हजारिका** (डिब्रूगढ़) : मैं इन अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। मैं आसाम में बड़ी लाइन की परियोजना का स्वागत करता हूं तथापि इस कार्य में जिस तेजी से प्रगति होनी चाहिये थी उतनी तेजी से यह प्रगति नहीं हो रही है।

सरकार को चाहिये कि वे रात्रि में रेलगाड़ियां चलायें। दुख की बात है कि अभी भी रात की गाड़ियां चलनी शुरू नहीं हुई हैं। रेलवे बोर्ड को चाहिये कि वे इस मामले में आसाम सरकार से बातचीत करे तथा रेलवे लाइन के निकट लोगों को बसाने में प्रोत्साहित करे।

डीमापुर और नागा क्षेत्र को मिलाने वाली लाइन के साथ साथ नवगांव तथा अन्य क्षेत्रों से गुजरने वाली एक अन्य लाइन बनायी जाये। यह वैकल्पिक लाइन सिद्ध होगी तथा बहुत लाभदायक रहेगी।

मैं एक अन्य बात भी कहना चाहता हूं वह यह है कि टलाय से ढोला तक रेलवे लाइन बढ़ा दी जाये।

श्रीमती शशांक मंजरी (पालामऊ) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं रेलवे के बारे में कुछ कहना चाहती हूं। पहले ऐसा हुआ करता था कि बड़साखाना से जो रेल जाती थी वह मुहरी और टाटा होकर सीधे कलकत्ता जाती थी लेकिन अब मुहरी में कट जाती है। वहां दो दो दिन मुसाफिरों को ठहरना पड़ता है। रांची से जो रेल आती है, उसमें मुहरी वालों को बैठ कर कलकत्ता जाना पड़ता है वह गाड़ी रांची से ही बड़ी भरी हुई आती है और मुहरी के मुसाफिरों को उसमें बैठने का मौका नहीं मिलता है और बैठने की बात तो दूर खड़े हो कर भी वे जा नहीं पाते हैं। इस तरह से मुसाफिरों को बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। उनको एक एक और दो दो दिन वहां रुकना पड़ता है। इसलिए मैं चाहती हूं कि हजारीबाग और रामगढ़ वालों को सुविधा दी जाये। जिस तरह से इनको पहले बिना रुके हुए सीधे कलकत्ता जाते थे। मैं आशा करती हूं कि रेल मंत्री महोदय इस ओर तुरन्त ध्यान देंगे।

अभी मैं रेल की यात्रा करके आ रही हूं और मैंने थर्ड क्लास के पैसेंजरों की तकलीफों को देखा है। इन डिब्बों में बड़ी भीड़ होती है। इतनी भीड़ होती है कि अन्दर वाले आदमी बाहर नहीं जा सकते हैं और बाहर वाले आदमी अन्दर नहीं जा सकते हैं। भीड़ के कारण लड़ाई झगड़े बहुत हो जाते हैं। मारपीट में किसी का सिर तोड़ दिया जाता है, किसी की नाक टूट जाती है, किसी की नाक छिल जाती है और किसी को कहीं और चोट आ जाती है। जिस घटना का मैं जिक्र कर रही हूं, उस में दो दो बार इस भीड़ की वजह से गाड़ी को रुकना पड़ा। यह जो तीसरे दर्जे में भीड़भाड़ होती है और मुसाफिरों को सुविधा नहीं होती है, इस ओर आपका विशेष ध्यान जाना

†मूल अंग्रेजी में

चाहिये । बैठने की बात तो दूर खड़ा होने तक को स्थान नहीं मिलता है और रेल पकड़ कर भी वे जाना चाहें तो नहीं जा सकते हैं ।

अब खाना जो दिया जाता है, उसके बारे में मेरा कहना यह है कि वह बहुत गन्दा होता है, उसमें माछी वगैरह होती है और इस मैले और गन्दे खाने को खाने से लोगों के बीमार हो जाने का डर रहता है । चीजों की सफाई बिल्कुल नहीं होती है । जब आप पैसा पूरा लेते हैं, पूरा रुपया लेते हैं तो सफाई का तो आपको ध्यान रखना चाहिये, सफाई तो ठीक तरह से होनी चाहिये । जहां वह बनता है, वह स्थान भी बड़ा गन्दा होता है और जहां वह दिया जाता है वह भी बहुत खराब जगह होती है । इसका भी आपको खयाल करना चाहिये ।

रास्ते में जो भोजन आदि दिया जाता है, वह भी बहुत गन्दा होता है, बहुत मैला होता है और माछी वगैरह के हाथ डालने से वह और भी गन्दा हो जाता है । इस तरह का मैला और गन्दा खाना खाने से बीमारी हो जाने का डर रहता है । इस ओर विशेष रूप से आपका ध्यान जाना चाहिये ।

†**श्री सोनावने** (पंढरपुर): रेलवे मंत्रालय ने अनुदानों की मांगों पर जो प्राक्कलन और व्याख्यात्मक टिप्पण दिये हैं उनसे यह ज्ञात होता है कि रेलवे मंत्रालय अपने कार्यों के निर्णय और संचालन में ढुलमुल नीति अपना रहा है । उन्होंने स्वयं लिखा है कि अप्रैल के पश्चात् सारे मामले पर पुनर्विचार करना पड़ा ।

दूसरी अनुपूरक मांग सर्वेक्षण के सम्बन्ध में है । रेलवे मंत्रालय कई बार सर्वेक्षण करती है लेकिन वे सब यों ही छोड़ दिये जाते हैं । उन पर कोई कार्यवाही नहीं होती है । कई बार यह मांग की गई थी कि पंढरपुर की नैरो गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदल दिया जाये लेकिन इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं हुई है ।

मैं इस सम्बन्ध में श्री शाहनवाज खां का ध्यान दिलाना चाहता हूं । उन्होंने मेरे क्षेत्र का दौरा किया था मैं इस सम्बन्ध में उनसे केवल यही अनुरोध करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र की नैरो गेज लाइन को बड़ी लाइन बना दिया जाये । मैं आशा करता हूं कि रेलवे मंत्री मेरे निर्वाचन क्षेत्र के निवासियों की महत्वाकांक्षायें पूरी करेंगे ।

†**श्री प्रिय गुप्त** (कटिहार) : मुझे अत्यधिक दुख से यह कहना है कि रेलवे बजट पर चर्चा के दौरान हमने जो भी बातें कही थीं उन पर ध्यान नहीं दिया गया और न ही उनका उत्तर ही दिया गया । मैं चाहता हूं कि रेलवे बजट पर भी उसी प्रकार मतदान लिया जाये जिस प्रकार सामान्य बजट में मतदान लिया जाता है ।

रेलवे मंत्रालय सर्वेक्षण करने में जिस प्रकार व्यय करती है उस प्रकार अपव्यय नहीं किया जाना चाहिये । आसाम में यातायात के सुधार के लिये एक लाख रुपये से भी अधिक कीमत का एक केबिन बनाया जा रहा था उस का आज तक कोई उपयोग नहीं किया गया ।

ब्रह्मपुत्र नदी पर पुल को यातायात के लिये खोलने पर काफी त्रुटियों का अनुभव हुआ । अब वहां पर मालगाड़ियों इत्यादि दुहरे कर्मचारी पद्धति से चलती हैं । इस पद्धति का परिणाम यह हुआ है कि ड्राइवर और फायरमैन इत्यादि को विश्राम नहीं मिलता है । इसके साथ साथ इससे बहुत आर्थिक हानि भी हो रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री प्रिय गुप्त]

रेलवे के पास दो प्रकार के डीजल इंजिन हैं। ये लांग हूड और शार्ट हूड प्रणाली से चलते हैं। इससे ड्राइवर के फेफड़ों पर घातक प्रभाव होता है रेलवे मंत्रालय को चाहिये कि वे ऐसे साधन अपनाये कि ड्राइवरों के स्वास्थ्य में हानि न हो।

अभी हाल कटिहार में दुर्घटना समिति की बैठक हुई थी। समिति के सदस्य वहां कुछ ही घंटों के लिये आये थे किन्तु इतनी देर के लिये वहां आफिस से एयर कंडिशन हटा कर लगाये गये। मेरे विचार से इस प्रकार का अपव्यय अनुचित है।

अन्त में मेरा सुझाव है कि जब घोषित पदाधिकारियों को आपातकाल के दौरान काम करने के लिये तीन तीन वेतन वृद्धियां मिली हैं तो ये वेतन वृद्धियां तृतीय एवं चतुर्थ कर्मचारियों की भी होनी चाहिये।

†**श्री पाराशर** (शिवपुरी) : मुझे अभी हाल दक्षिण रेलवे में यात्रा करने का अवसर मिला है। वहां तीन टायर वाले डिब्बों में टायरों की लम्बाई तथा उन के बीच इतनी कम जगह है कि आदमी बहुत कठिनता से ही सो सकता है।

जहां तक सीमान्त रेलों का प्रश्न है, मेरा सुझाव है कि उन्हें आन्तरिकों रेलों से अच्छी तरह सम्बन्धित रहना चाहिये। मेरा सुझाव यह है कि उड़ीसा और आसाम को बंगाल और बिहार से मिलाने वाली लाइनें बनायी जायें जो उत्तर प्रदेश और पंजाब को भी मिला दें।

श्री भू० ना० मंडल (सहरसा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं डिमांड नम्बर २ के सर्वे पोरशन पर बोलना चाहता हूं। जो डिमांड हाउस के सामने पेश की गयी है उस में सिर्फ सदर्न रेलवे और ईस्टर्न रेलवे का जिक्र है। मेरा यह ग्रीवान्स है कि एन० ई० रेलवे के सम्बन्ध में भी सर्वे होना चाहिए था और उसके बारे में भी सप्लीमेंटरी डिमांड होनी चाहिए थी। मेरी कांस्टीट्यूएंसी सहरसा है, जो कि बिहार का पिछड़ा हुआ इलाका है। वहां यातायात की सुविधा की बहुत जरूरत है। जो रेलवे लाइन कोसी के जमाने में खत्म हो चुकी है उसके बारे में कहा गया है कि वह रेस्टोर हो लेकिन वह अभी तक रेस्टोर नहीं हुई। मेरा सजेशन है कि यह लाइन सपोल से भवटियाही और राघवपुर होते हुए फारबिसगंज से मिला दी जाये। यह बहुत जरूरी है। यह इलाका डालर अर्निंग इलाका है और नेपाल की सीमा के पास होने से भी महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस लाइन पर खास तौर से ध्यान दिया जाये और इसको रेस्टोर किया जाये।

†**श्री कृ० ल० मोरे** (हथकंगले) : मैं रेलवे मंत्रालय की अनुदानों का समर्थन करता हूं। मैं मीराज कोल्हापुर लाइन को इस में शामिल करने के लिये आप को बधाई देता हूं। यह लाइन इस समय छोटी लाइन है किन्तु मैंने उसे बड़ी लाइन बनाने के लिये मंत्री महोदय से सिफारिश की थी, मुझे प्रसन्नता है कि यह लाइन योजना में शामिल कर ली गयी।

श्री कछवाय (देवास) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसका स्वागत करते हुए यह कहना चाहता हूं कि जो किराया बढ़ाया गया है उसके अनुसार तीसरे दर्जे के मुसाफिरों को सहूलियत मिलनी चाहिए

उपाध्यक्ष महोदय : यह थर्ड क्लास की सहूलियत के लिए नहीं है। य आसाम और सदर्न रेलवे के एक्सटेंशन और सर्वे के लिए है। उसके बारे में कुछ कहना हो तो कहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री कछवाय : मैं वैस्टर्न रेलवे के बारे में कहना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : वैस्टर्न रेलवे इसमें नहीं आता ।

श्री कछवाय : असम क्षेत्र के रेलवे के सम्बन्ध में भी मुझे यह कहना है कि जो किराया बढ़ाया गया है उस क्षेत्र में, उसके अनुसार जो थर्ड क्लास के यात्रियों को सहूलियत मिलनी चाहिए वह नहीं मिलती है । इसका कारण या तो यह है कि डिब्बे कम हैं या ठीक व्यवस्था नहीं है इस कारण उनको सहूलियतें नहीं मिल पातीं । अधिकांश में देखा गया है कि इस रेलवे पर गरीबों की जेबें कट जाती हैं और इस काम में अधिकांश रेलवे कर्मचारियों का हाथ होता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह अलग बात है । यह इसमें नहीं आती । यह सर्वे के लिए है । उसके बारे में कहना हो तो कहिये नहीं तो बैठ जायें ।

†**श्री शाहनवाज खां :** मैं उन सभी माननीय सदस्यों का कृतज्ञ हूं जिन्होंने चर्चा में भाग लिया तथा इन मांगों का समर्थन किया । जो बातें यहां उठायी गयी हैं मैं उनका उत्तर देने का भरसक प्रयत्न करूंगा ।

श्री नम्बियार ने ऐजन्सी को फिर से शुरू करने के बारे में कहा था । मैं इस प्रश्न पर पुनर्विचार करूंगा और यदि आवश्यक होगा तो उसे फिर से शुरू की जायेगी ।

जहां तक ताम्बरम्-विलुपुरम लाइन का प्रश्न है, कार्य शीघ्रता से चल रहा है और जैसे ही जापान से इंजिन आ जायेंगे यह लाइन खोल दी जायेगी । जहां तक विरुदाचलम तक बिजली से रेलें चलाने का प्रश्न है, यदि यातायात को देखते हुए उस क्षेत्र में इसकी आवश्यकता अनुभव की गयी तो उस लाइन में भी बिजली से गाड़ियां चलाई जायेंगी ।

जहां तक जोलरपेट से शोरनपुर जाने वाली लाइन का प्रश्न है उसे दुहरी बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि फिलहाल लाइन में काफी क्षमता है । कुछ माननीय सदस्यों ने मध्य तथा दक्षिण रेलवे को पृथक करने की मांग की है । मांग नयी नहीं है । तथापि रेलवे में खंड कार्य-प्रवर्तन की सुविधा से बनाये गये हैं । अतः नये खंड बनाने की आवश्यकता नहीं है । यदि भविष्य में कार्य-प्रवर्तन की दृष्टि से इसके दो खंड बनाने आवश्यक समझे गये तो ऐसा कर दिया जायेगा ।

जहां तक एस० एस० लाइट रेलवे का प्रश्न है उसे अभी बड़ी लाइन बनाने का कोई विचार नहीं है ।

कुछ सदस्यों ने हमारे "यदि उपयुक्त समझा जायेगा तो रेलवे लाइन को मीटर लाइन से बड़ी लाइन में बदल दिया जायेगा" वस्तुतः सर्वेक्षण के पश्चात् ही हमें यह ज्ञात होता है कि इस में कितना व्यय होगा तथा कितनी आय होगी । इन्हीं नतीजों के आधार पर हम अन्तिम निर्णय में पहुंचते हैं । मर्मागाओ पत्तन के विकास से कई मंत्रालय सम्बन्धित हैं । मंत्रालय आपस में परामर्श कर रहे हैं । कार्य सर्वेक्षण का कार्य समाप्त होते ही तत्काल निर्णय कर लिया जायेगा ।

तिन्नेवली-कन्या कुमारी सर्वेक्षण बजट में शामिल है तथा कार्य चल रहा है ।

आसाम तक बड़ी लाइन बनाने का कार्य पूरी तेजी से चल रहा है । आसाम सरकार से रेलवे लाइन के दोनों ओर जंगल साफ कर उनमें लोगों को बसाने पर विचार किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री शाहनवाज़ खां]

अभी लातूर से मिराज रेलवे लाइन बनाने का कोई विचार नहीं है यदि बाद में ऐसा करना आवश्यक होगा तो हम विचार करेंगे ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या कटौती प्रस्तावों पर आग्रह किया जा रहा है ?

†**श्री प्रभात कार** : जी नहीं ।

कटौती प्रस्ताव सभा की अनुमति से वापस लिये गये ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष १९६३–६४ के लिये (रेलवे) के सम्बन्ध में अनुदानों की अनुपूरक मांगें मतदान के लिये रखी गयीं तथा स्वीकृत हुईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
२	विविध व्यय . . .	१,५०,०००
१५	चालू लाइनों का निर्माण—बढ़ाना तथा बदलना . .	१,००,०००

भांडागार निगम (संशोधन) विधेयक

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"भांडागार निगम अधिनियम, १९६२ में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

१९६२ के अधिनियम की धारा ३ उपधारा (२) तथा उस अधिनियम द्वारा जो १९६२ के अधिनियम से संशोधित किया गया था, केन्द्रीय भांडागार निगम का मुख्य कार्यालय दिल्ली में रहता था । इस निगम के मुख्य कार्यालय के दिल्ली से बाहर जाने पर प्रतिबंध लगता है । यह त्रुटि में तब ज्ञात हुई जब कि दिल्ली से कुछ कार्यालयों के बाहर जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव रखा गया तथा दिल्ली से कार्यालयों को बाहर भेजने की व्यापक योजना बनी ।

श्री स० मो० बनर्जी ने यह प्रश्न पूछा था कि क्या सरकार ने इस कार्यालय को बाहर भेजने का निश्चय कर लिया है यदि हां तो कहां । वस्तुतः यह केवल समर्थकारी अधिनियम है । जिससे कि यदि सरकार कोई निर्णय करे तो संविहित उपबंध उसमें आड़े न आयें । अतः विधेयक में केवल यही उपबंध किया गया है कि भांडागार निगम को केन्द्रीय कार्यालय दिल्ली में, अथवा किसी ऐसे स्थान पर रहेगा जहां सरकार अधिसूचना द्वारा रखने को निश्चित करे । संशोधन द्वारा केवल इस बात को रखने का उपबंध किया गया है ।

मुख्य कार्यालय को भेजने के लिये दो स्थानों का सुझाव दिया गया है । एक फरीदाबाद और दूसरे आगरा । मंत्रालय का विचार है कि इसे फरीदाबाद में शिफ्ट किया जाये । फरीदाबाद में केन्द्रीय सरकार की जमीन है तथा वहां निगम की अपनी इमारत बन सकती है । इस समय कार्यालय के पास ५२८० वर्ग फीट स्थान है तथा १०० कर्मचारी वहां काम करते हैं जिसका किराया हम २६०० रु० दे रहे हैं । मैं आशा करता हूं कि सभी सदस्य इस संशोधन विधेयक का समर्थन करेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री प्रभात कार** (हुगली) : इस विधेयक का उद्देश्य य उपबंध करना है कि केन्द्रीय भांडागार निगम का कार्यालय दिल्ली के बाहर भी किसी ऐसे स्थान पर हो सके, जिसे केन्द्रीय सरकार गजट में अधिसूचना निकाल कर विनिर्दिष्ट करे । इस सम्बन्ध में मैं आपको निम्नलिखित सुझाव देना चाहता हूं ।

भांडागार निगम का कार्य खाद्य तथा कृषि मंत्रालय से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित है । हमें य चाहिये कि हम भांडागारों को ऐसे स्थानों में स्थापित करें जहां कि खाद्यान्नों या नकद फसलों का उत्पादन होता हो । वस्तुतः तभी हम किसानों की सहायता कर सकेंगे क्योंकि किसानों को बिचौलियों व दलालों से काफी हानि उठानी पड़ी है । गांवों के निकट और अधिक भांडागार बनाये जायें ।

भांडागार निगम का कार्य संतोषजनक नहीं रहा है । इसका कारण यह है कि खाद्य तथा कृषि मंत्रालय उसे स्पष्ट निर्देश नहीं दे सका । जहां तक केन्द्रीय कार्यालय का प्रश्न है उसे खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के निकट ही रहना चाहिये ।

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस बिल का ताल्लुक है, मैं इसका समर्थन करता हूं । मैं ने पिछले साल भी यह बात कही थी कि जितने आफ़िसिज़ और मकानात शहरों में बनाये जायेंगे, देहात उतने ही ज्यादा उजड़ते जायेंगे । दिल्ली आज इतना कन्जस्टिड हो चुका है कि यहां पर और गुंजायश नहीं है । इसलिए इन आफ़िसिज़ को बाहर ले जाना बहुत मुनासिब है, लेकिन, जैसा कि मैं ने अपनी एमेंडमेंट में कहा है, इन आफ़िसिज़ के स्टाफ़ को कम से कम छः महीने का नोटिस देना चाहिए, जिससे वे अपने बाल-बच्चों का और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों का उचित इन्तज़ाम कर सकें ।

सारी दुनिया में यह अकेली सरकार है, जो नौकरी दे देती है, लेकिन मकानात की कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेती है । अभी उस दिन निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री ने कहा था कि दिल्ली में ५४,००० ऐसे गवर्नमेंट सरवेंट्स हैं, जिनको सरकार मकानात नहीं दे सकी है । उनकी बड़ी डिफीकल्टी है । इसलिए जब आफ़िसिज़ यहां से उठाये जाते हैं, तो उनमें काम करने वाले कर्मचारियों को कम से कम छः मास का नोटिस देना चाहिए । उन कर्मचारियों को एकदम शिफ्ट करना उनके स्वास्थ्य और घर के इन्तज़ाम के लिए घातक होगा ।

इसलिए मेरा निवेदन है कि इस संशोधन को स्वीकार करके, इस बिल को पास किया जाये । मैं इस बिल का स्वागत करता हूं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : सरकार ने इस कार्यालय को स्थानान्तरित करने का निश्चय कर लिया । इसमें कुल १२२ व्यक्ति काम करते हैं जिनमें ११ अन्य कार्यालयों से हैं । फरीदाबाद में स्थानान्तरित करने की बात समझ में आ सकती है क्योंकि वहां बस का सीधा मार्ग है । किन्तु इससे और जटिल स्थिति पैदा होगी, क्योंकि ये कर्मचारी जो दिल्ली में काम करते हैं प्रतिकर भत्ते की खातिर फरीदाबाद को ए श्रेणी का नगर बनाना चाहिये जो कि हो नहीं सकता क्यों कि फरीदाबाद पंजाब में है ।

मेरे संशोधन का उद्देश्य यह है कि जिस कार्यालय को स्थानान्तरित करना हो उसके कर्मचारियों को छै मास पूर्व सूचना देनी चाहिये और उनके कुल वेतन की रक्षा होनी चाहिये तथा उन्हें आवास मिलना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री स० मो० बनर्जी]

जब हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के कार्यालय को रांची से स्थानान्तरित किया गया था तो कर्मचारियों के साथ परामर्श कर के १० प्रतिशत विस्थापन भत्ता आदि और अन्य रियायतें भी दी गई थीं ।

मेरी समझ में नहीं आता कि निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय ने जिन कार्यालयों के स्थानान्तरण की बात कही है उनके २००० लोगों के चले जाने से दिल्ली साफ हो जायेगा । कार्यालय को जहां भी ले जाया जायेगा वहां भवन का निर्माण भी करना होगा और क्या आपातकाल में इतना खर्च करना उचित है । मुझे आशा नहीं कि इन परिवारों के लिये आवास की भी व्यवस्था की जायेगी । यह बहुत आश्चर्य की बात है कि जो कार्मचारी इस निगम के मुख्यालय में काम कर रहे हैं उन पर तो वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होती हैं किन्तु राज्य में काम करने वाले निगम के क्षेत्रीय आधिकारियों पर यह नहीं लागू होते और यदि वे मुख्यालय में आकर काम करने लगें तो उनकी सेवा नये सिरे से आरम्भ होगी । इन लोगों को भी आयोग की सिफारिशों का लाभ प्राप्त होना चाहिये ।

आशा है मेरा संशोधन स्वीकार कर लिया जायेगा क्योंकि इससे कर्मचारियों के हितों की रक्षा होगी ।

†**श्री सोनावने** (पंढरपुर) : इस निगम की स्थापना का उद्देश्य यह था कि कृषकों को उचित मूल्य मिले । भला कार्यालय को स्थानान्तरित करने से यह उद्देश्य कैसे पूर्ण होगा । सरकार इसमें सर्वथा असफल रही है ।

भंडार ऐसे स्थानों पर अर्थात् गांवों में होने चाहिये थे जहां अनाज पैदा होता है ताकि लोगों को सुविधा रहती और उनका अनाज वहां संग्रहीत किया जा सकता । गोदाम उपयुक्त स्थानों पर नहीं बनाये गये और उनकी संख्या भी पर्याप्त नहीं है । गोदामों से लाभ भी वही लोग उठाते हैं जो कृषकों का शोषण करते हैं । इस लिये मंत्रालय ने जो संशोधन पेश किया है उससे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती । अतः मेरा निवेदन है कि सरकार इस दृष्टि से विधान में संशोधन प्रस्तुत करे ।

श्री क० ना० तिवारी : उपाध्यक्ष महोदय, जो एमेंडिंग बिल आया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । गवर्नमेंट के सारे आफिसज को दिल्ली या कलकत्ता में या और जगहों में ला कर इकट्ठा कर देने की नीति है वह अच्छी नहीं है । मेरा ख्याल है कि सिक्योरिटी के ख्याल से भी और दूसरे खयालों से भी किसी शहर को बहुत ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहिये । आफिसज को चारों तरफ अलग अलग कर के रखना ज्यादा अच्छा है । इस लिये वे अरहाउसिंग के ही नहीं बल्कि और भी जितने आफिसज हैं उन को जितना ज्यादा एक दूसरे से हटा सकें उतना हटा देना चाहिये । सारे आफिसज को एक साथ रखने से अपोजीशन जो किसानों के सवाल को लेकर बराबर इस हाउस में उठाया करता है वह भी नहीं उठेगा और छोटे छोटे जो शहर हैं, जो कि उजड़ रहे हैं वे उजड़ेंगे नहीं बल्कि उन की जो इम्पार्टेंस है वह और भी बढ़ जायेगी और वहां का व्यापार भी बढ़ जायेगा, उस की अहमियत बढ़ जायेगी । इस लिये मेरा खयाल है कि अगर गवर्नमेंट की पालिसी वेअरहाउसिंग को दिल्ली से हटा कर आगरा, नागपुर या दूसरी जगह में रखने की हो तो वह ज्यादा अच्छी हो । इसी तरह से और भी आफिसज हटा दिये जाने चाहियें ।

दूसरी बात यह है कि खर्चे का जो सवाल उठता है, यानी दिल्ली में आफिसज को रखने से जो एडीशनल पे उन को देनी पड़ेगी, इसी तरह से एकोमोडेशन का सवाल है, पानी का सवाल है, इतने

†मूल अंग्रेजी में

सारे सवाल उठ खड़े होते हैं। आगरा, कानपुर, बीकानेर, नागपुर या पटना जैसे जितने शहर हैं उन में ऐकोमोडेशन ज्यादा है। मैंने बीकानेर में देखा कि ऐसी बहुत सी बिल्डिंग्स पड़ी हुई हैं जिन में रहने वाला कोई नहीं है। वे गवर्नमेंट को भी कम किराये पर मिल सकती हैं। उनको बिल्डिंगें बनाने के लिये ऐडीशनल खर्च भी नहीं करना पड़ेगा, जो यहां पर एडीशनल पे दी जाती है एक्स्चेकर से, वह भी बचेगी। प्राविंसेज में जो कम पे मिलती है वह उन को दी जायेगी तो उस से काफी बचत रेवेन्यू में हो जायेगी।

इस लिये मेरा ख्याल है कि यह पालिसी जो है वह ज्यादा अच्छी है और सरकार को और ...जो आ...ेज हैं उन को हटाना चाहिये। वेअर ...उसेज़ को हटाने की जो बात है मैं उस को सपोर्ट करता हूं।

†**श्री प्रिय गुप्त** : भांडागार निगम का उद्देश्य तो यह था कि अनाज का संग्रह किया जाये किन्तु जिन प्रदेशों को मैं जानता हूं अर्थात् असम, बिहार और पश्चिम बंगाल वहां पटसन के पुराने गोदाम जो चूते हैं किराये पर दिये गये हैं और उन्हें इतना किराया दिया जाता है कि जिससे सरकार अपने गोदामों का निर्माण कर सकती थी। सरकारी पैसा अंधाधुंध व्यय किया जा रहा है। अब सरकार को अपने गोदाम बनाने चाहियें।

योजना के विकेन्द्रीयकरण के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि उड़ीसा, बिहार और पश्चिम बंगाल में इसके प्रादेशिक कार्यालय खोलने चाहियें।

गोदाम गांवों में खुलने, चाहिये और वितरण की उचित व्यवस्था होनी चाहिये तथा कर्मचारियों को उचित संरक्षण मिलना चाहिये।

†**श्री कृ० ल० मोरे** (हतकंगले) : इस विधेयक का उद्देश्य है कि केन्द्रीय भाण्डागार निगम को नई दिल्ली से भिन्न किसी स्थान पर ले जाना चाहिये। ऐसा केवल दफ्तरों को बाहर ले जाने की योजना को कार्यान्वित करने के लिये है।

मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

†**श्री अ० म० थामस** : वाद विवाद में संशोधक विधेयक के बारे में संगत और असंगत बातें कही गई हैं। गत वर्ष एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत किया गया जिसका परिणाम १९६२ का अधिनियम है। श्री सोनावने ने उस समय संभवतः चर्चा में रुचि नहीं ली या इस विधेयक को पढ़ा नहीं, नहीं तो वे इस प्रकार की बातें न उठाते।

केन्द्रीय भांडागार निगम का मुख्य उद्देश्य अखिल भारतीय दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर गोदाम बनाना है जबकि राज्य भांडागार निगम का उद्देश्य राज्य महत्व के केन्द्रों और मफसल क्षेत्र में भंडार स्थापित करना है। अतः दोनों की आवश्यकता है। यह बात सच नहीं कि केवल नगरों में ही गोदाम बनाये जाते हैं वास्तव में कुछ गोदाम नगरों और व्यापारिक केन्द्रों में इस लिये खोलने है कि व्यापार भी हो सके और कृषकों की दृष्टि से अनाज का वितरण भी हो सके। अतः हमें व्यापारियों का नहीं बल्कि किसानों के हितों का ध्यान है।

श्री प्रभात कार ने इस सम्बन्ध में बहुत संगत बात उठाई है कि केन्द्रीय भाण्डागार निगम के कार्यालय को स्थानान्तरित करना कहां तक उचित है क्योंकि यह खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का अंग है और उसे कार्य संचलन के सम्बन्ध में उपयुक्त निर्देश देने होते हैं अतः इसका वहां होना आवश्यक है जहां मंत्रालय स्थित हो। निस्संदेह निगम को सामान्य नीति के अनुसार काम करना है किन्तु इस का यह अभिप्राय नहीं कि वह मंत्रालय का अंग है। यह मंत्रालय का अधीनस्थ विभाग है, बल्कि वास्तव

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० म० थामस]

में वह स्वायत्तशासी विभाग ही है। अतः माननीय मित्र के इस तर्क में संगति नहीं है कि निगम का कार्यालय दिल्ली में ही रहना चाहिये।

श्री सा० मो० बनर्जी ने कहा है कि यह तो छोटा सा दफ्तर है और इसको स्थानान्तरित करने से थोड़े ही लोग बाहर जायेंगे। यह तो किसी भी दफ्तर के बारे में कहा जा सकता है। मंत्रालय को तो स्थानान्तरित किया नहीं जा सकता। इस सभा में कई बार निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय की इस बात पर आलोचना की गई है कि वह सरकार की नीति के अनुसार दफ्तरों को बाहर नहीं भेज रही। अतः यह स्थानान्तरण वांछनीय है। श्री के० एन० तिवारी ने ठीक ही कहा है कि जिन दफ्तरों को बाहर भेजने में लाभ है उन्हें दिल्ली में रखना उचित नहीं क्योंकि यहां भीड़ बहुत अधिक हो रही है।

श्री यशपाल ने कहा कि कर्मचारियों को कम से कम छै मास पूर्व सूचना देनी चाहिये। मेरा उत्तर यह है दफ्तरों का स्थानान्तरण तो केवल आपात काल में किया जाता है अतः सूचना देने का प्रश्न पैदा नहीं होता। अन्यथा कर्मचारियों को काफी समय पहले सूचना दी जायेगी। उदाहरणतः किसी दफ्तर को फरीदाबाद ले जाना हो तो वहां भवन बनाना होगा और सुविधाओं की व्यवस्था करनी होगी। स्वभावतः उस कार्य में श्री यश पालसिंह द्वारा प्रस्तावित समय से अधिक समय लगेगा।

श्री स० मो० बनर्जी ने श्री यशपाल सिंह के संशोधन से यह बात बढ़ा दी कि स्थानांतरण पर भी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों को सुरक्षित करना चाहिये। इस समय निगम अपने कर्मचारियों को वही वेतन और भत्ते देता है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित है। विभिन्न स्थानों पर वही वेतन भत्ते देना नियमानुसार नहीं है। निगम इस समय कर्मचारियों के लिए आवास की व्यवस्था नहीं करता। केन्द्रीय भाण्डागार निगम के कर्मचारियों के वेतन में वर्ष १९६२ में १ जुलाई, १९५९ के भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन किया गया था। केन्द्र द्वारा गोदामों में नियुक्त किये गये कर्मचारियों के वेतन में भी उसी आधार पर संशोधन किया गया था और उन्हें १ जुलाई, १९५९ से केन्द्रीय दरों पर महंगाई भत्ते का लाभ दिया गया था। राज्य सरकारों द्वारा वेतनों में संशोधन करने पर अन्य क्षेत्रीय कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करने का विचार किया जा रहा है और जो संभव हुआ निश्चित रूप से किया जायेगा।

इस विधेयक से संगत न होते हुए भी क्योंकि यह प्रश्न उठाया गया है अतः मैं कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय भांडागार निगम ने यथेष्ट प्रगति की है। १९६२-६३ के लेखे तैयार किये जा रहे हैं और लगभग २० लाख रुपये के लाभ की आशा है, गोदामों का खर्च १८ या १९ लाख रुपया होगा। गत वर्ष यह खर्च केवल १६ लाख रुपया था। हानि उत्तरोत्तर कम हो रही है। आशा है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में निगम आत्म निर्भर हो जायेगा। वस्तुतः हम इस ओर बढ़ रहे हैं। अब कुल गोदाम ७८ हैं जिन में से ११ केन्द्रीय भाण्डागार निगम ने बनाये हैं और ६७ किराये पर हैं। भाण्डार की कुल क्षमता १,८४,७२६ टन है। इन भाण्डागारों पर १२ करोड़ रुपये तक का अग्रिम दिया जा चुका है। हम इस प्रगति से संतुष्ट नहीं किन्तु कुछ वर्षों में काफी प्रगति हुई है और मुझे विश्वास है कि हानि समाप्त हो जाएगी।

श्री सोनावने ने पूछा कि किराये पर गोदाम लेने की बजाय गोदाम बनाये क्यों नहीं जाते। गोदामों के निर्माण की योजना है किन्तु कुछ केन्द्रों की परीक्षा करनी है कि वहां गोदाम रखना वांछनीय है अथवा नहीं। यदि लाभदायक हुआ तो गोदाम बनाये जायेंगे।

कुछ असंगत बातें भी कही गई हैं। मैं समझता हूं कि सरकार को इस चर्चा से लाभ हुआ है। हम स्वयं प्रयत्न कर रहे हैं कि यह निगम यथा संभव अधिकाधिक लाभदायक प्रमाणित हो।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भाण्डागार निगम अधिनियम १९६२ में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**श्री यशपाल सिंह** : मैं संशोधन संख्या १ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मैं संशोधन संख्या २ प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १ और २ मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड १, अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी विधेयक में जोड़ दिया गया।

†**श्री अ० म० थामस** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाय।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक को पारित किया जाय।"

†**श्री मा० श्री० अणे** (नागपुर) : गोदाम बनाने में कितना खर्च होता है ?

†**श्री अ० म० थामस** : १,८४,७२६ टन की क्षमता में से कुल ४,६०० टन की क्षमता के गोदाम बनाये गये हैं।

†**श्री प्रिय गुप्त** : अब तक गोदामों का किराया दिया जा चुका है ?

†**श्री अ० म० थामस** : इस समय मेरे पास जानकारी नहीं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (संशोधन) विधेयक

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि सीमा शुल्क अधिनियम, १९६२ और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

विधेयक का उद्देश्य सरल है। इस समय सीमाशुल्क केन्द्रीय सरकार द्वारा आयात या निर्यात की गई वस्तुओं पर लगाया जाता है। इसी तरह केन्द्रीय उत्पादन शुल्क भी केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्मित वस्तुओं पर लगाया जाता है। किन्तु राज्य सरकार द्वारा आयात या निर्यात अथवा निर्मित वस्तुएं इन करों से मुक्त हैं जब तक वे व्यापार के लिए प्रयोग न की जाएं। विधेयक का उद्देश्य है कि चाहे वस्तुएं राज्य सरकार की हों या केन्द्रीय सरकार की उन पर एक समान रीति से कर लगाया जाय।

१९५१ से पूर्व राज्य सरकारों की ऐसी वस्तुओं पर कर लगता था। १९५१ में उन वस्तुओं पर ही कर लगाने की व्यवस्था की गई जो व्यापार के लिए प्रयुक्त होती हों। ऐसा संविधान के अनुच्छेद खंड की व्याख्या के अनुसार किया गया था ताकि इस पर कहीं विवाद खड़ा न हो जाए।

गत कुछ वर्षों का यह अनुभव है कि इस कर विमुक्ति से राजस्व की हानि के अतरिक्त कई कठिनाइयां और असंगतियां पैदा हो जाती हैं। इन दिनों केन्द्र अथवा राज्यों में सरकार को विभिन्न नीतियों के अनुसार वस्तु निर्माण और वस्तु विक्रय के कार्य करने पड़ते हैं। ये परियोजनाएं गैर सरकारी परियोजनाओं के साथ तथा उन से प्रतियोगिता करते हुए काम करती हैं। उदाहरणतः दुग्ध पूर्ति, मुद्रणालय, या शिक्षा संस्थाओं की योजनाएं हैं। जेलों में अपराधियों को काम दिया जाता है और वे वस्त्र आदि शुल्क योग्य वस्तुओं का निर्माण करते हैं और बूट निर्माण का प्रशिक्षण देने की राज्य सरकारों की योजनाएं हैं। ये सब योजनाएं सरकारी फर्मों के अन्तर्गत हैं और अनुच्छेद २८९ के अन्तर्गत व्यापार में शामिल नहीं। हम अब तक ऐसी सभी योजनाओं पर राज्य सरकारों को कर मुक्ति देते रहे हैं। किन्तु असंगति यह है कि ऐसी गैर सरकारी संस्थाओं को कर देना पड़ता है। ऐसी ही स्थिति में केन्द्रीय सरकार के माल पर कर लगाया जाता है। जहां कहीं गैर-सरकारी उपक्रमों से तुलना या प्रतियोगिता का प्रश्न हो हम इसे लागत और लेखे के लिए आवश्यक समझते हैं। यह असंगति है कि केन्द्रीय सरकार अपने माल पर कर लगाये किन्तु राज्य सरकार के उसी माल पर कर न लगाये।

अतः प्रस्ताव किया गया है कि राज्य सरकारों से कर विमुक्ति वापस ले ली जाय। सभी परिणामों पर विचार करने के उपरांत सरकार ने यह विचार किया है कि यह कर विमुक्ति संविधान के उपबन्ध के अन्तर्गत नहीं है। अनुच्छेद २८९ में उपबन्ध है कि राज्य सरकार की सम्पत्ति संघ के कर से मक्त होगी। किन्तु सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, कर नहीं हैं। कुछ राज्य सरकारें इस से सहमत नहीं हैं। राष्ट्रपति ने अनुच्छेद १४३ के अन्तर्गत संशोधक विधेयक सहित उच्चतम न्यायालय विशेष निर्देश किया था। उच्चतम न्यायालय ने सलाह दी है कि केन्द्रीय सरकार व्यापार आदि के लिए प्रयुक्त वस्तुओं से भिन्न वस्तुओं पर सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क लगा सकती है और प्रस्तावित संशोधित अनुच्छेद २८९ के विरुद्ध नहीं।

इन कारणों से वर्तमान विधेयक प्रस्तुत किया गया है और इस में यह स्पष्ट शब्द हैं कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों पर सीमा शुल्क या केन्द्रीय उत्पादन शुल्क लगाया जायेगा। मैं यह भी कह दूं कि इस विधेयक के पास होने से राज्य सरकारों पर अधिक वित्तीय भार नहीं पड़ेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रस्तुत छूट के कारण १९६२-६३ में छोड़ी गई सीमा शुल्क की राशि वर्ष के सीमा शुल्क राजस्व २४६ करोड़ रुपये की तुलना में २० लाख रुपये की थी। उसी प्रकार केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की छोड़ी गई राशि ५८९ करोड़ रुपयों के कुल राजस्व की तुलना में ३ लाख रुपये थी। इन आंकड़ों से पता चलता है कि जबकि सिद्धान्ततः विधान बनाना आवश्यक है, इस के परिणामस्वरूप राज्य सरकारों पर कोई उल्लेखनीय भार नहीं पड़ेगा। मैं यह और कहूंगा कि विधेयक यह उपबन्ध नहीं करता कि राज्य सरकार द्वारा आयात की गई, निर्यात की गई, निर्मित की गई वस्तु पर अथवा उस के प्रत्येक उत्पादन पर शुल्क लगाया जायेगा। जहां किसी पदार्थ को सीमा शुल्क अथवा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के अन्तर्गत शुल्क से मुक्त है अथवा जिसे शुल्क से सामान्य मुक्ति प्राप्त है, वहां राज्य सरकारों को भी स्वभावतः यह छूट दी जायेगी। उदाहरणार्थ प्रशुल्क अथवा अन्य सम्बन्धित अधिसूचनाओं के अन्तर्गत दी गई प्रस्तुत सामान्य छूट के अधीन राज्यों द्वारा आयात किये गये शस्त्रास्त्रों, गोला बारूद और सैनिक सामानों पर, मान्यताप्राप्त शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थाओं द्वारा आयात किये गये वैज्ञानिक उपकरणों और औजारों पर, राज्य सरकारों द्वारा आयात किये गये, मक्खन निकले दूध का पाउडर, प्लेग निरोधक सीरम, खाद और उर्वरकों, कृषि औजार, सार्वजनिक संग्रहालयों, में रखी जाने वाली कलाकृतियों जैसे मूर्तियां और तस्वीरें और अन्य बहुत ही वस्तुओं पर, इस विधेयक के कारण, शुल्क नहीं लगाई जायेगी। इसी प्रकार उत्पादन शुल्क लगाने योग्य किसी भी श्रेणी की वस्तुओं के सम्बन्ध में जहां उत्पादन शुल्क की पूरी या आंशिक छट दी हुई है वहां राज्य सरकारों द्वारा बनाई गई वस्तुओं पर भी, यदि छूट का नियमन करने वाली शर्तें, यदि कोई हों, पूरी हो जायें छूट दी जायेगी।

मैं नहीं समझता, श्रीमान्, कि मेरे कहने के लिए और कुछ शेष हैं। मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह विधेयक कई असंगतताओं को दूर करने के लिये आवश्यक है। यह संविधान के अनुरूप है, और इस से राज्य सरकारों पर कोई वित्त सम्बन्धी प्रभाव नहीं पड़ेगा। मुझे विश्वास है कि इस को पारित करने के लिए सहमत होने में सभा को कोई कठिनाई नहीं होगी।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री शं० शा० मोरे** (पूना) : क्या उच्चतम न्यायालय के मत को परिचालित कर दिया गया है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : सभा के सम्मुख कोई संशोधन नहीं है। श्री काशीराम गुप्त अगले दिन अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

तेईसवां प्रतिवेदन

†**श्री मुथिया** : (तिरुनेलवेली) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के तेईसवें

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रतिवेदन से जो २१ अगस्त, १९६३ को सभा में पेश की गई थी, सहमत है ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के तेईसवें प्रतिवेदन से जो २१ अगस्त, १९६३ को सभा में पेश की गई थी, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प

†**उपाध्यक्ष महोदय** : सभा अब २९ मार्च, १९६३ को श्रीमती सुभद्रा जोशी द्वारा प्रस्तुत बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प पर अग्रेतर चर्चा आरम्भ करेगी । श्री बनर्जी अपना भाषण जारी रखें ।

[श्री तिरुमलराव पीठासीन हुए]

†**श्री स० मो० बनर्जी** : (कानपुर) : मैं इस संकल्प का स्वागत करता हूं । १९५९ में भी ऐसा ही संकल्प प्रस्तुत किया गया था । उस समय वित्त उपमंत्री ने इसे अस्वीकार करते हुए कहा था कि यदि हम ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया तो कुछ प्रशासकीय कठिनाइयों के कारण देश की प्रगति में बाधा पहुंचेगी । मैं नहीं समझ पाया कि इस का क्या अर्थ था । मैं चाहूंगा कि श्री भगत उन प्रशासनिक कठिनाइयों पर प्रकाश डालें ।

जीवन बीमे का राष्ट्रीयकरण करते समय भी यह तर्क दिये थे और इस का राष्ट्रीयकरण किये जाने के बाद भी बहुत से प्रसिद्ध अखबारों में राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध लेख निकलते रहे थे; किन्तु आज जीवन बीमा निगम से हमें काफ़ी लाभांश प्राप्त हो रहे हैं और देश की प्रतिरक्षा के लिये हमारे पास करोड़ों रुपयों के संसाधन भी उपलब्ध हैं ।

यह दुर्भाग्य की बात है कि श्री भगत जो मन से राष्ट्रीयकरण स्वीकार करने के लिये तैयार हैं, वास्तव में ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मंत्रि परिषद् में उनकी नहीं चलती । १९५९ में इसे अस्वीकार करने के लिये दिये गये तर्कों का श्री रामकृष्ण गुप्त ने उत्तर दिया था । किन्तु फिर भी वह संकल्प सभा ने स्वीकृत नहीं किया ।

किन्तु अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ के लाखों सदस्यों के विशाल संगठन ने यही भाव व्यक्त किये हैं कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये । बैंक के कर्मचारियों द्वारा प्रकाशित "दि केब फोर नेशनलाइजेशन ऑफ बैंकस" पुस्तिका में बैंकों द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली दुष्प्रणालियां, बैंक का कार्य कैसे किया जाता है, इस देश के एकाधिकार इन बैंकों से जिनके कि वे मालिक हैं किस प्रकार अधिकतम लाभ उठाते हैं, ये सब बातें इस पुस्तिका में दिखाई गई हैं । यह चार पृष्ठों की पुस्तिका है और यदि सम्बन्धित मंत्री इस पुस्तिका को पढ़ें तो मुझे विश्वास है कि वे बैंकों के राष्ट्रीयकरण से सहमत हो जायेंगे ।

प्रधान मंत्री ने कल कहा था कि हम समाजवाद की ओर बढ़ रहे हैं । किन्तु भगत कहते हैं कि इस बात का अर्थ बैंकों का राष्ट्रोयकरण करना नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इन बैंकों की पूंजी २९ करोड़ रुपये, जमा राशि १६०० करोड़ रुपये और उन का लाभ वित्त मंत्री के अनुसार ६ करोड़ ५० लाख रुपये हैं। किन्तु बैंक कर्मचारियों के अनुसार यह लाभ इस से कहीं अधिक है। वित्त मंत्री ने कहा है कि हम प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं और बिना समुचित प्रतिकर दिये बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं कर सकते।

उन की पूंजी कुल २५ करोड़ रुपये है। जमींदारों को भी प्रतिकर के रूप में बोंड दिये थे। यही बात हम बैंकों के सम्बन्ध में भी कर सकते हैं; क्योंकि बैंकों के मालिक शक्तिशाली व्यक्ति हैं। ऐसी बात नहीं कि तुरन्त प्रतिकर न देने से वे भूखों मर जायेंगे। यह बैंकें टाटा, बिड़ला, डालमिया आदि बड़े व्यक्तियों के हाथों में हैं। इन लोगों के हाथों में बैंकों का, सीमेंट का, जूट मिलों का कार्य है। प्रत्येक चीज इन बड़ी शक्तियों के नियंत्रण में है। यदि हम ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर लिया तो हम देश की अर्थ-व्यवस्था को सुचारू रूप से चला सकेंगे।

उपमंत्री ने यहां कहा था कि बर्ड एण्ड कम्पनी के मामले में किसी मंत्री का हाथ नहीं है। यदि आप श्री पेल्टिगन और श्री अशोक चन्दा के बीच हुआ पत्र व्यवहार देखें तो आप को पता चलेगा कि किस प्रकार इस के नियंत्रण में बैंकों, जूट उद्योग और बहुत से उद्योगों का कार्य था। महालेखा परीक्षक भारतीय जूट मिल संघ के सलाहकार थे। यदि इन लोगों के साथ श्री बुध्वार का पत्र-व्यवहार प्रकाशित किया जाये तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि बर्ड एण्ड कम्पनी के मामले में कुछ केन्द्रीय मंत्रियों का भी हाथ था। रिजर्व बैंक के कुछ अधिकारियों का भी इस में हाथ था। इसलिये हम चाहते हैं कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाये। कल राज्य सभा में एक प्रश्न के उत्तर में वित्त मंत्री ने कहा था कि एक केन्द्रीय मंत्री और एक राज्य मंत्री का विदेशी बैंकों में हिसाब है। यह आश्चर्य की बात है।

बैंक कर्मचारियों द्वारा प्रकाशित पुस्तिका में बैंकों के राष्ट्रीयकरण से होने वाले लाभों पर प्रकाश डाला है :

१. बैंकों का सारा लाभ लगभग ३५ करोड़ रुपये सरकारी राजस्व में जायेगा;

२. मूल्य रेखा स्थिर रखी जा सकेगी;

३. ग्रामीण बैंकिंग के कार्य को सब से अधिक प्रोत्साहन मिलेगा, इस से कृषकों और कृषि-कार्य को लाभ पहुंचेगा;

४. विदेशी मुद्रा में हेर फेर नहीं किया जा सकेगा;

५. आयात-निर्यात व्यापार में भी वृद्धि होगी।

६ कर-अपवंचन रोका जा सकेगा;

७. बैंकों के रुपये को योजना आयोग द्वारा निर्धारित विकास कार्यों में आवश्यकतानुसार लगाया जा सकेगा;

८. कुछ व्यक्तियों के हाथ में धन के एकत्रित होने का काम बन्द हो जायेगा। इससे समाजवाद की ओर अधिक प्रगति हो सकेगी।

इतने लाभ बैंकों के राष्ट्रीयकरण से होंगे। और हानि कुछ भी नहीं होगी। फिर इन का राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं किया जाता ? दुर्भाग्य से देश की सारी अर्थ-व्यवस्था पर ७ परिवार अधिकार जमाना चाहते हैं। सरकार सोचती है कि इन बातों के कारण बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाये। सरकार १२५ रुपये मासिक पाने वालों से ४० या ६० करोड़ रुपये इकट्ठा करना चाहती है और यह अनिवार्य जमा योजना के अधीन किया जा रहा है। यह अनिवार्य जमा नहीं,

अनिवार्य भूखों मरना है। यदि हम वह करना चाहते हैं तो देश की अर्थ-व्यवस्था पर नियंत्रण करने के लिये बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं करते ?

इसलिये यह संकल्प स्वीकार कर लिया जाना चाहिये क्योंकि वह उन्हीं के पक्ष के लोगों ने प्रस्तुत किया है। इस संकल्प को प्रस्तुत करने के लिये श्रीमती सुभद्रा जोशी को बधाई देता हूं और उन से निवेदन करता हूं कि वे इसे वापिस न लें क्योंकि केवल यह सभा ही नहीं अपितु सारा देश उन के साथ है।

†**श्री महेशदत्त मिश्र :** (खंडवा) : श्रीमान्, मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं। मुझे अभिमान है कि मेरे दल की एक सदस्या ने इसे प्रस्तुत किया है, जब कि कल ही वित्त मंत्री ने यह कहा है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने में कुछ कठिनाइयां हैं। यह हो सकता है कि इस आपात काल में ऐसा करने में सरकार कुछ संकोच अनुभव करे। मैं इस विषय में कुछ कहना चाहता हूं।

एक तो यह कि हम सरकारी क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि आपातकाल के कारण भी हमारे सामने वित्तीय कठिनाइयां उपस्थित हो गई हैं। हमें आपातकाल का सामना करने के लिये रोज नये-नयेसाधनों के विषय में सोचते हैं। इसलिये जब हम उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के विषय में सोचते हैं तो हमारे सामने तकनीकी कर्मचारियों, पर्याप्त अनुभव, और रुपये का प्रश्न आता है। किन्तु बैंकों के सम्बन्ध में तकनीकी कर्मचारियों और अनुभव का कोई प्रश्न नहीं उठता। बैंकें पहले से ही कार्य कर रही हैं केवल उन का स्वामित्व परिवर्तित कर देना है। प्रतिकर देने के सम्बन्ध में रुपये का प्रश्न भी पैदा नहीं होता। ज़मींदारी उन्मूलन के सम्बन्ध में भी यह प्रश्न मारे मार्ग में रुकावट नहीं बन सका था। सारे देश की आंखें इस प्रश्न पर लगी हुई हैं कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये। यदि हम ने ऐसा किया कि तो हम लोग लोगों में यह विश्वास उत्पन्न नहीं कर सकेंगे कि हम इस प्रकार की अर्थ-व्यवस्था को अपने हाथ में लेना चाहते हैं।

मैं चाहता हूं कि इस का दूसरा कदम, किसी अन्य उद्योग के राष्ट्रीयकरण करने की अपेक्षा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना ही होना चाहिये। यदि उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया तो कुछ क्षति पहुंचने की संभावना है। क्योंकि यदि हम ने पहले से चले हुए उद्योगों को अपने हाथ में लिया तो हम नये उद्योगों को चालू नहीं कर सकेंगे। इसलिये जहां तक उद्योगों का प्रश्न है। यदि हम उन्हें नहीं चला सकें, तो मैं चाहिये कि उन्हें दूसरों को चलाने दें। हमारे पास उद्योगों को चलाने के लिये कर्मचारियों की कमी है। किन्तु जैसा कि मैं कह चुका हूं बैंकों के सम्बन्ध में यह कठिनाई उत्पन्न नहीं होती। केवल हमें उनका नियंत्रण बदलना है और बैंक के कर्मचारियों को समझा देना है कि यह कार्य लोकहित में किया गया है, इस से कार्य में शिथिलता और अदक्षता उपपन्न नहीं होगी।

मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता कि सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार क्यों नहीं कर देती। संसद् केवल लोकमत तैयार कर सकता है। इसलिये इस संकल्प पर इस के गुण दोषों को देखते हुए विचार करना चाहिये और वर्तमान परिस्थिति और आपात काल को देखते हुए बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिये।

श्री स० मो० बनर्जी ने बहुत सी बातें कहीं है। मैं केवल एक बात और कहना चाहता हूं। कल प्रधान मंत्री ने लघु उद्योगों के महत्व पर बल दिया था। यदि हम लघु उद्योगों को राष्ट्रीय अर्थ

†मूल अंग्रेजी में

व्यवस्था में उचित स्थान देना चाहें तो यह आवश्यक है कि बैंक सरकारी क्षेत्र में ही हों, नहीं तो बैंक उद्योगों पर छाये रहेंगे और लघु उद्योग नहीं पनप पायेंगे । लघु उद्योगों के उत्पाद बड़े उद्योगों के उत्पादों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। इसलिये हम यह आवश्यकता अनुभव करते हैं कि उन्हें प्रोत्साहन दिया जाये। कुछ छोटे सहकारी बैंक उन की सहायता करते हैं, किन्तु यह पर्याप्त नहीं है। इसलिये यह आवश्यक है कि बैंकों का नियंत्रण सरकार के हाथों में हो।

सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में पूंजी निर्माण के लिए भी यह आवश्यक है। क्योंकि जब तक बैंकों का एकाधिकार कुछ लोगों के हाथों में है, वे अपने हितों की रक्षा के लिये, सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योगों और लघु उद्योगों में पूंजी निर्माण के कार्य में बाधा पहुंचायेंगे। अन्त में मैं कहना चाहूंगा कि जब तक सरकार यहां पर पूंजीवादियों के हितों पर नियंत्रण करने की दिशा में कदम नहीं उठाती तब तक समाजवाद की बातें करने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

राष्ट्रीयकरण के विरोध में यह कहा जाता है कि इस से कार्यालय सम्बन्धी शक्तियां कुछ ही लोगों के हाथों में चली जायेंगी और भ्रष्टाचार, कार्य की अदक्षता आदि बढ़ेगी। बैंकों में भ्रष्टाचार का कोई प्रश्न ही नहीं है।

जहां तक कार्यालय सम्बन्धी नियंत्रण का प्रश्न है यह सब प्रकार के राष्ट्रीयकरण में होता है। किन्तु यह बात अस्थायी ही है। क्योंकि जब जनता के हाथ में अधिक नियंत्रण होगा तो वे अधिकाधिक सचेत हो जायेंगे और नौकरशाही का खतरा उत्पन्न नहीं होगा।

यह आवश्यक है कि सरकार अपने राजस्व के साधनों में वृद्धि करे। हम आपातकाल में से गुजर रहे हैं। बाहरी आक्रमण का खतरा है। हमें बहुत सी चीजों का राष्ट्रीयकरण करना है। इसलिये हमें बैंकों के राष्ट्रीयकरण से यह कार्य आरम्भ कर देना चाहिये और इस बात की चिन्ता नहीं करनी चाहिये कि प्रतिकरस्वरूप क्या कुछ देना होगा।

श्री काशीराम गुप्त (अलवर) : सभापति महोदय, बैंकों का राष्ट्रीयकरण न सिर्फ संकट-कालीन स्थिति के कारण ही आवश्यक है, अपितु मूलभूत सिद्धान्तों के आधार पर भी आवश्यक है।

हमारी सरकार समाजवाद का नारा लगाती है लेकिन मालूम ऐसा होता है कि उन का दिमाग उलझन में है, और वह स्वयं यह नहीं जानते कि उन के समाजवाद का स्वरूप क्या है।

हम एक ओर देखते हैं कि हमारे देश में बिजनेस मानापली है और जो इंडस्ट्रीज़ हैं वे मानोपलाइज्ड हैं, कुछ लोगों के हाथों में हैं। इस काम में रुकावट डालने का अगर कोई सब से अच्छा तरीका हो सकता है तो वह बैंकों का राष्ट्रीयकरण है। हमारे वित्त मंत्री महोदय ने बतलाया कि अगर बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाय तो उस के लिए सौ करोड़ रुपया कम्पेन्सेशन का देना होगा और उस से साढ़े ६ करोड़ रुपये की आमदनी होगी। प्रथम तो हो सकता है कि बैंकों की पूंजी ही सौ करोड़ न हो। जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण होगा तो देखना पड़ेगा कि बैंकों ने यह सौ करोड़ की पूंजी कैसे बना ली है और उन को इतना रुपया देने की जरूरत भी है या नहीं यह भी तभी मालूम होगा।

सब जानते हैं कि इन बैंकों के पास एक सीक्रेट फंड होता है जिस को वह किसी को नहीं बताते। वह केवल रिज़र्व बैंक को मालूम होता है। जिस देश में यह प्रथा आज भी चल रही हो बैंकों के बारे में, कि वह अपना छिपा हुआ फंड रखें, उस देश की सरकार यह कहे कि हम समाजवाद लायेंगे तो यह नामुमकिन है। इसलिए इस दृष्टिकोण को बदलना होगा।

[श्री काशी नाथ गुप्त]

केवल यही दृष्टिकोण राष्ट्रीयकरण का नहीं होता है कि उस से हमारी आमदनी बढ़ेगी। यदि कोई पार्टी यह कहे कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण से उन के बजट में बहुत आमदनी होगी, तो सरकार उस दलील का मुकाबला यह कह कर कर सकती है कि उस से आमदनी होने वाली नहीं है, और इसीलिए उस का मुकाबला करने के लिए उन्होंने दलील दे डाली। लेकिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण केवल इसी अर्थ में नहीं होता है। देखना यह है कि उस से हम समाजवाद की तरफ कदम कितनी तेजी से बढ़ा सकते हैं। आज जो बड़े बड़े बिजनैस वाले हैं, इन बैंकों के जरिए से देश की अर्थ बकों नीति पर छाए हुए हैं। इन को रोकना सब से पहला काम है और यह तभी सम्भव होगा जबकि बकों का राष्ट्रीयकरण किया जाय।

मुझ से पहले श्री बनर्जी ने बहुत साफ साफ बतलाया कि किस प्रकार अंडर इनवाइसिंग और ओवर इनवाइसिंग होता है और उस में किस प्रकार इन बैंकों का हाथ होता है। बैंकों के राष्ट्रीय करण द्वारा हम अपने विदेशों के व्यापार के रूप को अच्छा बना सकेंगे। आज भले ही रिजर्व बैंकों का बैंकों पर बहुत कुछ कंट्रोल है, लेकिन इस के होते भी अपनी नीति निर्धारित करने में बैंक जो घपला करते हैं वह तभी सामने आवेगा जबकि बैंकों का राष्ट्रीयकरण होगा।

आम तौर से देखा जाता है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट मानापलिस्ट हैं, जिन्होंने सब जगह पर कब्जा किया हुआ है और जिन के हाथों में ये बैंक हैं, उन का ही ७०–८० प्रतिशत हित इन बैंकों से होता है। यदि जांच की जायेगी तो यह स्पष्ट मालूम हो जायेगा।

साथ साथ जो हम आज समाजवाद का नारा लगाते हुए कोआपरेटिव कंज्यूमर स्टोर्स के जरिये या स्टेट ट्रेडिंग के जरिये व्यापार चलाना चाहते हैं, यह भी तभी सम्भव होगा जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो। यदि बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं होगा तो पूंजी के अभाव में ये सब चीजें रह जाएंगी। देखने में आता है कि सरकार कंज्यूमर कोआपरेटिव स्टोर्स के लिए रुपया दे रही है। क्या यह जो कुछ हो रहा है वह योजना के आधार पर हो रहा है। और यदि योजना के आधार पर हो रहा है तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण फौरन होना चाहिए। यह तो योजना का प्रथम अंग है। उस के बिना योजना समाजवाद की तरफ नहीं जा सकती।

हमारा मुल्क तो समाजवाद का नारा ही लगा रहा है लेकिन और देश जोकि यह नारा नहीं लगाते, जैसे मिस्र आदि, उन्होंने हम से पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर लिया। समाजवाद का नारा लगाना और बैंकों का राष्ट्रीयकरण न करना ये दो बातें एक दूसरे के विपरीत हैं।

मैं श्रीमती सुभद्रा जी से निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार वे भाषण देने में और विरोधी दल पर कटाक्ष करने में बहादुर हैं उसी प्रकार से इस में भी बहादुरी दिखलाएं। खास तौर से यह ऐसा विषय है जिस में कि सारा हाउस उन के साथ है। मैं समझता हूं कि स्वतंत्र पार्टी के लोग भी शायद इस का विरोध करने की हिम्मत न करें।

एक माननीय सदस्य : करेंगे।

श्री काशीराम गुप्त : करेंगे तो देख लिया जायेगा।

श्री यशपाल सिंह : सरकार से पूछ लें।

श्री काशीराम गुप्त : मैं उन से निवेदन करूंगा कि सरकार तो बहुत से आश्वासन दिया करती है। परइस में कोई ज्यादा आश्वासन की गुंजाइश नहीं है। इसलिये मैं आशा करूंगा कि इस

प्रस्ताव को वे किसी भी प्रकार वापस न लेंगी और इस की परवाह नहीं करेंगी कि पास होता है या नहीं। और अगर यह रिजेक्ट भी हो जाता है तो इस से देश का हित ही होगा। ये जो प्रस्ताव हम लाते हैं या कोई कांग्रस का सदस्य लाता है, तो उस के लिए यह जरूरी नहीं हो जाता कि वह सरकार की बात मानने को मजबूर है। जब उन के प्रस्ताव को हम सब लोग सहयोग दे रहे हैं और फिर भी अगर उस में कमजोरी आय तो हम समझेंगे कि हमारे और आप के समय का सदुपयोग नहीं हो रहा। मैं यह निवदन करूंगा कि इस राष्ट्रीयकरण के बारे में इस के अन्दर कोई दलील एसी बाक़ी नहीं जो कमज़ोरी लाती हो। जहां तक बैंकों के राष्ट्रीयकरण करने का सवाल है, यह बिलकुल स्पष्ट है कि उन के अंदर कोई बहुत गड़बड़ होने का अंदेशा नहीं है। उन का स्टाफ़ अच्छा होता है। सारा पढ़ा लिखा स्टाफ़ होता है बल्कि यह जो नारा लगाया जाता है कि इंडस्ट्रीज़ के अन्दर लेवर का सहयोग होना चाहिए, लेबर की ज़िम्मेदारी उस के अन्दर लेनी चाहिए यह बैंकों में सब से ज्यादा हो सकती है। यह अवश्य है कि यदि बैंकों का राष्ट्रीयकरण होगा और उस में उन का जो कर्मचारी वर्ग है, उस का सहयोग बाक़ायदा नियमित रूप से नहीं लिया जायगा तो एक ख़तरे की संभावना हो सकती है और ब्यूरोक्रटिक ढंग में उस में सब काम हो सकता है। लेकिन यदि उन लोगों को साझीदार बनाया जायगा कामकाज में तो सारी समस्याएं बहुत अच्छी तरह से सुलझ जायेंगी और एक सब से अच्छा नमूना होगा इस बात के लिए कि किस प्रकार से साझदारी दोनों की होती है। लेबर की और मैनेजमेंट की, दोनों की साझेदारी बैंकों के मामले में बहुत अच्छ ढंग से हो सकती है। वह ऐसा मजदूर दल भी नहीं है जिस को हम बहका देंगे, भड़का देंगे या कोई राजनीतिक दल उन को भड़का देगा। वह किसी के भी भड़कावे में आने वाले नहीं हैं। वह लोग बहुत अच्छे ढंग से समझने वाले होते हैं। बैंकों के राष्ट्रीयकरण से आज जो उन के ऊपर एक अनिश्चितता की एक तलवार लटकी रहती है वह भी उतर जायेगी और उस में भी निश्चितता आ जायेगी। इसलिए मैं इस प्रस्ताव का हृदय से समर्थन करता हूं।

डा० राम मनोहर लोहिया (फर्रुखाबाद) : सभापति महोदय, इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मुझे ख़ुशी होती है। अफ़सोस सिर्फ यही है कि शायद सुभद्रा जी इस को वापिस ले लेंगी।

इस प्रस्ताव के ख़िलाफ़ एक बात कही जा सकती है कि इस से देश में पूंजीशाही ख़त्म हो जायगी। मैं नहीं कहूंगा, जो पूंजीशाही के समर्थक हैं वे कहेंगे। उन से मैं इतना ही कहता हूं कि इटली में १९४५ के बाद से बैंकों का राष्ट्रीयकरण चालू है और वहां की पूंजीशाही बहुत अच्छे तरीक़े से पनपी हुई है। फिर मैं क्यों समथन कर रहा हूं ? एक तो इसलिए कि हिन्दुस्तान की पूंजीशाही सामन्ती है यह आधुनिक नहीं है। यह नफ़ा इतना करती है कि कभी कभी मुझे अचरज हो जाता है कि २५ सैकड़े और ३० सैकड़े की पूंजी के ऊपर किस तरह से मुनाफ़ा हो सकता है और वैसे भी दुनिया भर की पूंजीशाही ऊपर और नीचे दोनों तरीके से काम करती है लेकिन हिन्दुस्तान की पूंजीशाही ऊपर और नीचे का काम करने में ज्यादा माहिर है और यहां के बड़े बड़े व्यापारी और घरानों का एक अलग अपना बैंक चलता है जैसे टाटा का सेंट्रल बैंक, बिड़लाओं का यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, और सिंघानियों का हिन्दुस्तान कमर्शियल बैंक है। जो अंग्रेजी कम्पनियां हैं बर्ड वग़ैरह उन का किसी ज़माने में लायड्स हुआ करता था, शायद अब भी हो लेकिन आजकल हो सकता है कि उन का नीदरलैंड बैंक हो। इन सब बैंकों की मार्फत उन्हें मुनाफ़ा, जो अपना छिपाना चाहें, जितना भी छिपाना चाहें, शायद सभी छिपाना चाहते होंगे, उस के छिपाने में आसानी हो जाया करती है।

आज कल सुनते हैं कि क्रोम के एक जहाज़ के ऊपर क़रीब ९० लाख रुपये का छिपा हुआ मुनाफ़ा हो जाता है। इसलिए मैं समझता हूं इन बैंकों की मार्फ़त सहूलियत हुआ करती होगी।

[डा० राममनोहर लोहिया]

वह चीज इस से इस वक्त थोड़ी बहुत बद हो सकती है।

इसके साथ साथ जब कि मेरा जैसा आदमी सभी तरह के राष्ट्रीयकरण का, खासतौर से फ़ौलाद, चीनी और कपड़े का राष्ट्रीयकरण पसन्द करेगा व किसी एक बैंक राष्ट्रीयकरण को इतना ज्यादा पसन्द नहीं करेगा लेकिन इसलिए कि समर्थक बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो जाय। कम से कम एक काम तो हो फिर बाद में देख लिया जायेगा।

इसके अलावा मैं एक बात और जरूर कह देना चाहूंगा कि जिस तरीके से अब तक राष्ट्रीयकरण हुआ है उससे मुझको जरूर मतभेद है और उसको बदलना चाहूंगा। दुनिया भर में निजी क्षेत्र कुछ लालची होता है लेकिन कुछ इंतजाम ज्यादा अच्छा करना जानता है। सार्वजनिक क्षेत्र कुछ ज्यादा कर्तव्यशील होता है लेकिन बदइन्तजामी उसमें ज्यादा होती है। यह दुनिया भर का तरीका रहा है। हिन्दुस्तान में निजी क्षेत्र ने और सार्वजनिक क्षेत्र ने, दोनों ने एक दूसरे से बहुत सीखा पढ़ा है, आपस में आदान प्रदान किया है। नतीजा यह हो गया है कि निजी क्षेत्र बन गया है बदइन्तजामी-वाला और सार्वजनिक क्षेत्र बन गया है लालच वाला। दोनों के अवगुण एक दूसरे ने सीख लिये हैं, गुण नहीं सीख पाये हैं। इसलिये सब से पहले मैं इस बात पर जोर दूंगा कि सार्वजनिक क्षेत्र में मजदूरी का फर्क इतना नहीं रहना चाहिए। अफ़सर और मजदूर के बीच जैसा मैंने पहले भी कहा है बहुत फर्क विद्यमान है। राउरकेला के सार्वजनिक क्षेत्र में फ़ौलाद के कारखाने में जो कि सार्वजनिक क्षेत्र में है, एक हजार अफ़सरान को करीब ३० लाख रुपये महीने सुविधाओं और नौकरियों में मिल जाते हैं और दूसरी तरफ ३० हजार मजदूरों को ३० लाख रुपये मिलते हैं। वह गैर-बराबरी क़रीब क़रीब बिल्कुल वैसी ही है जैसी कि जमशेदपुर के टाटा कारखाने में है। अगर इस तरह की गैर बराबरी रखते हुए राष्ट्रीयकरण होता है तो उसका कोई मतलब नहीं हुआ करता है। यह गैर बराबरी खत्म होनी चाहिए और यह गैर बराबरी कम होनी चाहिए। लेकिन मैं नहीं समझता कि मेरी जिन्दगी में कभी यह गैर बराबरी मिट सकेगी। २०–३० वर्ष पहले बोलता होता तो कहता कि यह बिल्कुल मिटाई जाय। आज मैं इसको घटाओं की बात कहूंगा।

इसके अलावा एक बात पर जोर दूंगा कि हिन्दुस्तान में बहुत कुछ सार्वजनिक क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के अधिकार छीन लिये जाते हैं। वे सरकारी नौकर बन जाते हैं। सरकारी नौकरों के बारे में इस तरह का कानून बना दिया गया है कि वह किसी राजनीतिक पार्टी का मेम्बर नहीं बन सकता है। यह बहुत बुरा है। इसका तो साफ मतलब हो जायेगा समाजवादी गुलामी क्योंकि समाजवाद में ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक क्षेत्र बढ़ता चला आयेगा और निजी क्षेत्र घटता चला जायेगा। सरकारी नौकरों की तादाद बढ़ती चली जायेगी। और फिर जनता के इतने बड़े हिस्से को अगर मना कर दिया जाय कि वह राजनीतिक पार्टियों का सदस्य बने या राजनीतिक काम करे तब तो साफ जो समाजवाद के दुश्मन लोग कहा करते हैं कि समाजवाद गुलामी है वह साबित हो जाएगा। इसलिए जो भी सरकारी नौकर हैं उनको राजनीतिक अधिकार देने चाहिएं। उनको देना क्या, उनके राजनीतिक अधिकार अक्षुण्ण रहने चाहिएं।

इसके अलावा मैं यह भी चाहूंगा कि इन सार्वजनिक क्षेत्रों का नियंत्रण सरकार के हाथ में सीधे न रहे बल्कि उसके लिए कुछ एक तरीके की एजेंसी बनाई जाय, चाहे कोई निगम बनाया जाय, या चाहे कोई और तरीका निकाला जा सके तो निकाला जाय। इस तरीके से राष्ट्रीयकरण को हम अगर बढ़ाते हुए चले जाते हैं तो फिर उस मकसद को हासिल कर पाना मुश्किल होगा। एक तरफ तो हिन्दुस्तान में पूंजी बढ़ नहीं पा रही है और मेरा हिन्दुस्तान की पूंजीशाही के खिलाफ़ सब से बड़ा आरोप यह है कि वह अपना धर्म ही नहीं निभा पा रही है। वह अपना कर्तव्य नहीं कर पा रही है।

मान लीजिये थोड़ी देर के लिये कि मुनाफाखोर लोग गैर बराबरी फैलायें लेकिन कम से कम हिन्दुस्तान के उद्योगों को तो पनपायें और बढ़ायें लेकिन हिन्दुस्तान की पूंजीशाही इतनी नालायक हो चुकी है कि हिन्दुस्तान के उद्योगों को व बढ़ा नहीं सकती है। हिन्दुस्तान के उद्योग तो तभी बढ़ सकते हैं जब ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक क्षेत्र बढ़ें। यह मैं मानते हुए इतना और कहना चाहूंगा कि आज सारे संसार में एक हम नक़शा देख रहे हैं, गैर बराबरी का। मैंने एक जगह पर बतलाया भी है कि यह गैर बराबरी सात किस्म की है। इसको मिटाया जाय और इसको निकाला जाय। मैं तो चाहता था कि मर्द और औरत की भी गैर बराबरी मिट जाये लेकिन सुभद्रा जी न मालूम क्यों मेरे बहुत ख़िलाफ़ रहती हैं। जब मैं उस गैर बराबरी को मिटाने की कोशिश करता हूं, उसको निकालने की चेष्टा करता हूं तो मारी सुभद्रा जी कहती हैं कि यह आदमी बड़ा विचित्र है कि किसी के चेहरे की तारीफ करता है। अब अगर मैं कहूं कि सुभद्रा जी बड़ी अच्छी लगती हैं और लगती रही हैं पिछले तीस वर्ष से तो वे बुरा तो नहीं मानेंगी ?

श्रीमती सुभद्रा जोशी : बिलकुल नहीं।

डा० राम मनोहर लोहिया: इन सब कारणों से मैं बहुत जोर के साथ इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

†**श्री मा० ल० जाधव** (मालेगांव) : श्रीमान्, मैं इस संकल्प के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** (कलकत्ता—दक्षिण पश्चिम): आप इसके समर्थन में कहना चाहते हैं या विरोध में ?

†**सभापति महोदय** : आप उनकी बात सुनिये, कुछ ही मिनटों में आपको पता लग जायेगा।

†**श्री मा० ल० जाधव** : सरकार ने राष्ट्रीयकरण का सिद्धान्त स्वीकार कर लिया है क्योंकि यह एक ऐसा सिद्धान्त है जिसका कोई भी विरोध नहीं कर सकता। ऐसे समय जब कि सरकार ने सरकारी क्षेत्र में उर्वरक कारखाना, इंजिन कारखाना, इस्पात परियोजनायें जैसी कई परियोजनायें आरम्भ की हैं और जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण करने जैसा साहसी कदम उठाया है कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि उद्योगों के राष्ट्रीयकरण करने और सरकारी क्षेत्रों में मुख्य परियोजनायें आरम्भ करने के लिये पर्याप्त प्रयत्न नहीं कर रहे। फिर क्या बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का यह उचित अवसर है जब कि आपातकाल चल रहा है और चीन और पाकिस्तान से हमें खतरा है। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र को समाप्त करने की सरकार की नीति नहीं है, क्योंकि हमने मिश्रित अर्थ-व्यवस्था को स्वीकार कर लिया है।

इस समय जब कि हमें प्रतिरक्षा के लिये बहुत अधिक धन की आवश्यकता है और हम उसे एकत्र करने के लिये अनिवार्य जमा योजना जैसे कई पग उठा रहे हैं क्या यह उचित है कि सरकार बैंकों के कार्य को हाथ में लेकर उसमें रुपया लगाये ?

सरकार की हमेशा से किसानों को सहायता देने की नीति रही है। बैंकें उन्हें ऋण आदि देकर उनकी सहायता करती हैं। इसलिए चाहे हम सिद्धान्ततः बैंकों के राष्ट्रीयकरण को स्वीकार करलें हमें इसे अभी कार्य रूप नहीं देना चाहिये।

निजी क्षेत्रों के बैंकों पर पहले से ही कुछ प्रतिबन्ध लगाये हुये हैं। सरकार इन पर नियंत्रण रखती है। खाद्यान्न जैसे पदार्थों की कीमतों पर अत्यन्त आवश्यक है। सरकार आवश्यकता

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मा० ल० जाधव]

पड़ने पर निजी क्षेत्र के बैंकों पर ऐसे नियंत्रण लागू कर सकती है जो उसके इस ध्येय में सहायक हों इसलिये हमें इस का राष्ट्रीयकरण करने में जल्दी नहीं करनी चाहिये ।

इन शब्दों के साथ में इस संकल्प के आधारभूत सिद्धान्त का समर्थन करता हूं ।

†**सभापति महोदय** : श्री इन्द्रजीत गुप्त । वे यहां नहीं हैं । श्री कामत ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मारी ओर से श्री मोहन स्वरूप बोलेंगे ।

†**सभापति महोदय** : श्री मोहन स्वरूप ।

श्री मोहन स्वरूप (पीलीभीत) : सभापति महोदय, आज की परिस्थिति में, जब कि हमने इस देश में सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी बनाने का इरादा किया है और इस देश में सोशलिज्म को लागू करना चाहते हैं, यह आवश्यक हो गया है कि बैंकिंग के सिस्टम का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये । इस सिलसिले में माननीय सदस्या, श्रीमती सुभद्रा जोशी, ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं ।

जहां तक कि इस देश की समृद्धि और प्रगति का सम्बन्ध है, बैंकों की व्यवस्था अच्छी हालत में और अच्छे ढंग से चलना अनिवार्य बात है । लेकिन दुख की बात है कि बैंकिंग का सिस्टम कुछ धनाढ्य लोगों के हाथ में है, जो कि उस पर काबू पाये हुए हैं और जिस तरह से चाहते हैं, उसको चलाते हैं । इस बारे में काफी बातें बताई जा चुकी हैं और नाम भी बताए जा चुके हैं मैं उनमें नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बैंकों के कुछ आदमियों के हाथों में चलते रहने की प्रवृत्ति कोई अच्छी बात नहीं है । इससे देश को हानि ही पहुंचेगी ।

इस देश में कुल ३०४ बैंक हैं, जिनमें से ८२ शिड्यूल्ड लिस्ट में हैं और १४ फारेन एक्सचेंज बैंक्स हैं । जो बाकी ६८ बैंक रह गए हैं, उनमें से ११ ऐसे हैं, जिनका वर्किंग फंड २५ करोड़ रुपये से ऊपर है, १३ का साढ़े सात करोड़ रुपये से २५ करोड़ रुपये और शेष का साढ़े सात करोड़ रुपये है । नेशनलाइज्ड सैक्टर में स्टेट बैंक आफ इंडिया की हालत यह है कि उसका डिपाजिट ६६१·०९ करोड़ रुपये और पेडअप कैपिटल १०·५८ करोड़ रुपये है । मेरे पास इन फ़िगर्ज़ की एक लम्बी लिस्ट है, जिसको पढ़ कर मैं हाउस का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं ।

प्राइवट सैक्टर में जो बैंक हैं, वे ८५ प्रतिशत डिपाज़िट रखते हैं । इस तरह से वे सारे देश की इकानोमी पर छाए हुए हैं । आज सारे देश में बैंकों की कुल ५,१११ शाखायें हैं जिन में से ग्रामों में कुल ९५७ शाखायें हैं । जाहिर है कि गांवों में बैंकिंग की आवश्यकता बढ़ती जा रही है । एग्रीकल्चर का विस्तार हो रहा है और को-आपरेटिव्ज़ का विस्तार हो रहा है, लेकिन इस दिशा में कोई उन्नति नहीं हो रही है । इस वजह से नहीं हो रही है कि बैंक कुछ प्राइवेट लोगों के हाथ में हैं । स्थिति यह है कि प्राइवेट सेक्टर के लोग उस पर काबू पाए हुए हैं । लोग जो रुपया जमा करते हैं, वे उससे लाभ उठाते हैं और लोगों को कम सूद देते हैं । एक एक व्यक्ति जो बैंक का डायरेक्टर है, कई कई इंडस्ट्रियल कन्सर्ज़ का मालिक है । इस तरह से उसकी प्राडक्शन और डिस्ट्रिब्यूशन पर उसका काबू है और वह मनमाने तौर से कार्यवाही करता है ।

इस परिस्थिति पर हमको विचार करना चाहिये । महज़ यह कह देना उचित नहीं है कि बैंकों

†मूल अंग्रेजी में

का नेशनलाइज़ेशन करने से काफी रुपया कम्पेन्सेशन में देना पड़ेगा और उसका भार म वर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। य तो एक टालने वाली बात है। अभी यू० पी० में और देश के दूसरे भागों में ज़मींदारों की करोड़ों अरबों रुपये की ज़मींदारियां ली गई, लेकिन उनके मुआवज़े की शक्ल में उनको चालीस-साला बांड दिये गये। मैं समझता हूं कि बैंकों का नेशनलाइजेशन करने के पश्चात् अगर कम्पेन्सेशन की बात चलती है, तो चालीस साला या पचास-साला बांड्ज़ की शक्ल में मुआवज़ा दिया जा सकता है। उस चीज़ को य क कर टाल देने से काम नहीं चलेगा। वक्त आ गया है कि इस पर गम्भीरता से विचार किया जाए। बैंकों का नेशनलाइज़ेशन अब अनिवार्य हो चुका है।

नेशनलाइज़ेशन का ज़िक्र करते हुए इस बात पर भी मैं ज़ोर देना चाहता हूं कि जिन चीज़ों का राष्ट्रीयकरण किया गया है, उनमें सरकारीकरण ही अधिक हुआ है। लोहिया साहब ने इस पर कुछ कहा है। उन्होंने क ा है कि राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ है वास्तविक रूप में। जिस सोशलिस्टिक ढंग से वह होना चाहिये था, नहीं हुआ है, बल्कि सरकारीकरण हुआ है। मेरा निवेदन है कि आगे जब आप किसी भी सैक्टर का राष्ट्रीयकरण करना चाहें तो असली मानों में उसके समाजीकरण पर जोर दें और सरकारीकरण पर ज्यादा ज़ोर न दें। अभी लाइफ़ इनश्योरेंस को आपने अपने ाथों में लिया है। पहले जो लोगों में इंसेंटिव था और काम करने की भावना थी, वह आज नहीं है। इसका कारण य है कि वे समझते हैं कि उनको तनख्वाह मिलती है और महीने में एक बार तनख्वाह मिलने के बाद उनको और कुछ मिलना नहीं है। अभी लोहिया जी ने कहा कि कोई कारपोरेशन बने या कोई इस तरह की और चीज़ बने जो कि उसके कार्य को चलाये। यदि ऐसा किया गया तो लोगों को काम करने का इन्सेंटिव होगा, उनमें काम करने की क्षमता बढ़ेगी, हौसला पैदा होगा।

करप्शन का सवाल भी है। अभी विवियन बोस कमेटी की रिपोर्ट छपी थी और उसमें बताया गया था कि बैंकों में काफी करप्शन है। अगर और भी खोजबीन की जाए तो और भी केसिज़ नज़र में आ सकते हैं और भी आंकड़े मिल सकते हैं।

आज बैंकों की हालत क्या है, इसको आप देखें। अभी प्लाई बैंक और लक्ष्मी बैंक फेल हो चुके हैं और उनके फेल होने के कारण लाखों रुपये की लोगों की सम्पत्ति मारी गई है। इस तरह की घटनायें अगर होती रहती हैं, तो काम चलने वाला नहीं है। इस ओर भी आपका ध्यान जाना चाहिये।

मैं, श्रीमती सुभद्रा जोशी ने जो रेज़ोल्यूशन पेश किया है, उसका समर्थन करता हूं और सरकार से निवेदन करता हूं कि इस दिशा में वह सक्रिय कदम उठाये और बैंकों का राष्ट्रीयकरण शीघ्रातिशीघ्र करे।

†**श्री इन्द्रजी गुप्त** (कलकत्ता—दक्षिण पश्चिम) : इस संकल्प को सभा में लाने पर मैं माननीय सदस्या को मुबारकबाद देता हूं क्योंकि यह प्रश्न सभा के भीतर ही नहीं वरन् आम जनता में भी इस देश के भविष्य के लिए अत्यावश्यक महत्व का समझा जा रहा है।

१७ अप्रैल को बैंकों के कर्मचारियों ने देश भर में अखिल भारत दिन मनाया और उन की मांग थी कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाय। इसी प्रकार १३ सितम्बर को लगभग देश के एक करोड़ लोगों द्वारा इस संसद को एक याचिका भेजी जा रही है जिसमें इसी मांग को दोहराया

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

जायेगा। मेरा सरकार से निवेदन है कि वह इस मांग पर अधिक गम्भीरता से विचार करें क्योंकि ऐसा करने से देश की रक्षा और विकास के लिए संसाधन जुटाये जा सकते हैं।

मेरा उपमंत्री जी से अनुरोध है कि वह उत्तर देते समय बैंकों के राष्ट्रीयकरण के वित्तीय पहलुओं की व्याख्या करें, राजनीतिक और सैद्धान्तिक नहीं। माननीय मंत्री के अर्थ-शास्त्र के ज्ञान को देख कर मुझे बहुत असन्तोष हुआ है।

श्री मोरारजी देसाई ने तीन तर्क दिये हैं। सिद्धान्तों को एक तरफ रख कर मैं इन तर्कों को लूंगा। एक तर्क उन्होंने यह दिया कि जो रुपया बैंकों में जमा है, जो लगभग १३०० अथवा १४०० करोड़ है, वह राष्ट्रीयकरण के पश्चात् उनके पास नहीं आ जायेगा। मगर हमें देखना तो यह है कि इस धन का प्रयोग किस प्रकार किया जा रहा है और राष्ट्रीयकरण के परिणामस्वरूप यह धन किस प्रकार प्रयोग में लाया जा सकता है। माननीय प्रधान मन्त्री ने कहा कि हम योजना को लोकतन्त्र के साथ मिलाने का प्रयोग कर रहे हैं, परन्तु क्या हम यह सहन कर सकते हैं कि इतनी बड़ी राशियों का प्रयोग बड़े बड़े पूंजीपतियों द्वारा मनमाने ढंग से किया जाय। मैं समझता हूं कि ऐसा करके हम योजना के सिद्धान्तों को जड़ों से उखाड़ रहे हैं। योजना का एक उद्देश्य मूल्यों को बढ़ने से रोकना है परन्तु मूल्य तब तक बने नहीं रह सकते जब तक हम इतनी बड़ी राशियों का प्रयोग संचय करने, मुनाफाखोरी और सट्टाबाजी करने में होने दें। संचय करने, मुनाफाखोरी और सट्टेबाजी के लिये धन बैंकों द्वारा ही उपलब्ध किया जाता है। श्री पाटिल किसानों को प्रोत्साहन देने की बात करते हैं। वास्तव में बैंकों का राष्ट्रीयकरण न करके प्रोत्साहन उन व्यापारियों और बीच के व्यक्तियों को दिया जा रहा है जो किसानों से गल्ला खरीद कर स्टाक करते हैं और मुनाफाखोरी करते हैं। गल्ले का संग्रह करने के लिये धन उन्हें बैंकों से ही मिलता है। इसलिये किसानों को प्रोत्साहन देने वाली बात सर्वथा गलत है।

योजना का एक उद्देश्य विदेशी मुद्रा को बनाये रखना है परन्तु वास्तव में यह बैंक कम राशियों के और अधिक राशियों के बीजक बना कर इस उद्देश्य को प्राप्त होने में बाधक सिद्ध होते हैं।

इसके अतिरिक्त, धन के कुछ व्यक्तियों के हाथों में संचय के लिये भी बैंक ही उत्तरदायी हैं। श्री मोरारजी देसाई का यह तर्क तथ्यहीन है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के परिणामस्वरूप उनमें जमा राशियां उनके हाथों में नहीं आ जायेंगी। वास्तव में जिस धन का प्रयोग अब योजना के उद्देश्यों को असफल बनाने में किया जा रहा है राष्ट्रीयकरण के पश्चात् उसका प्रयोग देश की प्रगति और आम जनता के हित के लिये किया जा सकेगा।

श्री मोरारजी के दूसरे तर्क के साथ कि बैंकों का लाभ केवल ६ करोड़ है मैं सहमत नहीं हूं। वास्तव में यह लाभ इससे कहीं अधिक है।

श्री मोरारजी का प्रतिकर के बारे में जो तर्क है, कि उन्हें १०० करोड़ रुपया प्रतिकर के रूप में देना पड़ेगा, गलत है। इन बैंकों की दत्त पूंजी २९·१८ करोड़ रुपये है और इस हिसाब से मुआवजा केवल ४७.३८ करोड़ ही देना पड़ेगा। वर्ष १९४७ से १९६१ तक बैंकों द्वारा लाभांश के रूप में ३४·५३ करोड़ रुपया दिया गया। उनकी गुप्त रक्षित निधियों के अलावा २४·२२ करोड़ रक्षित निधियां थीं। १५०० करोड़ रुपये, जो बैंकों के निक्षेप हैं, पर यदि ५ प्रतिशत भी ब्याज लगाया जाय तो वर्ष में ७५ करोड़ रुपया प्राप्त हो सकेगा। मुआवजे के रूप में अधिक से अधिक ४७ करोड़ अथवा ५० करोड़ रुपया देना पड़ेगा। तो क्या बैंकों की रक्षित निधियों और ७५ करोड़ रुपये वार्षिक ब्याज को मिला कर मुआवजे की राशि को चुकाया नहीं जा सकता है?

मेरा सरकार से अनुरोध है कि यदि आप योजनाओं को सफल बनाना चाहतेहैं, यदि आप चाहते हैं कि देश की अर्थ-व्यवस्था सुधरे और देश प्रगति करे, तो आप बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर अधिक गम्भीरतापूर्वक विचार करें।

†**सभापति महोदय** : माननीय सदस्य का समय पूरा हो चुका है।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : अन्त में मैं बताऊंगा कि बैंकों के निक्षेपों में से लगभग १०० करोड़ रुपये अनाज के संग्रह के लिये और ३६७.६२ करोड़ रुपये सट्टा बाजार के लिये और सोना चांदी के लिये दिये जा रहे हैं। यदि आप बैंकों का राष्ट्रीयकरण करें तो इन राशियों का प्रयोग देश के अन्य लाभकारी साधनों पर लगा सकते हैं : आप अनिवार्य जमा योजना से लोगों को प्रभावित होने से बचा सकते हैं। आप लोगों को अधिलाभ कर से बचा सकते हैं। मेरा अनुरोध है कि इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके देश की जनता को राहत पहुंचायें।

†**श्री मुत्तु गौंडर** (तिरुपत्तूर) : यदि बैंकों का राष्ट्रीयकरण योजनायें आरम्भ करते समय कर लिया जाता तो आज हमारे लिये साधनों की कमी नहीं होती। बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके हमें धन के कुछ हाथों में संचय को रोकना चाहिए। मद्रास में महाजन लोग बसें और लारियां चला कर शत प्रतिशत मुनाफा कमाते हैं जिसके परिणामस्वरूप वास्तव में काम करने वालों को कुछ नहीं मिलता। वर्तमान आपात का लाभ उठाते हुए शीघ्रातिशीघ्र बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिये।

एक किसान यदि आज खेती करता है तो उसे धन की आवश्यकता होती है। जो वह एक महाजन से ले लेता है। अब उस किसान की उपज को महाजन द्वारा बेच कर लाभ उठाया जाता है। मेहनत तो करता है गरीब किसान और उसका लाभ उठाते हैं यह महाजन। इन महाजनों को बैंकों से ही धन प्राप्त होता है। इसलिये यदि आप बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर देंगे तो स्वभावतः गरीबों को उनका लाभ मिलेगा।

†**श्रीमती सुभद्रा जोशी** : चूंकि अभी बहुत से सदस्य बोलना चाहते हैं इसलिये मेरा अनुरोध है कि यदि सब सहमत हैं तो इस संकल्प पर चर्चा का समय बढ़ा दिया जाय।

†**श्री भागवत झा आजाद** : मैं भी समझता हूं कि समय बढ़ाया जाना चाहिए।

†**सभापति महोदय** : हम सभा की अनुमति लेंगे।

†**श्री रंगा** : चूंकि बहुत से अन्य गैर-सरकारी संकल्प हैं इसलिये समय नहीं बढ़ाया जाना चाहिए।

†**श्री अब्दुल वहीद** (वेल्लोर) : मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं। यदि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय तो देश के औद्योगिक विकास में बाधा पड़ेगी।

निस्सन्देह भूतकाल में बैंकों द्वारा बहुत सी अनियमितायें की गईं परन्तु जब से भारत के रक्षित बैंक ने बैंकों पर कड़ा नियन्त्रण किया है तब से स्थिति में सुधार हुआ है और मुझे आशा है कि भविष्य में वह अनियमितायें नहीं कर सकेंगे। भविष्य में मुझे आशा है कि वित्त मन्त्रालय और रक्षित बैंक बैंकों पर और अधिक नियन्त्रण रखेंगे।

बैंकों को छोटे साहूकारों से मिलाया जा रहा है। मैं समझता हूं कि अब जो लोग बैंकों से वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं जब आप बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर देंगे तो उन्हें छोटे छोटे साहूकारों के पास जाना पड़ेगा, जिसके फलस्वरूप उनकी कठिनाइयों में और वृद्धि होगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अब्दुल वहीद]

एक तर्क यह भी दिया जाता है कि निजी क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों की हालत अच्छी नहीं है परन्तु मैं यह साबित कर सकता हूं कि उन बैंकों में रक्षित बैंक से भी अच्छी हालत है और रक्षित बैंक के कर्मचारी निजी क्षेत्र के बैंकों में जाना चाहते हैं। और यदि उन बैंकों में सेवा की शर्तों में किसी प्रकार की त्रुटि है तो उसे ठीक किया जा सकता है। राष्ट्रीयकरण ही इस समस्या का हल नहीं है।

मुझे ज्ञात है कि हमें समाजवादी ढांचे के समाज को चलाना है और धीरे धीरे सभी बड़ी बड़ी संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण करना है, परन्तु यह हमें धीरे धीरे करना है। यह समय राष्ट्रीयकरण के लिये उपयुक्त नहीं है। यदि अब बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय तो औद्योगिक विकास के लिये वित्त प्राप्त करने में कठिनाई होगी। भविष्य में जब हम औद्योगिक विकास कर चुकेंगे तो ऐसा कदम जरूर उठा लिया जाय परन्तु वर्तमान में ऐसा करना अनुचित और हानिकारक होगा।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : चेयरमैन महोदया, जो प्रस्ताव सुभद्रा जी ने सदन के सम्मुख रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं।

इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं कि बैंक एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान है, और आज के इस आर्थिक विकास के युग में यह बहुत ही आवश्यक है कि बैंक का राष्ट्रीयकरण किया जाए।

इस सदन के प्रायः सभी सदस्यों ने इसका समर्थन किया है और मेरा अनुमान है कि माननीय मन्त्री जी जो कि इस प्रस्ताव का जवाब देते, वे भी इसके पक्ष में होंगे। इसका कारण यह है कि इसके पक्ष में अब तक जितनी भी दलीलें दी गयी हैं वे अकाट्य हैं और उनका विरोध नहीं किया जा सकता। सदन में केवल एक ही माननीय सदस्य ने इसका विरोध किया है, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और उनके विरोध करने के कारण ऐसे नहीं हैं जिनके खिलाफ हम दलील न दे सकें। क्यों, क्या हम इसलिए चाहते हैं कि यह कुछ व्यक्तियों के हाथ से सिर्फ इसलिए ले लिया जाय कि यह उन व्यक्तियों के पास है? ऐसा हम इसलिए चाहते हैं क्योंकि हमने अपने सामने जो एक सिद्धान्त रक्खा है वह सिद्धान्त एक समाजवादी समाज की स्थापना का है और उसमें हमें अधिक से अधिक ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र का विकास करना है जिसके अन्दर आने वाला लाभ और अधिक से अधिक लाभ वितरित हो सके। लेकिन आज जो बैंक्स हैं, इन बैंकों के पास जो फाइनेंस के साधन हैं वे साधन ऐसे हैं जिनका कि वह सदुपयोग नहीं करते बल्कि वह उनका दुरुपयोग करते हैं। सदुपयोग करते हैं तो सिर्फ अपने लिये, अपने परिवार के लिए, अपने मित्रों के लिए तथा अपने बन्धु बांधवों के लिए। इस तरीके से इस देश में जो पूंजी है वह इस देश के सिर्फ एक प्रतिशतः आदमियों के पास में है। वह एक प्रतिशतः आदमी इसको अपनी भलाई के लिए करते हैं। यों कहा जाय कि इस देश में सिर्फ १४००० हाउसेज के पास ही इस देश के बैंकों की सम्पत्ति है। उसका लाभ केवल एक प्रतिशत आदमियों को मिलता है और जो इस देश के ९९ प्रतिशतः आदमियों के बल पर अपनी पूंजी लेते हैं उसके रुपये को लेकर सिर्फ मामूली तौर से उसको सूद देकर सम्पूर्ण लाभ स्वयं खा जाते हैं। इसलिये आज इस बात की आवश्यकता है कि हम अर्थ के सभी साधनों पर नियन्त्रण करें। जबकि संकटकालीन स्थिति में हमें आवश्यकता है अधिक से अधिक रुपये की, हमें आवश्यकता है अधिक से अधिक साधन की तो क्या इस समय यह उचित नहीं जंचता कि सरकार बैंकों का राष्ट्रीयकरण करे।

हम यह नहीं कहते और यहां तक कि हमारे किसी कम्युनिस्ट बंधु ने भी ऐसा नहीं कहा है और वे भी इस बात पर जिद नहीं करते कि इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण उनको बिना मुआविजा दिये करा जाय। हमारा विधान यह नहीं कहता और न हम यह चाहते हैं, हम अभी नहीं कहते, भविष्य के लिये

कहा नहीं जा सकता लेकिन अभी के लिये मैं यह नहीं कहता कि हमारे संविधान में ऐसा संशोधन किया जाय जिसके कि जरिए उनको हम बिना मुआविजे के ले लें। इस लिये हम चाहते हैं कि उनको मुआविजा दिया जाय। जिस तरीके से इस देश में जमींदारी प्रथा को ले लिया गया, जिस तरीके से मने एल० आई० सी० को लिया और उस के लिये उचित मुआविजा सरकार ने तय किया, उसी तरह हमारा यह विचार है और यह सदन का भी विचार है, सिवाय एक सदस्य महोदय के, कि हम बैंकों का राष्ट्रीयकरण करें . . .

श्री श्याम लाल सर्राफ (जम्मू तथा काश्मीर) : सिर्फ एक ही विरोध में है य आप कैसे कह सकते हैं ?

श्री भागवत झा आजाद : मैं ने अब तक के लिये कहा है कि सिर्फ एक ने विरोध किया है। मुझे मालूम नहीं और मैं यहं कैसे कह सकता हूं कि सर्राफ साहब इसका विरोध करेंगे या क्या करेंगे ? इस लिये यह बिल्कुल स्पष्ट है कि मेरा मतलब यह है कि अब तक बोलने वालों में से सिर्फ एक ने इसका विरोध किया है। यह प्रीज्यूम्ड था भाई।

मैं यह कह रहा था कि आज इसकी आवश्यकता है। क्यों? इसको दूसरे पहलू से देखा जाय। हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश है। हामारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने कल भी अपनी बहस में कहा कि इस देश को अगर विकास करना है, आगे बढ़ना है तो हमें कृषि के क्षेत्र में बचत चाहिये। आज इन बैंकों की क्या आवश्यकता है ? यह बैंक बड़े बड़े उद्योगों को ऐडवांस देते हैं। यह बुलियन और स्टौक मार्केट्स को एडवांस देते हैं। यह औरों को भी ऐडवांस देते हैं मगर यह छोटे उद्योगों को ऐडवांस नहीं देते हैं। यह बैंक होर्डिंग करने के लिये ऐडवांस देते हैं। यह बैंक जो मिडिलमैन, बीच के आदमी हैं जिनके साथ किसान अपनी सारी सम्पत्ति को अपने सारे अन्न को बेच देता है, उन मिडिल-मैनों को इन बैंकों से ऐडवांस मिलता है जमा करने के लिये लेकिन जो किसान हैं, जो मिट्टी पर मेहनत कर और खून पसीना एक करके अन्न उपजाते हैं उनको ऐडवांस नहीं मिलता है . . .

श्री पु० र० पटेल (पाटन) स्टेट बैंक हैं तो ?

श्री भागवत झा आजाद : स्टेट बैंक की शाखायें कहां कहां पर हैं ? गोड्डा ? सबडिवीजन जहां का मैं रहने वाला हूं वहां की आबादी ३ लाख ५६ हजार है। वहां गोड्डा में अभी तक स्टेट बैंक की एक भी शाखा खुली नहीं है। सरकार ने निश्चय किया है कि हर एक सब डिवीजन में स्टेट बैंक की शाखायें खोली जायें, सिद्धांत रूप में यह मान लिया गया है लेकिन दरअसल अभी तक खुली कहां कहां हैं यह माननीय सदस्य बतलायें तो सही ? जब इस सिद्धांत को कार्यरूप में परिणित करने के लिये हम इन से अनुरोध करते हैं तो इसके लिये उप वित्त मंत्री महोदय कहेंगे कि यह सम्भव नहीं है। क्यों संभव नहीं है ? हम चाहते हैं कि इन प्रश्नों के जवाब दिये जायें। जब कि उससे हमें इतनी आमदनी होने वाली है तब इसे क्यों नहीं अमल में लाया जा रहा है ? सरकार कहती है कि सिर्फ ६ करोड़ और कुछ लाख रुपये की आमदनी होगी। मैं कहता हूं कि यह गलत बात है। इन बैंकों से य जो पूंजीपति हैं इन को १५०० करोड़ रुपये की आमदनी है हालांकि मैं समझता हूं कि उससे भी अधिक आमदनी है। लेकिन चूंकि हमारे कम्युनिस्ट भाई इतनी ही बतलाते हैं तो खैर उनकी बात ही मान ली जाय और उसमें टैक्स देने के बाद उन के पास फिर भी ७ या साढ़े सात ७ करोड़ रुपया लाभांश का आता है। क्यों सरकार आज ४५ करोड़ रुपये खर्च कर रही है ? उनको मुआविजा देकर ऐसा इन्वैस्टमेंट क्यों नहीं करती जिस इन्वैस्टमट में उनको तुरन्त ७ करोड़ रुपया लाभांश में मिलें ?

श्री पु० र० पटेल : क्या प्रतिकर १०० करोड़ देना पड़ेगा ? इस पर ब्याज की दर क्या होगी ?

[मूल अंग्रेजी में]

श्री भागवत झा आजाद : श्रीमान्, यह दुर्भाग्य है हमारा और आपका कि हम इस प्रश्न पर गम्भीरता पूर्वक विचार नहीं कर सकते। मेरा कहना है कि १०० करोड़ रुपये की जरूरत नहीं है। हम कहते हैं कि अभी इसको सिर्फ ४० करोड़ रुपये की जरूरत है। आप कहेंगे कि ४० करोड़ बहुत अधिक है संकटकालीन की स्थिति में, तो मैं यह कहता हूं कि यह ४० करोड़ का इनवैस्टमेंट है जिससे आप को साल साल में कम से कम टैक्स देने के बाद ७ करोड़ रुपये का लाभांश मिलेगा। तो क्यों न हम यह इनवैस्टमेंट करें ?

यह जो हमें १०० करोड़ रुपये की बात कही जाती है कि १०० करोड़ रुपये बतौर मुआविजे के देने पड़ेंगे तो यह बात बिल्कुल निराधार है। बात तो असल यह है, सभापति महोदया, कि इस देश में जिनके पास पूंजी है या जो पूंजी रखने वाले हैं यह इतने अधिक शक्तिशाली हैं और उनके हाथ में इतनी अधिक शक्ति है कि यह हमें मजबूर कर देते हैं। पता नहीं श्री मुरार जी देसाई जैसे मजबूत मिनिस्टर को भी पूंजीपति कैसे मजबूर कर देते हैं ? उनको तो मजबूर नहीं होना चाहिये। जब सरकार की और सम्पूर्ण देश की मांग है, मारी पार्टी के हर एक सदस्य की मांग है कि इन का राष्ट्रीयकरण किया जाय, तो फिर सरकार क्यों आगे कदम नहीं बढ़ाती ? राष्ट्रीयकरण सिर्फ इस लिये नहीं कि हम इन पूंजीपतियों के खिलाफ हैं, या पूंजीपति रहें और इन्हें अभी भी बहुत से फील्ड खेलने खाने के लिये काफी है। इनके बारे में और भी बहुत से स्कैंडल्स सुने होंगे। अंडर इनवाएसिंग और ओवरइनवाएसिंग यह आज तक कर ही रहे हैं। तब ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि हम इस को करें।

श्री पटेल ने मुझे टोकते हुए कहा था कि आजाद साहब स्टेट बैंक तो है। अब मैं उनको यह बताऊं कि इन बैंकों की शाखायें सम्पूर्ण देश में ५१११ हैं और इन ५१११ शाखाओं में रूरल यानी देहाती साधनों के लिये सिर्फ ९५१ हैं। यह भारत देश एक कृषि प्रधान देश हैं। यह ७ लाख गांवों का देश है। इसके लिये प्रधान मंत्री स्वयं कहते हैं कि अगर इस देश को आगे बढ़ाना है तो इसकी कृषि को उन्नत करना है। इस देश में बैंकों की ५१११ शाखाओं में से उन देहातों में, जो कि सचमुच में भारत है क्योंकि यह गांवों का देश है, वहां सिर्फ ९५१ शाखायें हैं ....

†**श्री पु० र० पटेल** : क्या आप जानते हैं कि प्रथा के अनुसार राज्य बैंक की शाखाओं पर जो व्यय होता है उसके लिये केन्द्रीय सरकार की ओर से वित्तीय सहायता मिलती है ?

श्री भागवत झा आजाद : मुझे बड़ा अफसोस है कि आप जैसे सज्जन जो कि कृषि में इतनी अधिक रुचि रखते हैं उनको इसकी सही जानकारी नहीं है और जो कि इस तरह के सवाल उठाते हैं। मैं तो चाहता हूं कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में अगर किसी को कोई शंका हो और सवाल पूछे तो मैं उसका जवाब दे दूंगा। बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों न किया जाय इसके बारे में उनके पास वास्तव में कोई दलील नहीं है। मैं यह कह रहा था कि जो आप स्टेट बैंक की बात करते हैं तो उसका उत्तर मैंने पहले दे दिया कि यह स्टेट बैंक की शाखायें अभी तक भी सम्पूर्ण और वास्तविक रूप में जिला स्तर पर काम करती हैं, सरकारी नियम के अनुसार आज तक यह सब डिवीजनल लेविल पर नहीं पहुंची हैं। इस के लिये मैंने आप को एक उदाहरण दिया। हमारे बहुत से सबडिवीजंस हैं जहां कि इसकी शाखायें आज तक नहीं खुली पाई हैं। इस देश में आज एक प्रतिशत आदमी इसका उपयोग करते हैं। इस देश में जो ७ लाख गांव हैं और जहां के किसानों को ऐडवांस चाहिये वे नहीं हासिल कर पाते हैं। यह पूंजीपति होर्डिंग के लिये दामों को बढ़ाने के लिये अंडरइनवाएसिंग और ओवरइनवाएसिंग आदि चीजों के लिये इसका दुरुपयोग करते हैं। आज यह राष्ट्रीय सरकार जिसने कि समाजवाद का व्रत लिया है, जो चाहती है कि इस देश में हर एक आदमी का विकास हो, उस सरकार को अपने देश के आर्थिक

†मूल अंग्रेजी में

विकास के लिये, अपने सामाजिक विकास के लिये और इस देश के लाखों गरीबों को ऊपर उठाने के लिए कल से नहीं बल्कि आज से इस बात की घोषणा कर देनी चाहिये और बैंकों का राष्ट्रीयकरण करदे । वह पूंजी और वह लाभ जो आज कुछ व्यक्तियों की जेबों में जा रहा है इस आर्थिक असामानता को और भारी अन्तर को दूर करें ।

बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने से होने वाले लाभ स्पष्ट हैं । हमारे अन्य मित्रों ने इस पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला है । अब इस बात की आवश्यकता नहीं रही है कि उसके पक्ष में और दलीलें दी जायें । दलीलें बिल्कुल स्पष्ट और अकाट्य हैं । अगर कोई वास्तव में राष्ट्रीयकरण के खिलाफ दलील हो तो हम अवश्य उसे सुनना चाहेंगे लेकिन दरअसल दलील कोई उसके खिलाफ है ही नहीं जो कि पेश की जा सके । सरकार खुद नहीं कहती है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना कोई बुरी चीज़ है । सरकार उसके हक में है लेकिन उसको लागू करने के लिये तैयार नहीं जान पड़ती है । साफ साफ कुछ नहीं कहती महज़ एक गोल मटोल बात क. देती है कि यह मांग ठीक है लेकिन अभी क्या किया जाये ? इस लिये मैं माननीय श्री भगत से यह सुनना चा ता हूं कि उनके पास इन दलीलों का क्या जवाब है । अब अगर व यह कहें कि अभी के लिये तो भाई क्षमा करो, अभी नहीं कर सकते हैं, अभी नहीं आगे होगा, तो म इस पर भी मान जायेंगे और हम संतोष कर लेंगे लेकिन आप कहिये और स्पष्ट रूप में कहिये कि आप क्या करने जा रहे हैं ।

अभी फेडरेशन के एक बंधु ने ४ पेज का एक पैम्फलेट निकाला है, सारा पैम्फलेट है, मंत्री महोदय की तरह से भाषण नहीं है बल्कि उसमें फीगर्स दी हुई हैं, आंकड़े दिये हुए हैं । अब मंत्री महोदय बतलायें कि वह आंकड़े गलत हैं और अगर गलत हैं तो किस रूप में गलत हैं और कैसे गलत हैं ? इस लिये मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय इस पर पुनर्विचार करें और विचार करने के बाद इस देश के हर एक आदमी को जो आप की ओर देखता है, यह विश्वास दिलायें कि सरकार उनके हित में बैंकों का राष्ट्रीयकरण अविलम्ब करने जा रही है ।

†**सभापति महोदय** : इस संकल्प पर चर्चा के लिये ३ घंटे का समय आवंटित किया गया था । चर्चा ४.३५ सायं तक पूरी हो जानी चाहिये थी परन्तु बहुत से सदस्य अब भी वाद-विवाद में भाग लेने के इच्छुक हैं ।

†**श्रीमती सुभद्रा जोशी** : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि इस संकल्प के लिये निर्धारित समय में एक घंटे की वृद्धि कर दी जाय ।"

†**सभापति महोदय** : मेरा ख्याल है कि इस के लिये एक बार पहले भी समय बढ़ाया जा चुका है । यह समय बढ़ाये जाने का दूसरा अवसर है । मैं इस प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिये रखूंगा . . .

†**श्री अ० क० गोपालन**: (कासरगोड़) : पिछली बार जो मेरा संकल्प पेश किया गया था यदि उसे अब न लिया जाय तो मुझे आपत्ति नहीं परन्तु मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसे तीसरे अवसर पर लिया जायेगा ?

†**सभापति महोदय** : मेरा ख्याल है उसे अंशत: पिछली बार लिया गया था और अगले दिन उस पर चर्चा जारी रहेगी । अब मैं इस प्रस्ताव को मतदान के लिये रखता हूं ।

प्रश्न यह है :

"कि श्रीमती सुभद्रा जोशी द्वारा प्रस्तुत किये गये संकल्प के लिये निर्धारित समय में एक घंटे की और वृद्धि की जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सभापति महोदय** : प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है। इस लिये समय एक घंटे तक बढ़ा दिया जाता है।

†**श्री वारियर** (त्रिचूर) : मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं भारत में अधिकतर बैंक केरल में हैं और हमें अनुभव है कि बैंकिंग उद्योग में किस प्रकार काम होता है। केरल में एक अथवा दो बैंकों को छोड़ कर सभी बैंक अनुसूचित हैं। यह बैंक छोटी छोटी पान की दूकानों के समान हैं जहां बहुत सी वित्तीय अनियमितताओं को जनता से छिपाया जाता है। इन बैंकों के उन्हीं निक्षेपों का ज्ञान सरकार को हो पाता है जिन का लेखा वह देते हैं परन्तु लाखों रुपयों का हिसाब इन बैंकों द्वारा नहीं दिखाया जाता और उन का निर्धारण भी नहीं हो पाता। चोरबाजारी का सारा धन इन बैंकों में रखा जाता है। इन बैंकों के कर्मचारियों की स्थिति शोचनीय है। मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को केरल में लागू नहीं किया गया क्योंकि वह बहुत से बैंक केवल केरल में ही हैं। इन बड़े बड़े पूंजीपतियों द्वारा जो इन बैंकों को चलाते हैं छोटे छोटे व्यापारियों को समाप्त किया जा रहा है। कुछ लोग जो बिल्कुल निर्धन थे विभिन्न स्थानों पर व्यापार और उद्योग को हाथ में ले कर लाखपति बन गये हैं जिन की तुलना में छोटे व्यक्तियों की हालत खराबतर हो रही है। आप चिट फंड को लीजिये जिसे चलाने वाले लोग अधिकतर यहीं हैं। छोटे छोटे लोगों से धन ले कर यह महाजन लोग अन्य धंधों में लगाते हैं। और जब यह बैंक फेल हो जाते हैं, जैसे पलाई बैंक फेल हुआ था तो वह गरीब लोग, वह नर्सें और अन्य कर्मचारी जिन्होंने थोड़े थोड़े पैसे जमा किये होते हैं, वह खून के आंसू रोते हैं। जो प्रेक्षक रक्षित बैंक द्वारा वहां काम कर रहे हैं वह कुछ नहीं कर पाते।

यदि आप ऋण देने संबंधी स्थिति को देखें तो ज्ञात होगा कि यह बैंक किसानों को ऋण देने में असमर्थ हैं। बड़े बड़े लोग वहां सोना रख कर धन प्राप्त करते हैं और उसी धन से किसान की खेती को खरीद लेते हैं। आप मूल्यों को बढ़ने से नहीं रोक सकते क्योंकि यही धनी लोग मूल्यों को बढ़ाते हैं। इसलिए ऋण के लिये हम इन बैंकों पर निर्भर नहीं कर सकते।

इन बातों को ध्यान में रखते हुये हमें यह पहला कदम, यह सीधा सादा कदम अविलम्ब उठाना चाहिए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण अवश्य होना चाहिए।

†**सभापति महोदय** : श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा। माननीय सदस्या ६ मिनट लें।

†**श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा** (खम्मम) : मैं इस संकल्प का समर्थन करती हूं। मैं समझती हूं कि स्वयं वित्त मंत्री भी इस बात से सहमत होंगे कि राष्ट्रीयकरण हमें करना ही है। राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था के लिये बकों के महत्व को देखते हुए इन का राष्ट्रीयकरण अविलम्ब कर दिया जाना चाहिए।

देश में धन का प्रयोग योजनाओं के लिए न हो कर निजी स्वार्थों के लिये हो रहा है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

बैंक देश की वित्तीय पूंजी का नियंत्रण करते हैं। स्वयं भतपूर्व देश रक्षित बैंक के गवर्नर ने कहा था कि बकों में शक्तियां कुछ ही हाथों में केन्द्रित हैं। बड़े बड़े लोग अपने अपने उद्योगों को बढ़ाने के लिये इन बैंकों का प्रयोग करते हैं। लोगों के बचाये हुए धन का प्रयोग इन पूंजीपतियों द्वारा अपने हित के लिये किया जाता है। यदि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय तो सरकार इन से काफी लाभ उठा सकती है। इस से बैंकों की गतिविधियों में नियमितता आयेगी, मूल्यों के स्तर बनाये रखने में सहायता मिलेगी और संचय करना लोगों के लिये कठिन हो जायेगा। वस्तुओं की जो कमी

†मूल अंग्रेजी में

बनावटी तौर पर लाई गई है दूर हो जायेगी । विदेशी मुद्रा के लिये अधिक राशि के बीजक बनाना अथवा कम राशि के बीजक बनाना समाप्त हो जायेगा । हमारे आयात और निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा । चोर बाजारी का धन छिपाया नहीं जा सकेगा । धन का केन्द्रण नहीं होगा । देश के संसाधनों का प्रयोग रक्षा और विकास कार्यों के लिये किया जा सकेगा । बैंकों के राष्ट्रीयकरण से यह लाभ प्राप्त होंगे । इन शब्दों के साथ मैं संकल्प का समर्थन करती हूं ।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ** (जम्मू तथा काश्मीर) : यद्यपि इस संकल्प के उदेश्यों से मुझे पूरी सहानुभूति है फिर भी मैं समझता हूं कि ऐसा कदम उठाने से पूर्व, जिस का हमारे देश की अर्थ व्यवस्था से घनिष्ठ संबंध है, हम सावधानी पूर्वक विचार करना चाहिए ।

बैंकिंग में हमें यह नहीं देखना है कि क, ख अथवा ग वर्ग का देश में बैंकों पर और वित्त पर नियंत्रण है । वरन हमें इस बात की ओर ध्यान देना है कि हमारी ऋण योग्यता क्या है । हमें देखना है कि क्या देश के सभी प्रकार के व्यापारियों, उद्योग पतियों आदि को ऋण संबंधी सुविधायें उपलब्ध हैं । मिश्रित अर्थ व्यवस्था की नीति इस सभा द्वारा स्वीकार की गई है जिस का यह अर्थ है कि सभी भागों की अर्थ संबंधी सुविधायें प्राप्त हों ।

श्री भागवत झा आजाद ने यह तर्क दिया कि बैंकिंग में करोड़ों रुपये योंही चले जाते हैं । परन्तु वस्तु स्थिति यह नहीं है । बैंक लोगों से धन लेते हैं और अन्य लोगों को ऋण के रूप में देते हैं । इसके साथ साथ उन्हें अंशधारियों को लाभांश देना होता है और कर्मचारियों पर भी व्यय करना होता है ।

मैं एक बैंक का ८, ९ वर्ष तक सभापति रहा हूं जो बैंक की ७५ प्रतिशत राष्ट्रीयकृत है, परन्तु मेरा अनुभव यह है कि राष्ट्रीयकरण के परिणामस्वरूप धन जमा कराने वाले आगे नहीं आते । पूर्व इस के कि लोग रुपया बैंक में जमा कराये लोगों को उस बैंक में विश्वास होना चाहिए । जिस बैंक में जम्मू तथा काश्मीर सरकार के ७५ प्रतिशत अंश थे लोग उस में धन जमा कराने नहीं आये । क्योंकि भारत में लोग अनपढ़ हैं, वह राष्ट्रीयकरण का अर्थ नहीं समझते । इसलिये मैं समझता हूं कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिये यह उपयुक्त समय नहीं है ।

सरकार द्वारा बैंकों पर नियंत्रण रखने के लिये कुछ कदम उठाये गये हैं । उन के अतिरिक्त अन्य कार्यवाही भी की जा सकती है जिस से हर प्रकार की अनियमिततायें दूर हो सकती हैं ।

श्री शिव नारायण (बांसी) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो प्रस्ताव सामने है उस का समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं । मैंने बहुत से माननीय सदस्यों की बातों को इस हाउस में सुना है । मैं डिप्टी मिनिस्टर साहब से निवदन करना चाहता हूं कि इस मुल्क की आबादी ४० करोड़ के लगभग है और इसमें करीब ३५ करोड़ के डिपाजिट्स बैंकों में हैं । आज अगर पब्लिक को यह एश्योरेंस हो जाय कि उसके धन दौलत की रक्षा हो जायेगी तो ४० करोड़ रु० एक दिन में जमा हो सकते हैं । और साथ में अगर आप चालीस का सौगुना कर दीजिये तो कितना रुपया जमा हो सकता है । आज पब्लिक को इस बात का विश्वास नहीं है कि उस का धन कहां जाएगा । आज मुल्क में कहीं पंजाब बैंक है, कहीं नेशनल बैंक है, इस तरह नाना प्रकार के बैंक हैं । स्टेट बैंक तो नामिनल हैं । इन बैंकों में हम पेट काट कर पैसा जमा करते हैं और इस को पूंजीपति अपने बिजनैस में लगाते हैं । और गवर्नमेंट की जो पंचवर्षीय योजना है उस के लिए हम को रूस और अमरीका से कर्ज लेना पड़ता है और उस पर सूद देना पड़ता है । मुल्क में पैसा गढ़ा हुआ है । सोना गढ़ा हुआ है । लेकिन उस को लोग छिपा कर रख हुए हैं । इसी से प्रकट होता है कि इन लोगों का राष्ट्र प्रेम कितना है ।

---

†मूल अंग्रजी में

[श्री शिव नारायण]

सरकार ने गोल्ड कंट्रोल किया तो इस पर बड़ी आवाजें उठायी गयीं । ग्यारह ग्यारह टन सोना लोगों के घरों में है जिसे सरकार नहीं निकलवा पायी है अगर बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो जाए तो जिस प्रकार सोना अन्य बैंकों में जमा होता है और जिस का लोग सूद खाते हैं, वह रुपया गवर्नमेंट के हाथ में आ जाए । और यह जो बैंक कर्मचारियों के स्ट्राइक होते रहते हैं ये भी बन्द हो जाएं ।

हमारी मौजूदा सरकार कांग्रेस की सरकार है । हम इस देश में सोशलिस्ट पैटर्न आफ सोसाइटी लाना चाहते हैं । आज गवर्नमेंट को उस पर अमल करना चाहिए । अगर आज हमारी बैंक नेशनलाइज हो जाएं और अर्थ की गारंटी हो जाए तो जनता को हिम्मत हो जाए कि बाई एंड बाई नेशनलाइजेशन की तरफ गवर्नमेंट चल रही है और समाजवादी व्यवस्था लाना चाहती है । हम को ऐसा कदम उठाना चाहिए कि जिस से यह काम आगे बढ़े ।

अभी हाल में आपने उस हाउस में और यहां विवियन बोस कमीशन की रिपोर्ट को पेश किया । उस के डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता । उस से पता चलता है कि कुछ लोगों के हाथ में आज पैसा है । अगर इस देश का धन कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथों में रहेगा तो यहां समाजवादी व्यवस्था पनप नहीं सकती ।

हम ने इस देश में नारा लगाया था :—

गरीबों को मिले रोटी तो मेरी जान सस्ती है ।

भगत सिंह जिस ने इसी भवन में बम चलाया था, उस ने यह एलान किया था :

गरीबों को मिले रोटी तो मेरी जान सस्ती है ।

अगर बैंकों का आप राष्ट्रीयकरण कर दें तो जो पैसा जनता के पास है वह जमा कर दें और निश्चित हो जाए । आज गांवों में चोरी डकैती इसी लिए होती कि किसान जो पैसा कमाता है उस को अपने ही पास रखता है, क्योंकि वह बैंकों का हिसाब किताब नहीं समझ सकता । जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो जाए तो गांव वालों को उस में विश्वास हो जाएगा और वह अपना पैसा उन बैंकों में जमा कर देंगे ।

आज लोगों को खेती के लिये समय पर पैसा नहीं मिलता । कोआपरेटिव बैंक आपने जो खोला है वह हम से ९ परसेंट सूद लेता है और हम को दो और तीन परसेंट देता है । जब गवर्नमेंट ने कम्पलसरी सेविंग के बारे में ऐलान किया तो मैंने कहा था कि आप इस में साढ़े चार परसेंट सूद देंगे, अगर आप डाकखाने में चार परसेंट कर दें तो करोड़ों रुपया डाक्खानों में लोग जमा कर दें । अगर गवर्नमेंट जिम्मेदारी ओढ़ ले, तो मैं समझता हूं कि एगीकल्चरल डेवलेपमेंट के लिए और पंचवर्षीय योजनाओं के लिए जो रुपया विदेशों से मांगना पड़ता है वह न मांगना पड़े और जो सरकार को फारिन एक्सचेंज की कठिनाई होती है वह न हो ।

मान्यवर, मैं जानना चाहूंगा कि सरकार बैंकों को अपने हाथ में लेने में क्यों संकोच करती है । मैं इस का जबाब चाहूंगा अपने डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर साहब से । उन को क्या हिच है । हमारा नारा है कि हम देश से गरीबी को मिटाना चाहते हैं, हम इस देश के गरीबों को प्रोटेक्शन देना चाहते हैं । गवर्नमेंट जो यहां बैठी है यह गरीबों की बिठायी है । मैं आज फाइनेंस मिनिस्टर से कहना चाहता हूं कि हम को पूंजीपतियों ने और धनी लोगों ने वोट नहीं दिया है । हम को गरीबों ने वोट दिया है । और इसीलिए यह नेशनल गवर्नमेंट है । हम को चाहिए कि हम बैंकों को नेशनलाइज करें और गरीबों को फायदा पहुंचाये । ऐसा न होने से बैंक कर्मचारियों में त्राहि त्राहि मची हुई है । १३ सितम्बर

को एक स्ट्राइक होने वाला है, अप्रैल में एक स्ट्राइक हुआ था। इस का क्या मतलव है। सरकार को चाहिए कि इस की जड़ में जाए और पता लगाए कि इस प्रकार की आवाज देश में क्यों उठती है।

हमारे देश में अर्थ शास्त्र का सब से बड़ा पंडित चाणक्य पैदा हुआ। आज तक दुनिया में उस से बड़ा अर्थ शास्त्री पैदा नहीं हुआ। मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार के फाइनेन्स मिनिस्टर चाणक्य की तरह काम करें, जिस ने इस देश को महानन्द के राज्य से मुक्त कराने के बाद चन्द्र गुप्त को राजा बनाया और देश की अर्थ व्यवस्था बना दी, पर स्वयं महा मंत्री नहीं बना और राक्षस को महा मंत्री बनाया जो पुराना मंत्री था और जो हिसाब किताब को जानता था। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे भगत जी, जो कि हमारे डिप्टी फाइनेन्स मिनिस्टर हैं, और जो कि बड़े विद्वान हैं वह इस बात को ऐसे फिट करें कि हमारी मांग स्वीकार हो जाये। यह सारे हाउस की आवाज है, कांग्रेस वाले भी इसके पक्ष में हैं और अपोजीशन वालों ने भी इसका समर्थन किया है। यह बहुत गम्भीर सवाल है।

मैंने चाणक्य को इसलिए कोट किया कि हमारे मित्र लोग अंग्रेजों की और रूस वालों की इकानमिक्स की किताबें पढ़ते हैं अपने अर्थशास्त्री और पंडितों की पुस्तकें नहीं पढ़ते। मैं तो तुलसीदास को पढ़ता हूं जिन्होंने कहा है :

जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी सो नृप अवशि नरक अधिकारी

यह तुलसीदास जी ने लिखा है। इस को पढ़िये और इस पर अमल कीजिये। रामराज्य में ही गांधी जी की कल्पना पूरी हो सकती है। इसलिए प्रार्थना यही है . . .

श्रीमती सुभद्रा जोशी : आजकल तो काम राज है, राम राज नहीं है।

श्री शिव नारायण : राम और काम में केवल एक अक्षर का ही तो अन्तर है। हम राम राज के नजदीक आ रहे हैं। आजकल जो काम राज प्लान चल रही है उसके बारे में मुझे एक साहब ने कहा कि कांग्रेस वाले बड़े चालाक हैं कि अपनी त्रुटियों को देखते हैं। हमारे नेता श्री कामराज और पंडित जी आदि देखते हैं कि हमारी कमजोरियां क्या हैं और उन को दूर करना चाहते हैं। ऐसा होगा तभी करप्शन दूर होगा। और जो पूंजी पति बड़ी बड़ी तोदें लिए फिरते हैं, जिन से उनके कारण चला फिरा भी नहीं जाता और उठने बैठने में मुश्किल होती है, उन का करप्शन खत्म हो जायेगा।

हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने बसों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। उसका परिणाम यह है कि वक्त पर गाड़ियां चलती हैं। लोगों को सब सुविधाएं मिलती हैं, ओवर लोडिंग नहीं होता और कोई गड़बड़ी नहीं होती। थानेदार बस को नहीं रुकवा सकते। रधौंली का थानेदार पहले बसों को घंटों खड़ा रखता था, चाहे उस में कोई रईस बैठा हो, या कोई कांग्रेसी बैठा हो या कम्युनिस्ट बैठा हो। यात्री ताकते रहते थे और घंटों इन्तजार में बैठे रहते थे, एक घंटे बाद थानेदार साहब खरामा खरामा आते थे और बस में बैठते थे तब बस चलती थी। अब हमारी गवर्नमेंट ने बसों का नेशनलाइजेशन कर दिया है जिस से उस को भी मुनाफा होता है और पबलिक को भी सुविधा है, सैकड़ों हमारे नौजवानों को इस में काम मिल गया और वे सरविस कर रहे हैं।

मैंने सुभद्रा जी की स्पीच को सुना। उन्होंने कहा कि सरकार अपने सब से बड़े अफसर को चार हजार तनख्वाह देती है और प्राइवेट लोग दस दस हजार तनख्वाह देते हैं। क्या बात है ? प्राइवेट संस्थानों में बेईमानी की जाती है, पैसे का गलत इस्तेमाल किया जाता है। आमदनी सौ है तो इनकम टैक्स के लिए पचास लिखाते हैं। इस तरह इनकम टैक्स में बेईमानी होती है और हर चीज में बेईमानी होती है।

आज सुबह मैं ऊपर सेक्रेटरी साहब के पास गया था, उन्होंने मुझ को कम्पलसरी सेविंग के बारे में सब अच्छी तरह बता दिया । अगर आज बैंकों का काम गवर्नमेंट के हाथ में रहे तो दिल्ली से बटन दबते ही सारे हिन्दुस्तान में आवाज उठेगी, और काम में एकसूत्रता आयेगी । कल जो अविश्वास प्रस्ताव आया वह तो एक मखौल था । किसी ने एक भी कन्क्रीट बात नहीं कहीं उधर से । मखौल किया । कन्क्रीट बात वह है, जो कि आज कांग्रेस वाले गवर्नमेंट के सामने रख रहे हैं । वे बता रहे हैं कि यह कमी है, इस को ठीक करना है । यह कांग्रेस वालों का दम है ।

मैं डिपुटी फ़िनांस मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं कि श्री टी० टी० कृष्णमाचारी जैसे फ़िनांस के विद्वान उन के साथ बैठे हुए हैं । मुल्क में और भी बड़े बड़े पंडित और विद्वान हैं । वह उन से बात करें और किसी उचित निर्णय पर पहुंचें । डिपुटी फ़िनांस मिनिस्टर साहब ने मुझ से कहा कि तुम किसान हो, तुम कोई रीयल बात बताओगे । मैं उन को यह रीयल बात बता रहा हूं । इस में कोई बनावट नहीं है । मैं फ़ारेन कंट्री से आया हूं, जहां पैनी सेविंग स्कीम चलाई गई थी, जहां मेरे बाप-दादा प्राइवेट बैंक चलाते थे और पैसा बचाते थे ।

हमारा देश दो एस्पेक्ट्स को मानता है । वह मैटीरियलिज्म में भी विश्वास करता है और स्पिर्टुअलिज्म में भी विश्वास करता है । फ़ारेन कंट्रीज़ में मैटीरियलिज्म पर ज़ोर दिया जाता है, लेकिन हमारे मुल्क में मैटीरियलिज्म और स्पिर्टुअलिज्म दोनों पर विश्वास किया जाता है । हम ७५ बरस की उम्र तक अर्थ और धन-दौलत कमाते हैं और ७५ बरस के बाद हम रिटायर हो जाते हैं और स्पिर्टुअलिज्म की तरफ़ अपने आप को लगाते हैं । यह हमारे देश की परम्परा और संस्कृति रही है । यह बात चाणक्य को पढ़ने से मालूम पड़ती है ।

एक माननीय सदस्य : धर्म ?

श्री शिव नारायण : धर्म और अर्थ दोनों को हम मानते हैं ।

एक माननीय सदस्य : काम और मोक्ष ?

श्री शिव नारायण : उस की तैयारी ७५ बरस के बाद होती है ।

डिपुटी फ़िनास मिनिस्टर साहब को मैं कहना चाहता हूं कि इस देश का कल्याण, पंच-वर्षीय योजना की सफलता और चीन को हटाने का सब से प्रमुख उपाय यह है कि बैंकों को नैशनलाइज़ कर दिया जाये । जब धन सरकार के पास होता, होगा, तो न हमें अमरीका के पास जाना पड़ेगा और न दुनिया के किसी और देश के पास ।

इस देश में हम ने व्रत रखना सीखा है । अगर महीने में एक दिन का व्रत रख लिया जाये, तो चालीस करोड़ पाव अनाज बच सकता है एक वक्त का ।

श्री ब० रा० भगत : उस से पेट भी नहीं निकलेगा ।

श्री शिव नारायण : पेट भी नहीं निकलेगा और बदन भी आउट आफ़ कंट्रोल नहीं होगा । आज मेरी ५२ बरस की उम्र है, लेकिन आज भी मैं हाकी खेल सकता हूं, एक मील दौड़ सकता हूं, क्योंकि मैं कंट्रोल रखता हूं, रेगुलेट करता हूं, ज्यादा धन नहीं है कि ज्यादा ख़र्च करूं, पच्चीस मोटरों पर चलूं और रोज़ नई मोटरें बदलूं ।

भारतीय संस्कृति ने सारी दुनिया को चिराग़ दिखाया है । मैं आशा करता हूं कि सरकार बैंकों को नैशनलाइज़ कर के दुनिया को मुंहतोड़ जवाब देगी । दुनिया के डेमोक्रेसी में विश्वास

करने वाले देशों में भारत अग्रदूत है। सरकार को ऐसा काम करना चाहिए कि हमारा और हमारे देश का नेतृत्व चलता रहे।

धन की कोई कमी नहीं है। आज भी घरों में सोना गड़ा हुआ है। लोगों के पास कमी नहीं है। लेकिन कोई गारण्टी नहीं है।

श्री भागवत झा आज़ाद : पूंजीपतियों के घरों में।

श्री शिव नारायण : पूंजीपतियों के घरों में ही है। तो क्या आज़ाद के पास सोना है या शिव नारायण के पास सोना है? अगर मेरे पास होता, तो मैं कहता कि ले लो। इस देश में भामाशाह ने महाराणा प्रताप के लिए अपने ख़ज़ाने खोल दिये थे, लेकिन आज बिड़ला और टाटा खोलने के लिए तैयार नहीं हैं। डिफेंस फंड में ग़रीबों ने पैसा दिया है, पूंजीपतियों ने नहीं दिया है। मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूं कि वह इस बारे में क्या कर रही है? उस की ढिलाई से ही यह स्थिति पैदा हुई है, वर्ना डी० आई० आर० के अन्तर्गत उन का सारा धन ले कर चीन के आक्रमण के विरुद्ध प्रयोग में लाया जाता। तब यह अविश्वास-प्रस्ताव हमारे ख़िलाफ़ न आ पाता। यह हमारी गवर्नमेंट की लीनिएन्सी, शराफ़त और भलमनसत का ही परिणाम है। हम जितनी भल-मनसत से पेश आते हैं, उतना ही हम को चिढ़ाया जाता है और उल्टी-सीधी बातें कही जाती हैं।

डिपुटी फ़िनांस मिनिस्टर साहब को मैं कहना चाहता हूं कि हमारे शब्द रायगां नहीं जाने वाले हैं। हम लोगों ने अपना खून-पसीना बहा कर इस देश की आज़ादी को हासिल किया है। 'यह देश ज़िन्दाबाद रहेगा। इस देश की आज़ादी मुफ्त में नहीं मिली है। गांधी जी' ने दुनिया के सामने एक नया एक्सपेरिमेंट रखा और हम ने बिना खून बहाये स्वराज्य लिया। यह स्वराज्य बड़ा कीमती है। इस को कायम रखने के लिए यह आवश्यक है कि बैंकों को नैशनलाइज़ किया जाये। मैं उन को बताना चाहता हूं कि एक एक ग़रीब हमारे पीछे खड़ा है। संयोग से हमारा लीडर ऐसा है, जिस की सारे देश में पूजा होती है, लेकिन केवल प्राइम मिनिस्टर होने के नाते ही उन की पूजा नहीं होती है। वह प्राइम मिनिस्टर रहें, तब भी उन की देश में पूजा होगी और अगर न रहें, तब भी होगी। इस देश में कोई दूसरा आदमी पैदा नहीं हुआ है, जो कि जवाहरलाल नेहरू का मुकाबला कर सके। अगर उस के नेतृत्व में, उस के शासन-काल में ही, हम यह नमूने का काम कर दें, तो मैं विश्वास दिलाता हूं, मैं ज़िम्मा लेता हूं कि पैंतीस करोड़, चालीस करोड़ रुपया दूसरे ही दिन बैंक में जमा हो जायेगा, पब्लिक देगी।

इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट इस रेज़ोल्यूशन को निहायत खुशी के साथ मंजूर करे। मैं इस रेज़ोल्यूशन का समर्थन करता हूं।

†**श्री भागवत झा आज़ाद :** समय बढ़ा दिया गया है इसलिये कुछ और सदस्यों को बोलने का अवसर दिया जाये।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** मुझे मालूम है कि समय बढ़ा दिया गया है। परन्तु मंत्री महोदय को पर्याप्त समय उत्तर देने के लिए मिलना चाहिये, और फिर प्रस्तावक भी बोलेंगे।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** (जोधपुर) : मैं कुछ समय के लिये बोलना चाहता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** यदि आप दो, तीन मिनट में समाप्त कर सकें तो आप बोल सकते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री म० ला० द्विवेदी : (हमीरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव इस सदन के सामने प्रस्तुत हुआ है, मैं उस के समर्थन में बोलना चाहता हूं ।

मुझे मालूम है कि हमारे देश में देहातों में लोगों से २४ रुपये सैंकड़ा, २९ रुपये सैंकड़ा तक ब्याज की दर ली जाती है और इस से देश के कृषिकारों, मज़दूरों और ग़रीबों को जो प्रताड़ना मिले रही है, उस का अनुमान आप नहीं लगा सकते । मेरे इलाके में एक सेठ जाते हैं । वह पौने आठ रुपये किसान को देते हैं और दस महीने में दस रुपये वसूल कर लेते हैं, जोकि तीस रुपये सैंकड़ा ब्याज पड़ता है । आप देख सकते हैं कि जब देश में ब्याज की इतनी ऊंची दरें चलती हैं, तो ग़रीबों का कितना नुकसान होता होगा ।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में वित्त मंत्री ने तर्क दिया कि उस से हम को केवल ६ करोड़ रुपये का फ़ायदा होगा और १०० करोड़ रुपये हम को प्रतिकर, कम्पेन्सेशन, के रूप में देने पड़ेंगे । मैं वित्त मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि ६ करोड़ रुपये के लाभ का हिसाब उन्हों ने किस तरह लगाया है । उन का यह हिसाब ग़लत है । यदि १०० करोड़ रुपया कम्पेन्सेशन देना है, तो उस को एक ही दिन में देने की कोई ज़रूरत नहीं है । हम ने ज़मींदारियां ज़ब्त कीं और ज़मींदारों को उस के बदले चालीस वर्ष के बांड दिये । इसी तरह हम निजी बैंकों के पूंजीपतियों को दस, बीस वर्षीय बांड दे सकते हैं और धीरे धीरे वह रकम चुकाई जा सकती है और उस पर उन को थोड़ा सा ब्याज दिया जा सकता है ।

मान लीजिये कि ६ करोड़ के लाभ का हिसाब सही है, तो सब खर्च को जोड़ कर, ५०० करोड़ रुपये की पूंजी हमारे पास एक दिन में आ जायगी, जिस को हम देश भर में अच्छे अच्छे कामों में लगा सकते हैं ; हम को कोई भी कम्पेन्सेशन तुरन्त देने की आवश्यकता इस लिए नहीं कि हम बांड दे कर यह काम चला सकते हैं ।

मैं आप से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय बैंक हम से ७ प्रतिशत ब्याज लेते हैं और कहीं कहीं ९ प्रतिशत लेते हैं, अगर वे किसी इंडस्ट्री को कोई क्रेडिट देते हैं, लेकिन उन को रिज़र्व बैंक से रुपया ४ प्रतिशत ब्याज पर मिल जाता है । इस का मतलब यह है कि कम से कम ३ प्रतिशत का लाभ वे बिल्कुल मुफ्त में ले लेते हैं । अगर सरकार बैंकिंग को नशनलाइज़ कर देगी, तो यह ३ प्रतिशत सरकार के हाथ में आ जायगा । अगर ३ प्रतिशत का हिसाब लगाया जाये, तो ६ करोड़ से ज्यादा की रकम होती है ।

दिल्ली में कुछ क्रेडिट कम्पनियां, फ़िनांसिंग कम्पनियां, खुली हुई हैं । अगर वे दस हजार रुपये उधार देती हैं, तो वे प्रति मास १२०० रुपये लेती हैं, जिस में अगर एक रुपया भी चुकाना होता है, तब भी वे १२०० रुपये का ब्याज लेती हैं । इस प्रकार से वह ब्याज पचास रुपये सैंकड़ा से भी अधिक पड़ता है । ये फ़िनांसिं कम्पनियां हमारे देश की घातक हैं, जो ग़रीब लोग रोज़गार या इंडस्ट्री चलाना चाहते हैं उन के लिए हानिकारक हैं और देश की उन्नति में बाधक हैं । अगर सरकार के पास बैंक होगा, तो उन लोगों से सही और मुनासिब ब्याज लिया जायगा, रिज़र्व बैंक की तरह ७ प्रतिशत से अधिक नहीं लिया जायगा और इस से देश में समाजवादी समाज की स्थापना होगी । यह राष्ट्र के हित में है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाये और अगर आज नहीं किया जाये, तो मंत्रालय यह आश्वासन दे कि हम इस बात पर विचार करेंगे, आंकड़े एकत्र करेंगे कि इस के पक्ष और विपक्ष में क्या क्या बातें हैं, जिन को संसद् के बजट अधिवेशन में रखा जाये

और उस समय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाये । लाइफ इंश्योरेंस के राष्ट्रीयकरण से हमें लाभ हुआ है । आप ने खुद प्रमाणित कर के बताया है कि हमें लाभ हुआ है । जब कोई वजह नहीं है कि जनरल इनश्योरेंस और बैंकिंग का अगर राष्ट्रीयकरण हो जायगा तो देश को लाभ नहीं होगा ।

इन शब्दों के साथ मैं आप को धन्यवाद देता हूं, वह समय जो आप ने मुझे दिया है और मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वह इस मामले पर ठंडे दिल से विचार करें और मैं इस प्रस्ताव का हृदय से समर्थन करता हूं ।

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : उपाध्यक्ष महोदय, अब चूंकि आज की बैठक का समय समाप्त होने को है यदि आप अनुमति दे तो मैं अगले दिन उत्तर दे दूं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : आप उत्तर देना आरम्भ कर दें और फिर अगले दिन जारी रखें ।

†**श्री ब० रा० भगत** : आरम्भ तो मैं ने कर दिया है :

†**उपाध्यक्ष महोदय** : तो फिर सभा सोमवार, सुबह ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है ।

इसके पश्चात् लोक-सभा सोमवार, २६ अगस्त, १९६३/भाद्र ४, १८८५ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

शुक्रवार, २३ अगस्त, १९६३
—
१ भाद्र, १८८५ (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		११११—३७
तारांकित प्रश्न संख्या		
२४०	केले	११११—१४
२४१	भारत-फ्रांस व्यापार	१११४—१५
२४२	प्रोत्साहन बोनस योजना	१११५—१६
२४३	नरम लकड़ी	१११७—२०
२४५	विद्युत् उपकरण संयंत्र	११२०—२३
२४६	अखबारी कागज का कारखाना	११२३—२६
२४७	भारतीय विदेश व्यापार संस्था	११२६—२८
२४८	दूसरा राज्य व्यापार निगम	११२९—३१
२४९	मोटर साइकिलों का निर्माण	११३१—३४
२५०	लन्दन में व्यापार मंत्रियों का सम्मेलन	११३४—३५
२५१	"इलक्ट्रोड्स" का अभाव	११३५—३७
२५२	गैर-सरकारी क्षेत्र के इस्पात के कारखाने	११३७
प्रश्नों के लिकित उत्तर		११३८—८३
तारांकित प्रश्न संख्या		
२४४	लोहा	११३८
२५३	मोटरों के पुर्जे	११३८
२५४	चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से स्थापित परियोजनायें	११३९
२५५	रबड़ का कारखाना	११३९—४०
२५६	संयुक्त राष्ट्र संघ सहायता "क्लब"	११४०
२५७	कच्चा पटसन	११४०—४१
२५८	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	११४१

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

तारांकित
प्रश्न संख्या

२५९ निर्यात . . . ११४१
२६० मथीलेटेड स्प्रिट . . ११४२
२६१ पादप-रासायनिक परियोजना . . . ११४२–४३
२६२ नेपाल को परिवहन सुविधायें ११४३
२६३ रासायनिक मध्यवर्ती पदार्थ निर्माण परियोजना ११४४
२६४ आर्थिक सहयोग . . . ११४४
२६५ हिन्दु धार्मिक धर्मस्व आयोग ११४४–४५
२६६ मशीन निर्माण का उद्योग . . ११४५
२६७ विदेशों में सप्लाई मिशन . . . ११४५–४६
२६८ केरल में शुद्ध मापक यंत्र बनाने का कारखाना . . ११४६
२६९ पाकिस्तानी कपास . . ११४६–४७

अतारांकित
प्रश्न संख्या

७४३ नवीन औद्योगिक एकक . . . ११४७
७४४ योजना कर्मचारियों का प्रशिक्षण . . . ११४७–४८
७४५ औद्योगिक सहकारी संस्थायें . . . ११४८
७४६ छोट पैमाने के उद्योग . . ११४८–४९
७४७ लघु औद्योगिक एकक . . ११४९
७४८ उद्योगों का विकास . . . ११४९–५०
७४९ औद्योगिक सहकारी संस्थायें . . . ११५०
७५० राजस्थान में छोटे पैमाने के उद्योग . ११५०
७५१ इस्पात का आयात . . ११५१
७५२ मैसूर का रेशम उद्योग ११५१
७५३ नमक ११५१
७५४ विदेशों में कुटीर और लघु उद्योगों के लिये प्रशिक्षण . ११५१–५२
७५५ भारत का निर्यात व्यापार . . ११५२
७५६ फैरो धातुओं का निर्यात . . . ११५२–५३
७५७ फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड का विस्तार . ११५३

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
७५८	लोहे की ढली हुई वस्तुओं का निर्यात	११५३
७५९	नीरा	११५४–५५
७६०	भारतीय दस्तकारी की वस्तुयें	११५५
७६१	रेफ्रीजरेटर	११५५–५६
७६२	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	११५६
७६३	पश्चिमी बंगाल के लिये सीमेन्ट	११५६–५७
७६४	रेल की पटरियों का निर्यात	११५७
७६५	कुटीर उद्योग	११५७
७६६	बोनाकालू, आन्ध्र प्रदेश में सीमेंट का कारखाना	११५७–५८
७६७	प्राग टूल्स कारपोरेशन	११५८
७६८	औषधि-निर्माण संयंत्र	११५८–५९
७६९	नमक विशेषज्ञों का फ्रांस को दौरा	११५९–६०
७७०	केरल के हथकरघा बुनकर	११६०
७७१	हथकरघा कारखानों के सूत के क्रय के लिये अर्थसहायता देना	११६०
७७२	खरादों का निर्यात	११६१
७७३	विदेशों में मरम्मत केन्द्र	११६१
७७४	सीमेंट	११६१–६२
७७५	संविधान सभा के प्रलेख	११६२
७७६	कम्पनियां	११६२
७७७	वकीलों की फीस	११६२–६३
७७८	चाय निर्माण विधि	११६३
७७९	निर्वाचन याचिकायें	११६३–६४
७८०	वनस्पति घी	११६४
७८१	कपड़े की मशीन का कारखाना	११६४–६५
७८२	सीमेंट का उत्पादन	११६५
७८३	आपात कालीन उत्पादन समिति	११६५–६६
७८४	केरल में छोटे पैमाने के उद्योग	११६६
७८५	रबड़ बागान	११६६–६७

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

७८६ दस्तकारी की वस्तुयें . ११६७
७८७ मेवा . ११६७
७८८ फूलों का निर्यात ११६८
७८९ भेषजों के पेटेन्ट .. . ११६८
७९० जापान को लौह अयस्क का निर्यात . . ११६८
७९१ वस्त्र लाइसेन्स आदेश ११६९
७९२ भोपाल टेक्स्टाइल मिल्स ११६९
७९३ ढलवां लोहा ११६९–७०
७९४ विदेशी शराब . . . ११७०
७९५ चावल की भूसी का निर्यात . ११७०–७१
७९६ ढलाई व गढ़ाई का दूसरा कारखाना ११७१
७९७ तम्बाकू . . ११७१
७९८ खादी एवं ग्रामोद्योग ११७२
७९९ खादी . . . ११७२
८०० मद्रास में सीमेंट का कारखाना . . ११७३
८०२ हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० . ११७३
८०३ ब्रिटिश कपड़ा उद्योग ११७३–७४
८०४ इस्पात तथा लोहा कारखाने . . ११७४
८०५ इस्पात प्रौद्योगिकी संस्था . ११७४–७५
८०६ पंजाब में इंजीनियरिंग एकक . . . ११७५
८०७ कांगड़ा में सीमेंट का कारखाना . ११७५–७६
८०८ पुस्तकों का निर्यात . ११७६
८०९ औद्योगिक विस्तार केन्द्र . . ११७६–७७
८१० नया नंगल में उर्वरक कारखाना ११७७
८११ हिमाचल प्रदेश में कपास कताई मिल . ११७७–७८
८१२ हिन्दुस्तान केबल फैक्टरी ११७८–७९
८१३ एडिन्बरा में चाय केन्द्र ११७९
८१४ औद्योगिक उत्पादन . ११८०
८१५ मद्रास यंत्र उद्योग ११८०

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
८१६	अभ्रक का निर्यात .	११८१
८१७	कागज़ का उत्पादन तथा विकास	११८१
८१८	साबुन उद्योग	११८१–८२
८१९	चप्पलें .	११८२
८२०	एकस्व विधि	११८२
८२१	लोहा और इस्पात का वितरण	११८२–८३
८२२	रूरकेला और दुर्गापुर इस्पात कारखाने .	११८३
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना .		११८३–८५
श्री स० मो० बनर्जी ने उत्तर प्रदेश, गुजर और अन्य राज्यों को ढलवें लोहे के अपर्याप्त संभरण की ओर इस्पात और भारी उद्योग मंत्री का ध्यान दिलाया		
इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया और ढलाई के लोहे का सेक्टर-वार और राज्य-सूची के ढलाई कारखानों के लिये राज्य-वार भी वितरण बताने वाला एक विवरण टेबल पर भी रखा ।		
सभा पटल पर रखे गये पत्र		११८५–८६
(१) रबड़ अधिनियम, १९४७ की धारा २५ की उपधारा (३) के अन्तर्गत, दिनांक २७ जुलाई, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२४२ में प्रकाशित रबड़ (दूसरा संशोधन) नियम, १९६३ की एक प्रति ।		
(२) प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—		
(क) ऊनी धागे, वस्त्रों और हौज़री के सामान के उचित मूल्यों के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९६२) ।		
(ख) दिनांक २८ जून, १९६३ का सरकारी संकल्प संख्या १७ (२६)—टेक्स (डी)/६२ ।		
(ग) उपरोक्त (क) और (ख) में उल्लिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति उक्त उप-धारा में निर्धारित अवधि के भीतर न रखे जाने के कारण बताने वाला विवरण ।		
(३) हिन्दुस्तान नमक लिमिटेड, जयपुर के ज्ञापन और अन्तर्नियमों की एक प्रति ।		

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र—(क्रमशः)

(४) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत, दिनांक १५ जुलाई, १९६३ के पांडिचेरी गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या २३२२–६३ कॉन की एक प्रति, जिसमें पांडिचेरी सीमेन्ट नियंत्रण आदेश, १९६३ दिया हुआ है ।

विधेयक पर राय ११८६

श्री जं० ब० सिं० बिष्ट ने हिन्दू उत्तराधिकार संशोधन विधेयक, १९६२ के बारे में राय के पत्र संख्या ३ को सभा पटल पर रखा ।

विधेयक पुरःस्थापित ११८७–८८

व्यक्तिगत चोट (प्रतिकर बीमा) विधेयक, १९६३

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), १९६३–६४ . . . ११८८—९८

वर्ष १९६३–६४ के आयव्ययक (रेलवे) से सम्बन्धित अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा आरम्भ हुई । चर्चा समाप्त हुई और मांगें पूरी पूरी स्वीकृत हुईं ।

विधेयक पारित . . . . . ११९८—१२०३

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) ने प्रस्ताव किया कि भाण्डागार निगम (संशोधन) विधेयक पर विचार किया जाये । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और खंडवार चर्चा के बाद विधेयक पारित किया गया ।

विधेयक विचाराधीन १२०४–०५

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) ने प्रस्ताव किया कि सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (संशोधन) विधेयक पर विचार किया जाये । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन—स्वीकृत १२०५–०६

तेइसवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ ।

गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प—विचाराधीन . . . १२०६—२९

श्रीमती सुभद्रा जोशी द्वारा २९ मार्च, १९६३ को प्रस्तुत बैंकों के राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी संकल्प पर अग्रेतर चर्चा जारी रही । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

सोमवार, २६ अगस्त, १९६३/४ भाद्र, १८८५ (शक) के लिये कार्यावलि—

सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (संशोधन) विधेयक, बड़े पत्तन न्यास विधेयक और व्यक्तिगत चोट (प्रतिकर बीमा) विधेयक पर अग्रेतर चर्चा और इसका पारित किया जाना ।

———

GMGIPND—LS III –1005 (Ai) LSD—24-9-63—160.

	पृष्ठ
भाण्डागार निगम (संशोधन), विधेयक	११९८–१२०३
विचार करने का प्रस्ताव	११९८
श्री अ० म० थामस	११९८–९९
श्री प्रभात कार	११९९
श्री यशपाल सिंह	११९९
श्री स० मो० बनर्जी	११९९
श्री सोनावने	११९९–१२००
श्री क० ना० तिवारी	१२००–०१
श्री प्रिय गुप्त	१२०१
श्री कृ० ल० मोरे	१२०१–०६
खंड २ और १	१२०३
पारित करने का प्रस्ताव	
श्री अ० म० थामस	१२०३
सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (संशोधन) विधेयक ..	१२०४–०५
बिचार करने का प्रस्ताव	१२०४
श्री ब० रा० भगत	१२०४–०५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति .	१२०५–०६
तेईसवां प्रतिवेदन	
बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प	१२०६
श्री स० मो० बनर्जी	१२०६–०८
श्री महेश दत्त मिश्र	१२०८–०९
श्री काशीराम गुप्त	१२०९–११
डा० राम मनोहर लोहिया	१२११–१३
श्री मा० ल० जाधव	१२१३–१४
श्री मोहन स्वरूप	१२१४–१५
श्री इन्द्रजीत गुप्त	१२१५–१७
श्री मुत्तु गौडर	१२१७
श्री अब्दुल बहीद	१२१७–१८
श्री भागवत झा आजाद	१२१८–२२
श्री बारियर	१२२२
श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा	१२२२–२३
श्री श्याम लाल सर्राफ	१२२३
श्री शिव नारायण	१२२३–२७
श्री म० ला० द्विवेदी	१२२८–२९
श्री ब० रा० भगत	१२२९
दैनिक संक्षेपिका	१२३०–३५

PLS. 41. XIX. 9. 63.
160

© १९६३ प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण) के नियम ३७६ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित और भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित ।